रजिस्ट्री संख्या डी. एल.-33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 1992/आश्विन 11, 1914
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1992/ASVINA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1992

का.आ. 2472.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एस. पी. सहगल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(193)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICE

New Delhi, the 17th August, 1992

S.O. 2472.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri S. P. Sehgal, Advocate for appointment as a Notary to practise in C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. (193)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1992

का.आ. 2473.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हनामन्त गुरुराव हनामदार, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे हुबली सिटी (कर्नाटक) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(195)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 18th August, 1992

S.O. 2473.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Hanamant Gururao Inamdar Advocate for appointment as a Notary to practise in Hubli City (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 2(195)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1992

का.आ. 2474.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इकबाल सिंह गिल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नवां शहर, जिला जालंधर (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(194)/92-न्यायिक]

NOTICE

New Delhi, the 18th August, 1992

S.O. 2474.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rults, by Shri Iqbal Singh Gill, Advocate for appointment as a Notary to practise in Nawashahar Distt., Jalandhar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(194)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1992

का.आ. 2475.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती सरनजीत कौर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 अधीन एक आवेदन इस बात लिए दिया है कि उसे दिल्ली (तीस हजारी कोर्ट) में व्यवसाय करने के लिए नौकरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(17)/91-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 25th August, 1992

S.O. 2475 .—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Srimati Sarabjit Kaur, Advocate for appointment as a Notary to practise in Tis Hazari Courts, (U.T. of Delhi).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(17)/91-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1992

का. आ. 2476.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सईद सादिक हुसैनी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सिरसिनूर ताल्लुक (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(200)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 27th August, 1992

S.O 2476.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, Sh. Syed Sadif Hussaini Advocate for appointment as a Notary to practice in Sirdhanoor Taluka (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the understand within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(200)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 1992

का.आ. 2477.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री गुरुसिद्धया एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कुबेरप्पू नगर (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(186)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 2nd September, 1992

S.O. 2477.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Gurusididiah Advocate for appointment as a Notary to practice in Kurerpuaagar (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(186)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992

का.आ. 2478.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री योगेश कुमार गौतम एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सिविल कोर्ट आगरा (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(201)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd September, 1992

S.O. 2478.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rult 4 of the said Rules, by Shri Yogesh Kumar Gautam Advocate for appointment as a Notary to practise in Civil Courts Agra (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[F. No. 5(201)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर 1992

का.आ.2479.—नोटरीज नियम, 1956, के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री आर. दशरथ प्रसाद, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मैसूर सिटी (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(203)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 1992

NOTICE

S.O 2479.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri R. Dasarath Prasad Advocate, for appointment as a Notary to practice in Mysore City (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[F. No. (203)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3सितम्बर, 1992

का.आ. 2480 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हाजी सईद असादुल्लाह अब्दुल्ला, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बम्बई (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप, इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (202)/92-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 1992

NOTICE

S.O. 2480.—Notict is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Haji Savyid Abdullaha Advocate for appointment as a Notary to practise in Bombay (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(202)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992

का.आ 2481 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री श्रीकान्त मारुतराव काले, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बारामती एवं पुणे (जिला) महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (204)/92-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd September, 1992

S.O. 2481.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Shrikant Marutrao Kale Advocate for appointment as a Notary to practise in Baramati & Pune Distt. (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(204)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

का.आ. 2482 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (205)/92—न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd September, 1992

S.O 2482.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Suresh Chandra Sharma Advocate for appointment as a Notary to practise in Neem Ka Thana Distt. Sikar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(205)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

का.आ. 2483 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बृजेन्द्र कुमार अवस्थी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सीतापुर जिला कचहरी (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (206)/92—न्यायिक]

पी सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 4th Septembr, 1992

S.O. 2483.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Brijendra Kumar Awasthi Advocate for appointmtnt as a Notary to practise in Sitapur Distt.Courts (U.P.)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No F. 5(206)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1992

का.आ. 2484 :—गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 60, 62 की उपधारा (2) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गोवा राज्य में सेवा के आबंटन संबंधी आदेश, 1990 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (i) यह आदेश गोवा राज्य सेवा के आबंटन (संशोधन) आदेश, 1992 कहलाएगा।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. गोवा राज्य सेवा आबंटन आदेश, 1990 की अनुसूची 1 में (इसके आगे इसे यथित आदेश कहा जाएगा);

(क) "स्वास्थ्य सेवायें" शीर्ष के अंतर्गत :—

(1) क्रम सं. 91 कालम (3) के आगे वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कनिष्ठ निश्चेतक"

(2) क्रम संख्या 92 के पश्चात् और तत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"92-क श्रीमती रोस्वा फर्नांडीज स्टाफ नर्स 9-2-1958

(ख) "पुलिस" शीर्ष के अंतर्गत :—

(1) क्रम सं. 134 और उससे उल्लिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 175 के पश्चात् और तत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा;

"175-क	श्री नानू एस. शिरोडकर	पुलिस कांस्टेबल	12-9-1954
175-ख	श्री वी.एस. गांवकर	पुलिस कांस्टेबल	14-11-1956
175-ग	श्री आटचट एम सेल	हैड कांस्टेबल	30-13-1948
175-घ	श्री उदय कुमार आर काले	पुलिस कांस्टेबल	1-06-1965

2. उक्त आदेश की अनुसूची II में :—

(क) "स्वास्थ्य सेवायें" शीर्ष के अंतर्गत और क्रम सं 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(ख) "पुलिस" शीर्ष के अन्तर्गत :—

(1) क्रम सं 104 और 105 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(2) क्रम सं. 107 और 108 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(3) क्रम सं. 108 के पश्चात् और तत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्

1	2	3	4
"108-ए.	श्री एस.पी. धुरे	पुलिस कांस्टेबल	17-2-1960

पाद टिप्पणी : मुख्य आदेश का.आ. 1295 दिनांक 31-5-1990 के अनुसार भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उपखंड (ii), दिनांक 23.5.1992 को प्रकाशित किया गया।

[फाइल सं.-14012/2/87-जीपी]

अरुण माथुर, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1992

S.O. 2484.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (5) of sections 60, 62 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), the Central Government hereby makes the following order to amend the Allotment for Service in the State of Goa Order, 1990, namely :—

1. (1) This Order may be called the Allotment for Service in the State of Goa (Amendment) Order, 1992.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule I to the Allotment for Service in the State of Goa Order, 1990 (hereinafter referred to as the said Order),—

(a) under the heading "Health Services",—

(i) against S. No. 91 in column (3) for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Junior Anaesthetist";

(ii) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"92A.	Smt. Rosda Fernandes	Staff Nurse	9-2-1958.";

(b) under the heading "Police"—,

(i) S. No. 134 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after S. No. 175 and the entries relating thereto, the following shall be inserted :—

"175 A. Shri Nanu S. Shirodkar

Police Constable 12-9-1954

175B. Shri V. S. Gaonkar

Police Constable 14-11-1956

175C. Shri Atchut M. Sail

Head Constable 30-12-1948

175 D. Shri Uday Kumar R. Kale

Police Constable 1-6-1965"

3. In Schedule II to the said Order,—

(a) under the heading "Health Services" S. No. 66 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) under the heading 'Police',—

(i) S. Nos. 104 and 105 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) S. Nos. 107 and 108 and the entries relating thereto shall be omitted.

(iii) after S. No. 108 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"108A.	Shri S. P. Dhure	Police Constable	17-2-1960"

Footnote.—Principal order was published vide No. S.O. 1295 dated 31st May, 1990 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 23id May, 1992.

[File No. 14012/2/87-GP]

ARUN MATHUR, Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1992

स्टाम्प

का.आ. 2485.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उन शुल्क को माफ करती है जो प्रोमिजरी नोटों के स्वरूप के बांड, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, के रूप में भारतीय थर्मल पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले केवल चार करोड़ रुपये मूल्य के समग्र बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य हैं :—

(क) 250 करोड़ रुपये मूल्य के एक-एक हजार रु. के 9 प्रतिशत (कर मुक्त) सुरक्षित विमोच्य बांडों की 8वीं श्रृंखला जिनकी विशिष्ट संख्या एच-00000001 से एच-2500000 है।

(ख) 150 करोड़ रु० मूल्य के एक-एक हजार रु० के 17 प्रतिशत सुरक्षित विमोच्य बांडों की 8 वीं श्रृंखला जिसकी विशिष्ट सं. 1 00000001 से 1500000 है।

[पत्र सं. 19/92-स्टाम्प फा.सं. 33/24/92 वि.क.

आत्मा राम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 1992

STAMPS

S.O. 2485.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes—described as—

(a) VIIIth Issue of 9 per cent (tax-free) Secured Redeemable bonds of the value of Rs. 250 crores bearing distinctive Nos. H 00000001 to H 2500000, of Rs. 1000 each;

(b) IXth Issue of 17 per cent secured redeemable bonds of the value of Rs. 150 crores bearing distinctive Nos. I 00000001 to 1500000, of Rs. 1,000 each,

of the aggregate value of rupees four hundred crores only to be issued by the National Thermal Power Corporation, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 19/92-Stamps-F. No. 33/24/92-ST]

ATMA RAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992

(आयकर)

का.आ. 2486.--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "पूणे टेनिस मण्डल पूणे" को 1990-91 से 1992-93 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उप धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों के संगत वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर, जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में से स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा, और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9083/फा.सं 196/1/90-आयकर (नि 1)]

केशव देव, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 2486.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Pune Tennis Mandal, Pune" for the purpose of the said clause for assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third proviso to the aforesaid clause (23)] for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grant to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9083/F. No. 196/1/90-IT(AI)]

KESHAV DEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992

आयकर

का.आ. 2487.--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया, मद्रास" को 1992-93 से 1994-95 तक के कर निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(1) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा की उप धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उनकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न (का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण करने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9084 फा.सं. 196/15/92-आयकर (नि.-1]

केशव देव, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 2487.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "The Federation of Motors Sports Clubs of India, Madras" for the purpose of the said clause for assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third proviso to the aforesaid clause (23)] for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grant to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9084/F. No. 196/15/92-IT(AI)]

KESHAV DEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992

(आयकर)

का.आ. 2488.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "बलसार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बलसार" को 1991-92 से 1993-94 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उप-धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) के विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा)

(3) कर निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपना आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं होगा तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9085 फा.सं. 196/20/91-आयकर (नि-1)]

केशव देव, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 2488.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Bulsar District Cricket Association, Bulsar" for the purpose of the said clause for assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third proviso to the aforesaid clause (23)] for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grant to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9085/F. No. 196/20/91-ITA-I]

KESHAV DEV, Dy. Secy.

(प्रधान समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय)

हैदराबाद, 8 सितम्बर, 1992

सं० 15/92-सीमा शुल्क (एन टी एच जैड०)

का.आ. 2489.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 6-4-90 तथा 18-6-90 की अधिसूचना सं. 16/90 सीमा शुल्क (एन.टी.) तथा 34/90 सीमा शुल्क (एन.टी.) अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूब नगर जिले के फरुकनगर मंडल के "शादनगर" ग्राम को औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समिति प्रयोजनार्थ शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भंडागार स्टेशन घोषित किया जाता है।

[फा.सी.सं. VIII/40/37/92-प्रधान समाहर्ता (एच. जैड.)]

जे. रामकृष्णन, प्रधान समाहर्ता

(Office of the Principal Collector of Customs & Central Excise)
Hyderabad, the 8th September, 1992

No. 15/92-Customs (NT)(HZ)

S.O. 2489.—In exercise of the powers conferred by Notification No. 16/90-Customs (NT) dated 6-4-90 and No. 34/90-Customs (NT) dated 18-6-90 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi "SHADNAGAR" Village, Farooqnagar Mandal, Mahaboob Nagar District in the State of Andhra Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Cus-

toms Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% Export Oriented Undertakings, approved by the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariat of Industrial Approvals, New Delhi.

[F. C. No. VIII/40/37/92-PC(HZ)]
J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2490.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. शाखा कार्यालय, 11-बी, गांधीनगर, दिल्ली
2. शाखा कार्यालय, 11-डी, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
3. शाखा कार्यालय, 11-ई, रूप नगर, दिल्ली
4. शाखा कार्यालय 11-एच, पलवल
5. शाखा कार्यालय, 11-के, फैज रोड, दिल्ली
6. शाखा कार्यालय, 11-एल, नरेला, दिल्ली
7. शाखा कार्यालय, 11-एम, शाहदरा, दिल्ली
8. शाखा कार्यालय, 11-पी, वजीरपुर, दिल्ली
9. शाखा कार्यालय, 11-यू, फरीदाबाद
10. शाखा कार्यालय, 12-बी, बदरपुर, दिल्ली
11. शाखा कार्यालय, 12-सी, कश्मीरी गेट, दिल्ली
12. शाखा कार्यालय, 12-डी, विवेक विहार, दिल्ली
13. शाखा कार्यालय, 12-एफ, मयूर विहार, दिल्ली
14. शाखा कार्यालय, 12-जे, जी.टी. रोड, बल्लभगढ़
15. शाखा कार्यालय, 12-के, दिलशाद गार्डन, दिल्ली
16. शाखा कार्यालय, 12-एल यमुना विहार, दिल्ली
17. शाखा कार्यालय, 12-पी, तिमारपुर, दिल्ली
18. शाखा कार्यालय, 12-आर, फरीदाबाद
19. शाखा कार्यालय, 114, चांदनी चौक, दिल्ली
20. शाखा कार्यालय, 116, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
21. शाखा कार्यालय, 123, माडल टाउन, दिल्ली
22. शाखा कार्यालय, 126, दरियागंज, नई दिल्ली
23. शाखा कार्यालय, 312, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली
24. शाखा कार्यालय, 314, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद
25. शाखा कार्यालय, 320, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
26. शाखा कार्यालय, 326, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
27. शाखा कार्यालय, 327, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
28. मंडल कार्यालय-II, शकरपुर, दिल्ली।

[सं. 13011/1/92-हि.का. क.]

प्रदीप पुरी, उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2490.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the Life Insurance Corporation of India (under the Administrative Control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. Branch Office, 11-B, Gandhinagar, Delhi.
2. Branch Office, 11-D, Lakshminagar, Delhi
3. Branch Office, 11-E, Roopnagar, Delhi
4. Branch Office, 11-H, Palval
5. Branch Office, 11-K, Faiz Road, Delhi
6. Branch Office, 11-L, Narela, Delhi
7. Branch Office, 11-M, Shahdara, Delhi
8. Branch Office, 11-P, Wazirpur, Delhi
9. Branch Office, 11-U, Faridabad
10. Branch Office, 12-B, Badarpur, Delhi
11. Branch Office, 12-C, Kashmiri Gate, Delhi
12. Branch Office, 12-D, Vivek Vihar, Delhi.
13. Branch Office, 12-F, Mayur Vihar, Delhi
14. Branch Office, 12-J, G. T. Road, Ballabhgarh
15. Branch Office, 12-K, Dilshad Garden, Delhi
16. Branch Office, 12-L, Yamuna Vihar, Delhi
17. Branch Office, 12-P, Timarpur, Delhi
18. Branch Office, 12-R, Faridabad
19. Branch Office, 114, Chandni Chowk, Delhi
20. Branch Office, 116, Asaf Ali Road, New Delhi
21. Branch Officer, 123, Model Town, Delhi
22. Branch Officer, 126, Daryaganj, New Delhi
23. Branch Officer,, 312, Friends Colony, New Delhi
24. Branch Officer, 314, Neelam Bata Road, Faridabad
25. Branch Office, 320, Asaf Ali Road, New Delhi
26. Branch Officer, 326, Asaf Ali Road, New Delhi
27. Branch Officer, 327, Asaf Ali Road, New Delhi
28. Divisional Office-II, Shakarpur, Delhi.

[No. 13011/1/92-HIC]

PRADEEP PURI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2491.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. कंपनी का नाम: नेशनल इंश्योरेंस कं.लि.

1. मंडल कार्यालय-4, दिल्ली
2. मंडल कार्यालय-5, दिल्ली
3. मंडल कार्यालय-10, दिल्ली
4. मंडल कार्यालय-11, दिल्ली
5. मंडल कार्यालय-13, दिल्ली
6. मंडल कार्यालय-15, दिल्ली
7. मंडल कार्यालय-3, इंदौर
8. मंडल कार्यालय, खंडवा
9. शाखा कार्यालय, बाराखंबा रोड
10. शाखा कार्यालय, कश्मीरी गेट
11. शाखा कार्यालय, अंबाला

12. शाखा कार्यालय, यूसुफ सराय
13. शाखा कार्यालय-3, इंदौर शहर
14. शाखा कार्यालय-4, इंदौर शहर
15. शाखा कार्यालय-2, भोपाल शहर
16. शाखा कार्यालय II-, भिलाई शहर
17. शाखा कार्यालय, रीवा
18. शाखा कार्यालय, उज्जैन शहर
19. शाखा कार्यालय, बदनावर

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि

1. मंडल कार्यालय-3, पटना
2. मंडल कार्यालय, चंडीगढ़
3. मंडल कार्यालय-II, चंडीगढ़
4. मंडल कार्यालय, करनाल
5. मंडल कार्यालय, अमृतसर
6. मंडल कार्यालय, शिमला
7. मंडल कार्यालय-क-1, बम्बई नगर
8. मंडल कार्यालय-क, 10, बम्बई
9. मंडल कार्यालय-क, 11, बम्बई नगर
10. मंडल कार्यालय-क, 13, बम्बई नगर
11. मंडल कार्यालय-क, 14, बम्बई नगर
12. मंडल कार्यालय-क, 18, बम्बई नगर
13. मंडल कार्यालय-क, 19, बम्बई नगर
14. मंडल इकाई, अमरावती
15. मंडल इकाई, अहमदनगर
16. मंडल इकाई, अकोला
17. मंडल-2 इकाई, नागपुर
18. मंडल-1 इकाई, नागपुर
19. मंडल इकाई, सोलापुर
20. मंडल इकाई, सतारा
21. क्षेत्रीय कार्यालय-1, बम्बई
22. शाखा कार्यालय, डाल्टेगंज
23. शाखा कार्यालय, बक्सर
24. शाखा कार्यालय, हनुमानगढ़
25. शाखा कार्यालय, अमृई
26. शाखा कार्यालय-2, चंडीगढ़
27. शाखा कार्यालय-3, चंडीगढ़
28. शाखा कार्यालय-4, चंडीगढ़
29. शाखा कार्यालय, रोपड़
30. शाखा कार्यालय-2, हिसार
31. शाखा कार्यालय, अम्बाला सिटी
32. शाखा कार्यालय, जगाधरी
33. शाखा कार्यालय, नाहन
34. शाखा कार्यालय, गुहाना
35. शाखा कार्यालय, छहरत्ता
36. शाखा कार्यालय-1, अमृतसर
37. शाखा कार्यालय-2, अमृतसर
38. शाखा कार्यालय-2, शिमला
39. शाखा कार्यालय, औरंगाबाद
40. शाखा कार्यालय, यवतमल
41. शाखा कार्यालय, सांगली
42. शाखा कार्यालय, राजापुर
43. शाखा कार्यालय, रत्नागिरी
44. शाखा कार्यालय, श्रीगोंदा
45. शाखा कार्यालय, सगमनेर
46. शाखा कार्यालय, श्रीरामपुर
47. शाखा कार्यालय, अंकोला
48. शाखा कार्यालय, खामगांव
49. शाखा कार्यालय, वाशिम
50. शाखा कार्यालय-4, नागपुर
51. शाखा कार्यालय, चन्द्रपुर
52. शाखा कार्यालय, गोंदिया
53. शाखा कार्यालय, लातुर
54. शाखा कार्यालय, बीड
55. शाखा कार्यालय, सातपुर
56. शाखा कार्यालय, कराड

[सं. 13011/1/92-हि.क.-1]

प्रदीप पुरी, उप सचिव

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2491.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notices the following offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative Control of, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 percent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. Name of the Company; National Insurance Company Ltd.,

1. Divisional Office-4, Delhi
2. Divisional Office-5, Delhi
3. Divisional Office-10, Delhi
4. Divisional Office-11, Delhi
5. Divisional Office-13, Delhi
6. Divisional Office-15, Delhi
7. Divisional Office-3, Indore
8. Divisional Office. Khandwa
9. Branch Office, Barakhamba Road
10. Branch Office, Kashmiri Gate
11. Branch Office, Okhla
12. Branch Office, Yusuf Sarai
13. Branch Office-3. Indore City
14. Branch Office-4, Indore City
15. Branch Office-2. Bhopal City
16. Branch Office-II, Bhilai City,
17. Branch Office, Rewa
18. Branch Office, Ujjain City
19. Branch Office, Badnavar

2. The Oriental Insurance Co. Ltd.,

1. Divisional Office-3, Patna
2. Divisional Office, Chandigarh
3. Divisional Office-II, Chandigarh
4. Divisional Office, Karnal
5. Divisional Office, Amritsar
6. Divisional Office, Shimla

7. Divisional Office-A. 1, Bombay City
8. Divisional Office A. 10, Bombay
9. Divisional Office-A. 11, Bombay City
10. Divisional Office-A. 13, Bombay City
11. Divisional Office-A. 14, Bombay City
12. Divisional Office-A. 18, Bombay City
13. Divisional Office-A. 19, Bombay City
14. Divisional Office-Amravati
15. Divisional Unit, Ahmednagar
16. Divisional Unit, Akola
17. Divisional-2, Unit, Nagpur
18. Divisional-1, Unit, Nagpur
19. Divisional Unit, Sholapur
20. Divisional Unit, Satara
21. Regional Office-1, Bombay
22. Branch Office, Daltenganj
23. Branch Office, Buxer
24. Branch Office, Hanumangarh
25. Branch Office, Jamui
26. Branch Office-2, Chandigarh
27. Branch Office-3, Chandigarh
28. Branch Office-4, Chandigarh
29. Branch Office, Ropar
30. Branch Officer-2, Hissar
31. Branch Office, Ambala City
32. Branch Office, Jagadhri
33. Branch Office, Nahan
34. Branch Office, Juhana
35. Branch Office, Chahratta
36. Branch Office-1, Amritsar
37. Branch Office-2, Amritsar
38. Branch Office-1, Shimla
39. Branch Office, Aurangabad
40. Branch Office, Yavatmal
41. Branch Office, Sangli
42. Branch Office, Rajpur
43. Branch Office, Ratangiri
44. Branch Office, Shrigoda
45. Branch Office, Sagamnet
46. Branch Office, Shrirampur
47. Branch Office, Akola
48. Branch Office, Khamgaon
49. Branch Office, Vashim
50. Branch Office-4, Nagpur
51. Branch Office, Chanderpur
52. Branch Office, Gondia
53. Branch Office, Latur
54. Branch Office, Beedh
55. Branch Office, Satpur
56. Branch Office, Karadh

[No. 13011/92-HIC]

PRADEEP PURI, Dy. Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का०आ० 2492.—निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 9 सितम्बर, 1992 से तीन वर्षों की अवधि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है :—

1. श्रीएन०पी०सारडा,
चार्टर्ड लेखाकार,
बम्बई ।

2. डा० पी० डब्लू० रेगे,
भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत,
सहकारी बैंक लि० ।

[एफ० सं० 7/2/91-बी०ओ० 1(i)]

एम०एस० सीतारामन, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2492.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons as directors of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation with effect from 9th September, 1992 for a period of three years :—

(1) Shri N. P. Sarda,
Chartered Accountant
Bombay.

(2) Dr. P. W. Rege,
Ex-Chairman of Saraswat
Co-operative Bank Ltd.

[F. No. 7/2/91-B.O.I.(i)]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का०आ० 2493.—निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री गंगाधर गाडगिल, अर्थशास्त्री, बम्बई को 9 सितम्बर, 1992 से तीन वर्षों की अवधि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है ।

[एफ० सं० 7/2/91-बी०ओ० 1(ii)]

एम०एस० सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2493.—In pursuance of the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government after

consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Prof. Gangadhar Gadgil, Economists, Bombay, as a director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation with effect from 9th September, 1992 for a period of three years.

[F. No. 7/2/91-B.O.I. (ii)]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का० आ० 2494 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 9 के साथ पठित खण्ड 3 के उप खण्ड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, वर्तमान में अंचल कार्यालय, ग्रेटर बम्बई अंचल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बम्बई में तैनात श्री के०के० नायर वरिष्ठ प्रबन्धक [एम०एम०जी०एस० III] को 9 सितम्बर, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ 9/28/91-बी०ओ० 1]

एम०एस० सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2494.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K. K. Nair, Senior Manager (MMGS-III), presently posted in the Zonal Office, Greater Bombay Zone, Bank of Baroda, Bombay, as a Director on the Board of Bank of Baroda with effect from the 9th September, 1992 for a period of three years or until he ceases to be an Officer of Bank of Baroda, Whichever is earlier.

[F. No. 9/28/91-B.O.I.]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1992

का०आ० 2495:—रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० शंकरनारायणन, आई ए एस (कर्नाटक 1957) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा 31 दिसम्बर, 1994 तक, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 7/20/92-बी ओ-1]

एम०एस० सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 1992

S.O. 2495.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (2) of section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Central Government hereby appoints Shri M. Sankaranarayanan, IAS (Karnataka : 1957) as a Member of the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction for the period from the date of his taking charge and upto 31st December, 1994.

[No. 7/20/92-B.O.I.]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नारियल विकास बोर्ड

कोची, 21 सितम्बर, 1992

का०आ० 2496.—नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का पंचम) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारियल विकास बोर्ड केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :—(1) ये विनियम नारियल विकास बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1992 कहलाएंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ये प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है—नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979.

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन गठित नारियल विकास बोर्ड,

(ग) "अध्यक्ष" और "सचिव" पदों का अर्थ, जहां भी प्रयुक्त हों, क्रमशः बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव होगा।

(घ) "परिलब्धियों" का अर्थ है—वेतन, जिसमें महंगाई वेतन यदि हों, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, और अवकाश वेतन अथवा जीवन निर्वाह अनुदान, यदि अनुमत्य हो, और विदेश सेवा से संबंधित वेतन के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक सम्मिलित हैं, किन्तु महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं।

(ङ) "परिवार" का अर्थ है :—

(I) पुरुष अंशदाताओं के मामले में पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे और यदि अंशदाता के माता-पिता जीवित न हों तो, दादा-दादी;

बशर्ते कि यदि अंशदाता यह प्रमाणित करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से पृथक हुई थी या वह उसके समुदाय की पारंपरिक विधि के अधीन जीवन निर्वाह की हकदार न रही हो तो इन विनियमों से संबंधित मामलों में पत्नी को तत्पश्चात् अंशदाता के परिवार की सदस्या तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बाद में अंशदाता सचिव को लिखित रूप से यह सूचित नहीं करता कि उसे वैसे माना जाए।

(II) स्त्री अंशदाताओं के मामलों में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा व बच्चे, और यदि अंशदाता के माता-पिता जीवित न हो, तो दादा-दादी।

बशर्ते कि अगर अंशदाता सचिव को लिखित रूप से सूचना देकर हलफा व्यक्त करे कि उसके परिवार में पति को शामिल न किया जाए, तत्पश्चात् पति को इन विनियमों से संबंधित मामलों में अंशदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि, बाद में, अंशदाता लिखित रूप से सूचना को रद्द नहीं करता।

टिप्पणी :

(1) "बच्चे" का अर्थ है वैध बच्चे।

(2) गोद लिए गए बच्चे को "बच्चा" तभी माना जाएगा, जब अध्यक्ष या यदि अध्यक्ष के मन में संदेह उत्पन्न हो तो बोर्ड संतुष्ट हो कि अंशदाता के वैयक्तिक कानून के अधीन इस बंध बच्चे की स्थिति गोद लेने से न्यायिक रूप से प्राप्त होती है।

(च) "निधि" का अर्थ है विनियम 3 के द्वारा गठित एवं स्थापित सामान्य भविष्य निधि।

(छ) "छुट्टी" का अर्थ है केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के अधीन बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को स्वीकृत किसी भी प्रकार की छुट्टी।

(ज) "बोर्ड का कर्मचारी" का अर्थ है बोर्ड का वेतन पाने वाला अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा-रत जिनकी सेवाएं बोर्ड को उधार दी गई हों या स्थानांतरित की गई हों।

(झ) "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष।

(ञ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों की अनुसूची।

(ट) यहां जो शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं हैं उनका अर्थ क्रमशः वैसा होगा जैसा अधिनियम, और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19वां) या मूलभूत नियमावली या सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली 1960 में, उनके लिए दिया गया है, जो भी लागू हो।

3. निधि का संस्थापन : (1) बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि संस्थापित की जाएगी।

(2) निधि इससे बनेगी :—

(अ) बोर्ड की भविष्य निधि में बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान और उस पर 31 मार्च 1991 को लागू ब्याज।

(आ) इन नियमों के अनुरूप निधि में जमा किए जाने वाले अंशदान।

(इ) इन विनियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी राशियां "नारियल विकास बोर्ड सामान्य भविष्य निधि" में जमा की जाएंगी।

(ई) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा समय-समय पर निधि में किए जाने वाले अन्य ऐसे अंशदान।

(उ) ऋण, जमा तथा निवेशों से प्राप्त निधि की आय।

(ऊ) ऐसी राशियां वर्ष के अन्त में निधि में जमा की जाएंगी जो देय होने के पांच साल के भीतर न ली गई हों।

4. निधि का प्रबंधन : निधि, बोर्ड में निहित होगी। बोर्ड की ओर से तथा कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित अथवा कार्यकारी समिति द्वारा बोर्ड से निर्दिष्ट सीमा तक अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित होगी।

5. पात्रता की शर्तें : निधि में अंशदान करने के पात्र हैं :—

(1) बोर्ड की स्थापना के बाद नारियल विकास निदेशालय से स्थानांतरित होने पर 12-1-81 से बोर्ड की सेवा में रहे कर्मचारी और जो इस सेवा में इन विनियमों की अधिसूचना के दिनांक से हों तथा 12-1-1981 को या तदनंतर एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो; और

(2) (1) बोर्ड का हर कर्मचारी (पुनर्नियुक्ति पेंशन प्राप्त को छोड़) जो बोर्ड की सेवा में 12-1-1981 या उसके बाद आया और उसकी सेवा-रत रहा है और जिसने एक वर्ष से कम सेवा न की हो, उन अधिकारियों को छोड़कर, जिनकी सेवाएं किसी सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपी गई हों और जिनके संबंध में बोर्ड से अपेक्षित है कि वह छुट्टी पेंशन या भविष्य निधि अंशदान उस सरकार को दे।

(2) ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो एक वर्ष की सेवा महीने के मध्य में पूरी करता है वह निधि में अंशदान आगामी महीने से देगा।

(3) हर ऐसा कर्मचारी इस निधि में अंशदान देगा जिस पर ये विनियम लागू होते हैं।

6. नामांकन : (1) अंशदाता निधि में शामिल होने समय सचिव को ऐसा नामांकन भेजेगा, जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को यह अधिकार देगा उसकी मृत्यु होने पर, निधि के उसके खाते में बकाया राशि प्राप्त करेगा, या वह राशि देय होने के पहले या देय होने के बाद दी नहीं गयी हो, प्राप्त करने का अधिकार देगा। बशर्ते कि अंशदाता यदि नाबालिग हो, वह वयस्कता की उम्र प्राप्त होने पर ही नामांकन करेगा।

आगे बशर्ते कि नामांकन करते समय अंशदाता का परिवार है तो वह ऐसा नामांकन परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम ही करेगा।

आगे बशर्ते कि निधि में शामिल होने से पहले अंशदाता यदि किसी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और यदि उस अन्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा राशि निधि में अंतरित हो गई है,

आगे बशर्ते कि अंशदाता निधि में होने से पहले किसी अन्य निधि में अंशदान कर रहा था और वहां उसने नामांकन कर दिया था, यदि उसे अन्य भविष्य निधि के उसके खाते में जमा राशि निधि में अंतरित हो गई है तो वह नामांकन इन विनियमों के अधीन विधिवत किया गया नामांकन माना जाएगा, तब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन कर देता है।

(2) अगर अंशदाता उपखंड (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह, नामांकन में हर नामांकित को देय राशि या हिस्सा ऐसे विनिर्दिष्ट करेगा जिससे पूरी राशि का विभाजन, जो निधि के उसके खाते में किसी समय बकाया हो, हो जाता है।

(3) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में ही हर नामांकन किया जाएगा।

(4) अंशदाता किसी भी समय सचिव को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है। अंशदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार नया नामांकन भेजेगा।

(5) अंशदाता नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है कि :

(अ) अंशदाता के पहले किसी विनिर्दिष्ट नामांकित की मृत्यु होने पर उसे प्रदत्त अधिकार अन्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को मिलेंगे जो नामांकन में विनिर्दिष्ट हों; बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति अंशदाता के परिवार में अन्य सदस्य हो/हों तो ऐसे अन्य सदस्यों को। यदि इस खंड के अधीन अंशदाता ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को देता है तो वह विनिर्दिष्ट करेगा कि नामांकित को देय पूरी राशि की कितनी राशि या हिस्सा हर एक व्यक्ति को मिलेगा।

(आ) कि उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा :

बशर्ते कि नामांकन करते समय अंशदाता के परिवार में एक ही सदस्य हो तो वह यह प्रावधान करेगा कि आगे चलकर उसके परिवार में अन्य सदस्य प्राप्त होने की दशा में खंड (अ) के अधीन एकांतर नामांकित को प्रदत्त अधिकार अवैध होगा।

(6) ऐसे नामांकित की मृत्यु के तुरन्त बाद जिसके बारे में उप-विनियम नियम (5) के खंड (अ) के अधीन नामांकन में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है या ऐसी कोई घटना होती है जिसके कारण खंड (5) के उपखंड (आ) या उसके अनुबंध के अनुसार नामांकन अवैध हो जाता है, अंशदाता सचिव को लिखित रूप से नामांकन रद्द करने की सूचना देते हुए इस विनियम के प्रावधान के अनुसार नया नामांकन भेजेगा।

(7) अंशदाता द्वारा किया गया हर नामांकन या रद्द करने की हर सूचना, जहा तक वैध है, सचिव को प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में अगर किसी संदर्भ में अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो तो, "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अर्थ में कम्पनी या समिति या व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है, चाहे वे निगमित हो न हों।

7. अंशदाता खाता : हर अंशदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा जिसमें दर्शाया जाएगा :—(अ) उसका अंशदान, (आ) विनियम 12 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट रूप से ब्याज, (इ) निधि से अग्रिम तथा निकासियां।

8. अंशदान की शर्तें : अंशदाता, अपनी निलंबन की अवधि को छोड़, माहवार अंशदान करेगा :

बशर्ते कि अंशदाता यदि चाहता है, औसत वेतन की छुट्टी या अर्जित छुट्टी को छोड़ अपनी छुट्टी की अवधि में अंशदान करना छोड़ सकता है

आगे बशर्ते कि अंशदाता को, निलंबन की अवधि के बाद बहाल होने पर एक या दो किस्तों में उतनी राशि का अंशदान करने की अनुमति दी जाएगी, जो ऐसी अवधि के संबंध में देय बकाया अंशदानों की राशि से अधिक न हो। (2) अंशदाता छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का अपना विकल्प निम्नलिखित रूप से देगा :—

(अ) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपने वेतन पर्चे स्वयं आहरित करता है, तो छुट्टी पर जाने के बाद के प्रथम पर्चे में अंशदान संबंधी कटौती न करके,

(आ) अगर वह अपना वेतन स्वयं आहरण करने वाला अधिकारी नहीं है, तो सचिव/आहरण व संवितरण अधिकारी को छुट्टी पर जाने से पहले लिखित सूचना देकर, समय पर विधिवत सूचना न दी जाए तो समझा जाएगा कि उसने अंशदान करना स्वीकार किया है।

टिप्पणी :—इस उप खंड के अधीन अंशदाता द्वारा दी गई विकल्प की सूचना अंतिम मानी जाएगी।

(3) विनियम 20 के अधीन निधि के अपने खाते में जमा राशि को जिस अंशदाता ने निकाल लिया हो वह ऐसी निकासियों के बाद कार्य-भार ग्रहण करने तक निधि में अंशदान नहीं करेगा।

(4) उपखंड "1" में कुछ भी होते हुए भी अंशदाता उस महीने में निधि में अंशदान नहीं करेगा जिसमें वह सेवा छोड़ता है, किन्तु यदि उक्त महीने के प्रारम्भ से पहले वह सचिव/आहरण व संवितरण अधिकारी को लिखित रूप से अंशदान देने का अपना विकल्प सूचित करता है तो निधि में अंशदान कर सकता है।

(5) जो अंशदाता उत्पादकता से जुड़े बोनस का हकदार है यदि वह चाहे योजना के अनुसार पूरी रकम या उसका अंश भविष्य निधि खाते में जमा कर सकता है।

9. अंशदान की दरें : (1) अंशदान की रकम अंशदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसकी निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(अ) वह पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त हो;

(आ) वह कितनी भी रकम हो सकती है, मगर उसके वेतन के छः प्रतिशत से कम या कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

(2) खंड (1) के प्रयोजन के लिए वेतन यानी (अ) पिछले वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में रत अंशदाता के मामले में वह वेतन जिसके लिए वह उस दिनांक को हकदार था :

बशर्ते कि (1) अगर उस तारीख को अंशदाता छुट्टी पर था और उसने वह छुट्टी की अवधि में अंशदान न करने का विकल्प दिया था उस तारीख को वह निलंबित था, तो उसका वेतन वह होगा जिसका हकदार वह छुट्टी से लौटकर कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम दिन होता।

(2) यदि अंशदाता उस तारीख को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और आगे भी छुट्टी पर रहता है तो उसकी परिलब्धियां, वह वेतन होगा जिसका हकदार वह भारत में कार्यरत होने पर होता।

(आ) ऐसे अंशदाता के मामले में जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था तो वह वेतन जिसका हकदार निधि में शामिल होने के दिन था।

3. अंशदाता हर साल सचिव को लिखित रूप से अपने माहवार अंशदान की निर्धारित राशि की सूचना देगा या निम्नांकित रीति से जो भी लागू हो :—

(अ) यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को कार्यरत था, तो उस महीने के अपने वेतन पर्चे से इस संबंध में जो कटौती दिखाता है उसके द्वारा,

(आ) पिछले वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और उस छुट्टी के दौरान अंशदान न देने का विकल्प दिया था या उस तारीख को निलंबित था तो छुट्टी से लौटने के बाद के प्रथम वेतन पर्चे में इस संबंध जो कटौती दिखाता है उसके द्वारा,

(इ) यदि वह बोर्ड की सेवा में वर्ष में पहली बार आया है तो निधि में शामिल होनेवाले महीने के अपने वेतन पर्चे में इस संबंध में कटौती दिखाने के द्वारा,

(ई) पिछले वर्ष के 31 मार्च को यदि वह विदेश सेवा में था तो चालू वर्ष के अप्रैल मास के अंशदान के लिए उसके द्वारा बोर्ड को जमा राशि द्वारा।

(4) अंशदान की इस तरह निर्धारित राशि को :—

(अ) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार घटाया जा सकता है,

(आ) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है,

(इ) पूर्वोक्त रूप से घटाया बढ़ाया जा सकता है, :

बशर्ते कि इस तरह घटाई गई राशि उप खंड (1) में नियत न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी :

आगे बशर्ते कि यदि अंशदाता कैलेण्डर मास के किसी भाग में अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन की छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी की अवधि अंशदान न देने का विकल्प दिया हो, तो देय अंशदान की राशि ऊपर उल्लिखित छुट्टियों को छोड़ यदि अन्य किसी छुट्टी सह ड्यूटी पर जितने दिन था उनके भुगतान पर निर्भर होगी।

10. विदेश सेवा में स्थानांतरण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति:–

जब कोई अंशदाता विदेश सेवा में स्थानांतरित होता है या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो निधि के अनुबंधों की शर्तों से बंधा रहेगा जैसे कि वह इस तरह स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर भेजने जाने पर रहता है।

11. अंशदान की वसूली:—(1) बोर्ड को ये अधिकार होंगे कि वह किसी अंशदाता की परिलब्धियों से ऐसी कटौती करे जैसे कि उससे बकाया अंशदान, अग्रिम का मूल तथा उस पर ब्याज, यदि हो, जो उसे निधि से दिए गए हों।

(2) जब परिलब्धियां अन्य किसी स्रोत से आहरित होती हों तो अंशदाता अपना बकाया सचिव को माहवार प्रेषित करेगा :

बशर्ते कि ऐसे अंशदाता के मामले में जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर है, तो अंशदान उस निकाय द्वारा वसूल करके सचिव को प्रेषित किए जाएंगे।

(3) यदि अंशदाता, निधि में शामिल होने की अपेक्षित तारीख से अंशदान नहीं करता या विनियम 8 के अनुबंध से भिन्न रूप में वर्ष के किसी महीने या महीनों में चूक जाता है तो अंशदान के बकाया के रूप में निधि को देय कुल राशि और उस पर विनियम 12 में निर्दिष्ट ब्याज निधि में अंशदाता द्वारा जमा करना होगा या चूक जाने पर सचिव द्वारा अंशदाता की मूल परिलब्धियों में से किस्तों में या अग्रिम मंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसे निर्देश दिए जाते हैं, जिसके लिए विनियम 13 के उप विनियम (2) के अंतर्गत विशेष कारण अपेक्षित है, वसूल करने का आदेश दिया जाएगा।

12. ब्याज:—(1) बोर्ड, अंशदाता के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) के लिए हर वर्ष हेतु निर्धारित दरों पर उसके द्वारा समय-समय पर नियत गणना के विधान से ब्याज जमा करेगा।

(2) ब्याज, हर वर्ष के 31 मार्च से निम्नांकित रूप से जमा किया जाएगा :–

(1) अंशदाता के खाते में पिछले वर्ष के अंतिम दिन को जमा राशि पर–चालू वर्ष में निकाली गई रकम को काटकर 12 महीने के लिए ब्याज ;

(2) चालू वर्ष में निकाली गई राशियों पर चालू वर्ष के प्रारंभ से निकासी के महीने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन तक ब्याज:–

(3) पिछले वर्ष के अंतिम दिन के बाद अंशदाता के खाते में जमा सब राशियों पर जमा करने की तारीख से चालू वर्ष के अंत तक ब्याज;

(4) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपये में बदला जाएगा (50 पैसे की गिनती अगले उच्च रुपए में होगी);

बशर्ते कि अंशदाता के खाते में जमा राशि जब देय हुई हो तो इस विनियम के अधीन उस पर का ब्याज, केवल वर्ष के आरम्भ से या जमा की तारीख से जो भी लागू हो, उस तारीख तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा, जब अंशदाता के खाते में की राशि देय हो जाती है;

3. इस विनियम में यदि उसी महीने के अंतिम कार्य दिवस को परिलब्धियों का आहरण और संवितरण किया जाता है तो अंशदानों की वसूली के मामले में, जमा करने की तारीख, आनेवाले महीने का पहला दिन मानी जाएगी जिसमें वसूली की जाती है, और अंशदाता द्वारा प्रेषित राशि संबंध में, प्राप्ति के परवर्ती महीने का पहला दिन माना जाएगी, यदि वह परवर्ती महीने के पांचवें दिन से पूर्व सचिव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि वह अगले महीने के पांचवें दिन को या उसके बाद, प्राप्त होती है तो अगले परवर्ती महीने का प्रथम दिन मानी जाएगी :

बशर्ते कि अंशदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसका अंशदान भी विलंबित हो, तो ऐसे अंशदानों पर ब्याज, अंशदाता का वेतन, या छुट्टी वेतन जिस महीने में देय था, वस्तुतः जिस किसी महीने में आहरित होने पर भी, उसी महीने से देय होगा :

आगे बशर्ते कि विनियम 11 के खंड (2) के अनुबंध के अनुसार प्रेषित राशि के मामले में जमा की तारीख, यदि वह उस महीने के पंद्रहवें दिन से पहले प्राप्त हो तो, महीने का पहला दिन मानी जाएगी।

(4) विनियम 19,20,21 के अधीन दी जाने वाली किसी राशि के अतिरिक्त उन पर ब्याज का जिस महीने में भुगतान किया गया हो, उसके पूर्व वाले महीने के अंत तक अथवा ऐसी राशि के देय हो जाने के बाद के छठे महीने के अंत तक, इनमें से जो भी अवधि कम हो, ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा जिसे दिया जाना हो :

बशर्ते कि सचिव ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को उस तारीख की सूचना दी है जब वह नकद रूप से भुगतान करने को तैयार हैं या भुगतान का चेक भेजा है, सूचित तारीख या चेक भेजने के पूर्ववर्ती महीने के अंत तक ही ब्याज देय होगा, जो भी लागू हो।

5. विनियम 11 के खंड 2, विनियम (14) के खंड (ii) विनियम 19 या 20 के अंतर्गत निधि में अंशदाता के खाते में स्थापित की जानेवाली राशियों पर ब्याज की गणना उन दरों पर होगी जैसा कि खंड (1) में क्रमशः नियत की जाए और इस विनियम में वर्णित रीति से हो।

13. निधि से अग्रिमः (1) अध्यक्ष निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी अंशदाता को निधि से अग्रिम की मंजूरी दे सकते हैं जो पूर्ण रुपयों में होगा और तीन महीने के वेतन के समान राशि से अधिक नहीं होगा या अंशदाता के खाते में जमा राशि का आधा होगा, जो भी कम हो :—

(अ) अंशदाता या उस पर वस्तुतः निर्भर परिवार के सदस्यों, अन्यों की अस्वस्थता, प्रसूति या अशक्यता के संबंध में भुगतान करने के लिए, इसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा का खर्च भी शामिल है:—

(आ) निम्नलिखित मामलों में, अंशदाता या उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर अन्य व्यक्ति की उच्च शिक्षा, जिसमें यात्रा खर्च भी शामिल है, यथा:—

(1) भारत के बाहर हाई स्कूल से उच्च शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक या औद्योगिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए ; और

(2) भारत में हाई स्कूल से उच्च चिकित्सकीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या वैशिष्टिक पाठ्यक्रम के लिए, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्षों से कम अवधि का न हो।

(इ) अंशदाता के या उसके बच्चे या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित अन्य व्यक्ति की सगाई, या शादी या, अंतिम संस्कार या अन्य समारोहों के अनिवार्य खर्चों के भुगतान के लिए जो दाता को हैसियत के अनुरूप संप्रदायों के कारण करने पड़ते हैं, बशर्ते वास्तविक रूप से आश्रित होने की शर्तें अंशदाता की बेटी या बेटे पर लागू नहीं होगी।

आगे शर्त कि वास्तविक रूप से आश्रित होने की शर्त अंशदाता के जन्मदाताओं के अंतिम संस्कार के खर्चों के आवश्यक अग्रिम पर लागू नहीं होगी।

(ई) अंशदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित अन्य व्यक्ति द्वारा या के खिलाफ दायर कानूनी कार्यवाहियों का खर्च उठाने के लिए, इस मामले में, इसी प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्रोत के अतिरिक्त, [illegible]

बशर्ते कि इस खंड के अधीन अग्रिम अंशदाता को अनुमत्य नहीं होगा, यदि वह किसी न्यायालय में अपने कार्यालयीन कार्य से संबंध न रखने वाले मामले में या बोर्ड के खिलाफ किसी सेवा-शर्त या उस पर लगाए दंड के संबंध में मुकदमा दायर करे।

(ङ) उसके द्वारा कथित रूप से किये गये कार्यालयीन कदाचरण संबंधी जांच के दौरान यदि अंशदाता ने अपने बचाव के लिए वकील को नियुक्त किया है तो, वह खर्च उठाने के लिए;

(ऊ) प्लॉट खरीदने के लिए या अपने वास के लिए आवास फ्लैट निर्माण के लिए या राज्य आवास बोर्ड या सहकारी गृह निर्माण समिति से फ्लैट या प्लॉट के आबंटन के संबंध में भुगतान के लिए :

(2) किसी अंशदाता को खंड (1) में रखी गई सीमा से अधिक अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा—विशिष्ट कारणों को छोड़कर जिनका उल्लेख लिखित रूप से किया जाना चाहिए—या जब तक पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त की अदायगी करने तक नया अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) यदि पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त की अदायगी पूर्ण होने से पहले कोई अग्रिम खंड (2) के अधीन मंजूर किया जाए तो, इस अग्रिम में पहले अग्रिम की शेष राशि जोड़ी जाएगी, और समेकित राशि के अनुसार वसूली की किस्तें तय की जाएंगी।

टिप्पणी: (1) इस खंड 5 के प्रयोजनार्थ वेतन में वेतन और अनमत्य हो, तो मंहगाई वेतन शामिल है।

(2) विनियम 13 के खंड (1) के (आ) के अधीन अंशदाता को हर छः महीने में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति होगी।

14. अग्रिमों की वसूली: (1) अग्रिम की वसूली, मंजूर करने वाले प्राधिकारी के निदेशानुसार अंशदाता से समान मासिक किस्तों में की जाएगी किन्तु ये किस्तें यदि अंशदाता नहीं चाहता है बारह से कम और चौबीस से अधिक नहीं होंगी। विशिष्ट मामलों में, विनियम 13 के खंड (2) के अधीन अंशदाता के तीन महीने से अधिक अग्रिम की राशि हो तो मंजूर करने वाला प्राधिकारी इन किस्तों की संख्या चौबीस से ज्यादा तय कर सकता है मगर किसी हालत में छत्तीस से ज्यादा नहीं होगी। अंशदाता, अपनी इच्छा से, महीने में एक से ज्यादा किस्तें चुका सकता है। किस्त पूर्ण रुपयों की संख्या में होगी और इस तरह किस्तों के निर्धारण की सहूलियत के लिए अग्रिम की राशि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

(2) अंशदानों की वसूली के लिए विनियम 11 में निर्धारित रूप में वसूली की जाएगी और जिस महीने में अग्रिम निकाला गया हो उसके अगले महीने से शुरु होगी। जब अंशदाता जीवन-निर्वाह अनुदान पा रहा हो या औसत वेतन को छोड़ अन्य प्रकार की छुट्टी या जो 30 दिन से कम अवधि की अर्जित छुट्टी पर हो तो, अंशदाता के मान लेने पर ही वसूली की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अंशदाता के लिखित अनुरोध पर मंजूर करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अंशदाता को मंजूर वेतन अग्रिम की वसूली स्थगित की जा सकती है।

(3) अंशदाता को यदि अग्रिम की मंजूरी दी गई हो और वह आहरित की गई हो और प्रतिसंदाय के पूर्ण होने के पहले, वह अस्वीकृत हो जाए, निकाली गई पूरी या उसकी शेष राशि का प्रतिसंदाय अंशदाता द्वारा तुरंत करना होगा, चूक जाने पर सचिव द्वारा आदेश जारी किया जाएगा कि अंशदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त या मासिक किस्तों में, जो बारह से ज्यादा नहीं होंगी, काटी जाए, जैसे कि विनियम 13 के खंड (2) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों के होने पर अग्रिम मंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी निर्देश देते हैं।

(4) इस विनियम के अंतर्गत की गई वसूलियां, निधि में अंशदाता के खाते में जमा जिस प्रकार की जाती है, उसी प्रकार जमा की जाएंगी।

15. अग्रिमों का अनुचित उपयोग: इन विनियमों में होने हुए भी विनियम 13 के अधीन निधि से निकाली गई राशि का उपयोग, जिस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है, ऐसा मंजूर करनेवाले प्राधिकारी को कारण सहित लगे, तो वह अंशदाता को अपने शक की सूचना देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर स्पष्ट करे कि धन की निकासी के लिए दिए गए प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया गया है या नहीं उक्त पंद्रह दिन की अवधि में अंशदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से मंजूर करने वाले प्राधिकारी संतुष्ट न हों तो वह अंशदाता को निर्देश देगा कि वह उक्त राशि निधि में तुरन्त संदाय करे या चूकने पर अंशदाता की परिलब्धियों में से वह छुट्टी पर हो तो भी एक मुश्त कटौती द्वारा, राशि की वसूल करने का आदेश देगा, यदि प्रतिसंदाय की राशि अंशदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियां परिलब्धियों में से मासिक किस्तों में पूरी राशि अदा होने तक की जाएगी।

टिप्पणी:—इस विनियम में "परिलब्धियों" में जीवन-निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

16. निधि से निकासियां: (1) विनियम 13 के खंड (2) के अधीन अध्यक्ष किसी भी समय यहां निर्दिष्ट शर्तों पर निकासियों की मंजूरी दे सकते हैं।

(अ) अंशदाता द्वारा बीस वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर (यदि हो, तो अवरत अवधि सहित) या उसके अधिवर्षिता प्राप्त करने के कारण सेवा निवृत्ति की तारीख से दस वर्ष पहले, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि से, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए यथा:—

(क) अंशदाता के या उसके बच्चे के, जहां आवश्यक हो यात्रा खर्च, उच्च शिक्षा का खर्च उठाने के लिए निम्नलिखित मामलों में, यथा—

(i) भारत के बाहर शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक या औद्योगिक पाठ्यक्रम जो हाई स्कूल श्रेणी से ऊपर से हों; और

(ii) भारत में हाई स्कूल के ऊपर के चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए;

(ख) अंशदाता या उसके बेटे या बेटियों की और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित अन्य महिला संबंधियों की सगाई या शादी-संबंधी खर्च उठाने के लिए;

(ग) अंशदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित अन्य व्यक्ति की अस्वस्थता, यदि आवश्यक हो, तो यात्रा खर्च सहित, से संबंधित खर्च उठाने के लिए;

(आ) अंशदाता द्वारा दस वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर, (यदि हो) अवरत अवधि सहित) या अधिवर्षिता प्राप्त होने के कारण सेवा निवृत्त होने की तारीख से दस वर्ष पूर्व, निधि में, अंशदाता के खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए यथा:—

(क) अपने लिए उचित आवास के निर्माण या बने हुए मकान, फ्लैट हासिल करने के लिए, जिसमें साइट की लागत भी शामिल है;

(ख) अपने लिए उचित आवास के निर्माण या बने हुए मकान या फ्लैट हासिल करने के लिए व्यक्त रूप से लिए गए ऋण की बकाया रकम की अदायगी के लिए;

(ग) अंशदाता द्वारा पहले से हासिल किए हुए मकान या फ्लैट के विस्तरण या उसमें परिवर्तन के लिए;

(घ) अपने लिए मकान निर्माण करने हेतु साइट खरीदने या इस खरीदी के लिए व्यक्त रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि की अदायगी के लिए;

(ङ) अपने ड्यूटी-स्थल से भिन्न स्थान पर के पुराने मकान या ड्यूटी स्थल से भिन्न स्थान पर के सरकारी सहायता से निर्मित मकान के नवीकरण, विस्तरण या परिवर्तन के लिए,

(च) खंड (इ) के अंतर्गत खरीदे गए साइट में मकान निर्माण के लिए;

(छ) अंशदाता की सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व छः महीने की अवधि में कृषि भूमि या व्यावसायिक आवरण या दोनों को हासिल करने के प्रयोजन के लिए अंशदाता के खाते में निधि में जमा राशि से।

टिप्पणी:—(1) ऐसे अंशदाता जिसने निर्माण व आवास मंत्रालय की योजना के अंतर्गत आवास-निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम प्राप्त किया है, या अन्य सरकारी स्रोतों से ऐसी सहायता पायी है, वह उप खंड (आ) के अधीन उपखंड (क), (ग), (घ), (इ) और (च) के अधीन अंतिम निकासी की मंजूरी का हकदार होगा/होगी, जिनके प्रयोजन वहां निर्दिष्ट है और पूर्वोक्त योजना के अधीन लिए गए ऋण के प्रति संदाय के लिए हैं, बशर्ते कि विनियम 17 के खंड (i) के अनुबन्ध में निर्दिष्ट सीमा में हों।

यदि अंशदाता क. पुराना मकान है या अपने ड्यूटी स्थान से भिन्न स्थान पर सरकारी सहायता से लिए ऋण से निर्मित मकान है तो वह खंड (आ) के उपखंड (क), (ग) और (च) के अधीन अंतिम निकासी की मंजूरी का हकदार होगा/होगी, जो मकान के साइट, खरीदने या और एक मकान निर्माण के लिए होगा, जो उसके ड्यूटी स्थान से भिन्न स्थान पर हो।

(2) खंड (आ) के उपखंड (क), (इ) और (च) के अधीन निकासियां तभी मंजूर की जाएंगी, जब अंशदाता ने, किए जाने वाले या निर्माण विस्तरण या परिवर्तनों के नक्शे स्थानीय नगरपालिका द्वारा विधिवत अनुमोदन कराके प्रस्तुत किया है, जहां वह साइट या मकान स्थित है और केवल ऐसे मामलों में जिनमें नक्शे वस्तुतः अनुमोदित कराए गए हैं।

(3) खंड (आ) के उपखंड (ब) के अधीन निकासी की राशि आवेदन की तारीख को खाते में शेष राशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी, जिसमें, उपखंड (ख) के अधीन निकाली गई पिछली राशि भी शामिल है और उनमें से पिछली निकासी की राशि घटाई गई हो। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत होगा: उस तारीख का शेष धन (+) पिछली निकासियों की राशि जो इस मकान के लिए हो (ऋण) (−) पिछली निकासियों की राशि।

(4) खंड (आ) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन निकासी भी अनुमत्य होगी यदि मकान या मकान साइट पत्नी या पति के नाम हो बशर्ते कि वह अंशदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि धन पाने वाला प्रथम नामांकित हो।

(5) इस विनियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए एक ही निकासी अनुमत्य होगी। लेकिन अलग बच्चों की शादी या शिक्षा अलग अवसरों पर अस्वस्थता या मकान या फ्लैट में पुनः विस्तरण या परिवर्तन जो कि उस क्षेत्र के म्युनिसिपल निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित नये नक्शे में है, जिसमें मकान या फ्लैट स्थित है, एक ही प्रयोजन नहीं माने जाएंगे। खंड (आ) के अधीन उपखंड (क) या (च) के अधीन दूसरी या परवर्ती निकासियां उसी मकान का पूरा करने के लिए टिप्पणी 3 में दी गई सीमा तक अनुमत्य होंगी।

6. यदि विनियम 13 के अधीन उसी प्रयोजन के लिए उसी समय अग्रिम मंजूर हो रहा हो तो इस विनियम के अधीन निकासी मंजूर नहीं की जाएगी।

(2) विनियम 16 के अधीन निधि से निकासी को अनुमत अंशदाता मंजूर करने वाले प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट संक्षिप्त अवधि में, इस बात से संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए राशि निकाली गई हो, उसी के लिए विनियोग की गई है, अन्यथा, इस तरह निकाली गई राशि की पूरी रकम या जिस प्रयोजन से निकाली गई हो उसके लिए विनियोग न की गई उतनी राशि, सुरंत एकमुश्त रूप से प्रतिसंदाय की जाए और ऐसा न करने पर मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा अंशदाता को परिलब्धियों से वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यह वसूली एकमुश्त रूप में या ऐसे मासिक किस्तों में होगी जैसे कि सचिव या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगी।

17. निकासी के लिए शर्तें:—(1) विनियम 16 में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि से अंशदाता के खाते में जमा राशि से किसी एक समय उसके द्वारा निकाली गई राशि सामान्यतया जमा राशि के आधे या उसके छः महीने के वेतन से जो भी लागू हो, अधिक नहीं होगी किन्तु, मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस सीमा से अधिक रकम की अंशदाता के खाते में शेष राशि का 3/4 तक मंजूर दे सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि (i) निकासी का उद्देश्य क्या है, (ii) अंशदाता का स्थान, मान और (iii) निधि में उसके खाते में जमा राशि कितनी है।

बशर्ते कि किसी हालत में विनियम 16 के उप विनियम (आ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकासी की महत्तम राशि, आवास निर्माण प्रयोजनों के लिए निर्माण व आवास मंत्रालय की योजना के नियम 2(क) और 3 (ख) के अधीन समय-समय पर नियत महत्तम सीमा से अधिक नहीं होगी।

आगे बशर्ते कि ऐसे अंशदाता के मामले में जिसने निर्माण व आवास मंत्रालय से मकान के निर्माण के प्रयोजनों के लिए अग्रिमों की मंजूरी की योजना के अधीन अग्रिम लिया हो, या इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से सहायता ली हो तो इस उपविनियम के अधीन निकाली गई राशि, उपरोक्त योजना अधीन राशि या अन्य किसी सरकारी स्रोत से ली गई राशि सहित उपरोक्त योजना के नियम 2 (क) और (ख) में समय-समय पर नियत महत्तम राशि से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी:—विनियम 16 के उप विनियम (आ) के खंड (क) के अधीन अंशदाता को मंजूर निकासी, किस्तों में की जा सकती है, जिनकी संख्या मंजूरी की तारीख से 12 कैलेंडर माहों में मंजूरी की तारीख से चार से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि अंशदाता को दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्मित मकान या फ्लैट की या साइट या मकान या फ्लैट की खरीदी के लिए किस्तों की अदायगी करनी हो तो, जब-जब उससे ऐसी किस्तें अदा करनी होती हैं, तब निकासी की अनुमति दी जा सकती है। विनियम 17 के उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसी हर अदायगी अलग प्रयोजन के लिए अदायगी मानी जाएगी।

(3) यदि मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि निधि में अंशदाता के खाते में जमा राशि अपर्याप्त है और निकासी के बगैर अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो अपनी जीवन बीमा पालिसी में अर्थ प्रबंध के लिए निधि से अंशदाता द्वारा पहले निकाली गई रकम को, इस विनियम में नियत सीमा के प्रयोजन के लिए, अंशदाता के खाते में वास्तविक रूप से जमा राशि में वृद्धि के रूप में गिना जा सकता है। इस तरह अनुमत्य निकासी की रकम निर्धारित होने के बाद

(i) यदि इस तरह निर्धारित रकम, जीवन बीमा पालिसी के अर्थ प्रबंध के लिए पहले से निकाली गई राशि से अधिक हो तो इस तरह निकाली गई राशि को अंतिम निकासी मानी जाए और ऐसे मानी गई राशि एवम् अनुमत्य निकासी का कुल राशि में अंतर, यदि हो, तो, उसे नकद रूप से अदा किया जाए; और

(ii) यदि ऐसे निर्धारित रकम जीवन बीमा पालिसी के अर्थप्रबंध के लिए निधि से पहले ही निकाली गई रकम से अधिक न हो तो, इस तरह निकाली गई राशि को, उपविनियम (i) में निर्दिष्ट सीमा के होते हुए भी अंतिम निकासी माना जाए।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, लेखा अधिकारी पालिसी या पालिसियों को अंशदाता या अंशदाता और संयुक्त बीमाकृत को, जो भी हो, पुनः सौंपेगा और अंशदाता को हस्तांतरित कर देगा जो उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने को मुक्त होगा जिसके लिए वह मुक्त की गई हो।

(2) विनियम 16 के अधीन निधि से निकासी को अनुमत अंशदाता मंजूर करने वाले प्राधिकारी को, उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट संगत अवधि में इस बात से संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए राशि निकाली गई हो, उसी के लिए विनियोग की गई है, अन्यथा इस तरह निकाली गई पूरी राशि या जितनी राशि निकाली गई है, उतनी तुरंत एकमुश्त रूप में निधि में अंशदाता द्वारा प्रतिसंदाय की जाए और ऐसा न करने पर मंजूर करने वाले प्राधिकरी द्वारा अंशदाता की परिलब्धियों से वसूल करने का आदेश दिया जाएगा । यह वसूली एकमुश्त रूप में या ऐसी मासिक किस्तों में होगी जैसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित हुई हों ।

बशर्ते कि इस विनियम के अधीन निकासी के प्रतिसंदाय को लागू करने से पहले अंशदाता को लिखित रूप में और सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा कि क्यों न प्रतिसंदाय लागू किया जाए, और यदि मंजूरकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या उक्त पंद्रह दिन के अंदर स्पष्टीकरण अंशदाता द्वारा प्रस्तुत न किया जाए, तो मंजूरकर्ता प्राधिकरी इस उपविनियम में नियत रीति से प्रतिसंदाय लागू करेगा ।

(3) (क) विनियम 16 के उपविनियम (आ) के उपखंड (क) (ख) या (ग) के अधीन अंशदाता को उसके खाते में जमा राशि निकालने की अनुमति दी गई हो, तो वह ऐसे निकाली गई रकम से निर्मित या खरीदे गए मकान या मकान-साइट का क्रय, बंधक, (अध्यक्ष का बंधक के सिवा) भेंट, विनिमय या अन्य किसी रूप में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी को कब्जा नहीं देगा ।

बशर्ते कि ऐसी अनुमति की आवश्यकता निम्नलिखित मामलों में नहीं होगी :

(i) यदि मकान या मकान-साइट तीन वर्षों की अवधि से अधिक के लिए पट्टे पर दिया गया हो, या :

टिप्पणी:—स्थानांतरणों में केन्द्र सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के अधीन बिना अवरोध के और बोर्ड से उचित अनुमति से नया पद ग्रहण करने के लिए दिए त्यागपत्र भी शामिल होंगे । सेवा में अवरोध के मामलों में सेवा अवरोध अन्य स्थानों पर स्थानांतरण होने पर अनुमत्य कार्यग्रहण अवधि तक ही सीमित होगा ।

स्पष्टीकरण-III:—ऐसे अंशदाता के मामले में जिसका स्थानांतरण, बिना अवरोध के, सरकार के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन निगमित निकाय या समितियों के पंजीकरण अधिनियम 1860, के अधीन पंजीकृत स्वायत्त संगठन में होता है तो, अंशदानों की राशि, ब्याज सहित, उसे अदा नहीं की जाएगी, किन्तु उस निकाय की सम्मति से उस निकाय के अधीन भविष्य निधि के नए खाते में स्थानांतरित की जाएगी । स्थानांतरणों में, सरकार के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन निगमित निकाय या समितियों के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त संगठनों में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से त्यागपत्र के ऐसे मामले शामिल हैं जो अवरोध सहित और बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त हों ।

नया पद ग्रहण करने के लिए लिया गया समय, यदि एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर सरकारी कर्मचारी को अनुमत्य कार्यग्रहण अवधि से ज्यादा न हो तो सेवा में अवरोध नहीं माना जाएगा ।

टिप्पणी:—स्पष्टीकरण III की शर्तों के अनुसार, यदि अंशदाता बिना अवरोध के, सरकार स्वामित्व व नियंत्रणाधीन निगमित निकाय में स्थानांतरित होता है तो अंशदानों और उन पर ब्याज सहित राशि उसे अदा नहीं की जाएगी बल्कि उस निकाय की सम्मति से उस निकाय की भविष्य निधि के उसके नए खाते में अंतरित की जाएगी ।

(ii) वह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के किसी अन्य निगम के पास बंधक रखा जा रहा हो, जो नए मकान के निर्माण या वर्तमान मकान में सुधार या परिवर्तन के लिए ऋण देते हैं ।

(ख) अंशदाता मंजूर-कर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें बताया कि मकान या मकान-साइट जो भी हो, उसके कब्जे में है या बंधक रखा गया है, अन्यथा अंतरित है किराए पर दिया गया है, जैसे पहले बताया गया है और यदि ऐसा कहा गया हो तो मंजूरकर्ता के सम्मुख उसके द्वारा निर्दिष्ट तारीख के पहले मूल क्रय पत्र, बंधक या पट्टे का अधिकार, पेश करेगा और संपत्ति पर उसका अधिकार जिन कागजातों पर आधारित हो उन्हें भी पेश करेगा ।

(ग) यदि, उसकी सेवा निवृत्ति से पहले किसी समय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अंशदाता, मकान या मकान-साइट का कब्जा किसी को दे देता है तो अंशदाता, निधि को, तुरंत ऐसी निकासियों की रकम का प्रतिसंदाय करेगा, और इसमें चूक जाने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी अंशदाता को इस मामले में अभ्यावेदन करने का संगत मौका देने के बाद, अंशदाता की परिलब्धियों से, एकमुश्त या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में, उक्त रकम की वसूली कराएगा ।

टिप्पणी:—अंशदाता ने सरकार से ऋण लेने के बदले में मकान या मकान-साइट सरकार के बंधक रखा है तो उससे अपेक्षित है कि वह निम्नांकित रूप में घोषणा-पत्र पेश करेगा, यथा:—

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणीकृत करता हूं कि भविष्य निधि से अंतिम निकासी लेकर मैंने जो मकान या मकान-साइट हासिल किया था वह मेरे कब्जे में है किन्तु सरकार के पास बंधक है।"

18. अग्रिम का निकासी में परिवर्तन:—विनियम 16 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अंशदाता ने विनियम 13 के अधीन जो अग्रिम लिया हो या भविष्य में लेगा, उसे वह अपनी मर्जी से सचिव को लिखित रूप से अनुरोध करके, अपने खाते में जमा शेष को ध्यान में रखते हुए अंतिम निकासी में परिवर्तित कर सकता है, किंतु इसके लिए विनियम 16 और 17 में निर्दिष्ट शर्तों को उसे पूरा करना होगा ।

19. निधि में संचयित की अंतिम निकासी:—जब अंशदाता सेवा विमुक्त होता है निधि में उसके खाते में जमा राशि उसे देय हो जाएगी।

बशर्तें कि ऐसे अंशदाता जो सेवा से बर्खास्त किया गया हो और बाद में बहाल किया गया हो यदि बोर्ड उससे यह अपेक्षा करता है कि वह इस विनियम के अनुसार उसे भुगतान की गई रकम का प्रतिसंदाय करे तो वह विनियम 20 में निर्दिष्ट रीति से विनियम 12 में बताई दर पर ब्याज सहित उस रकम का प्रतिसंदाय करेगा। इस तरह वसूली गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण I:—ऐसे अंशदाता को, जिसे बाह्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा विस्तरण की समाप्ति के बाद, सेवा विमुक्त माना जाएगा जिसे छुट्टी प्रदान या अस्वीकृत की गई हो ।

स्पष्टीकरण-II:—अनुबंध पर नियुक्त या सेवा से निवृत्त और बाद में अवरत या अनवरत सेवा सहित पुनर्नियुक्त को छोड़कर ऐसे अंशदाता को सेवा विमुक्त नहीं माना जाएगा, जब वह अनवरत सेवा सहित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में (जहां उस पर अन्य भविष्य निधि नियमावली लागू होती है) नए पद पर और अपने पूर्व पद से कोई संबंध रखे बिना स्थानांतरित होता है, तो ऐसे मामले में उसके अंशदान, ब्याज सहित निम्नांकित में जो भी लागू हो, खाते में अंतरित किए जाएं:—

(क) यदि वह केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग में नया पद हो तो, उस निधि के विनियमों के अनुसार उस निधि के उसके खाते में या

(ख) संबंधित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार मान ले तो अंशदान और ब्याजों के अंतरण के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस राज्य या केन्द्र सरकार के नए खाते में ।

ऊपर निर्दिष्ट प्रकार के मामलों में विनियम 12 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज दिया जाएगा, यह समझकर कि बोर्ड का कर्मचारी सेवा छोड़ रहा है । इन विनियमों की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि के शेषों पर संचयित राशि के देय हो जाने के बाद वाले महीने से छटे महीने के अंत तक ब्याज दिया जाएगा, इनमें से जो भी अवधि कम हो । इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में निधि शेषों का अंतरण संबंधित व्यक्तियों के स्थानांतरण के छः महीने के पहले ही यथाशीघ्र किया जाता है ।

20. अंशदाता की सेवा निवृत्ति:—जब अंशदाता (क) सेवा निवृत्ति प्रारंभिक छुट्टी पर गया है या (ख) या छुट्टी पर है या सेवानिवृत्ति की अनुमति उसे दी गई है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि, उसके द्वारा सचिव को इस संबंध में आवेदन करने पर अंशदाता को देय होगी ।

बशर्ते कि यदि अंशदाता ड्यूटी पर लौट आता है, बोर्ड अन्यथा निर्णय नहीं करता, तो निधि में जमा करने के लिए उसे निधि से अदा की गई राशि, विनियम के अनुसार प्रतिसंहाय करेगा और विनियम 12 में उल्लिखित ब्याज देगा । यह प्रतिसंहाय नकद या प्रतिभूतियों में, या भागशः नकद और भागशः प्रतिभूतियों के रूप में या अन्य रूप में, जैसे अग्रिमों के मंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाए, जिसकी मंजूरी के लिए विनियम 13 के खंड (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है ।

21. अंशदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया :—अंशदाता के खाते में जमा राशि के देय होने से पहले या देय होने के बाद अदा होने से पहले, अंशदाता की मृत्यु होने पर:—

(1) जब अंशदाता के पीछे परिवार है—

(क) अंशदाता द्वारा ऐसा नामांकन है, जो विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार या एतद् पूर्व का कोई नियम/विनियम लागू होते है, तो उसके अनुसार, अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों के पक्ष में नामांकन किया गया है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या/उसका भाग जिससे नामांकन संबंधित है, उसके नामांकित/तों को, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में देय होगी,

(ख) अंशदाता के परिवार के सदस्य या सदयों के पक्ष में नामांकन नहीं है या वह नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के एक भाग से संबंधित है तो पूरी राशि या उसका भाग जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जो भी हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जो परिवार का/के सदस्य नहीं है, के पक्ष में नामांकन हैं, कहे जाने पर भी, अंशदाता के परिवार के सदस्यों को समान भागों में देय होगी ।

बशर्ते कि कोई धारा निम्नांकित को देय होगा:

(1) वयस्कता प्राप्त बेटे,

(2) मृत बेटे के बेटे, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त की है,

(3) विवाहित बेटियां, जिनके पति जीवित हैं,

(4) मृत बेटे की विवाहित पत्नियां, जिनके पति जीवित हैं ।

यदि उपखंड (1) (2) (3) और (4) में निर्दिष्ट के अलावा परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो:

(i) आगे बशर्ते कि मृत बेटे का विधवा या विधवाओं और बच्चा या बच्चों को उतने भाग के समान भागों में प्राप्त होगा जितने के अंशदाता के मरने के बाद उस, बेटे को उसके जीवित होने पर, और खंड (1) के प्रथम अनुबंध के प्रावधानों से छूट मिलने पर मिलता ।

(ii) अंशदाता के पीछे कोई परिवार न हो, तो उसके द्वारा विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार या एतद्पूर्व संबंधित विनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन है, तो अंशदाता के खाते में निधि में जमा राशि या उसका भाग जिससे नामांकन संबंधित है, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामांकित को, देय होगा ।

22. निधि में की राशि के अदा करने की रीति:—

(1) जब अंशदाता के खाते में जमा राशि हो जाती देय हो, तो अभिरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि इस संबंध में खंड (3) में दर्शाए गए रूप में लिखित आवेदन मिलने पर, उसे अदा करें ।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कोई राशि अदा करनी हो, वह यदि विकृत है, जिसकी संपदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन, इस संबंध में, प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो उस प्रबंधक को अदा की जाएगी, न कि उस पागल को ।

(3) इस विनियम के अंतर्गत अदायगी के दावे के इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में सचिव को लिखित आवेदन भेजेगा । निकासी की रकमों की अदायगी भारत में ही होगी । ऐसे व्यक्ति जिन्हें रकमें देय हों भारत में अदायगी प्राप्त करने का अपनी ओर से प्रबंध करेंगे ।

टिप्पणी:—अंशदाता के खाते में जमा राशि के विनियम 19, 20 या 21 के अधीन देय हो जाने पर सचिव तुरंत अदायगी का प्राधिकार देगा जो कि अंशदाता के खाते में जमा ऐसी राशि के संबंध में हो, जिनके बारे में कोई विवाद या संदेह नहीं है शेष का यथा तत्पश्चात् समायोजित किया जाए ।

23. सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमित निकायों बोर्ड की सेवा में व्यक्तियों की सेवा का स्थानांतरण होने पर प्रक्रिया:—

निधि के प्रयोजन के लिए बाध्यित बोर्ड का कोई कर्मचारी, सरकार केसे स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय, या समितियों के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त संगठन राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की भविष्य निधि का अंशदाता रहा हो, उसके अंशदानों की राशि और नियोक्ता का अंशदान यदि हो, उस पर ब्याज सहित, निकाय या सरकार की सम्मति से, निधि में अंशदाता के खाते में अंतरित की जाएगी ।

यदि निधि का अंशदाता अंशदायी भविष्य निधि (भारत) के प्रयोजन हेतु दाखिल किया जाता है तो उसके अंशदानों की राशि, उस पर ब्याज सहित, अंशदायी भविष्य निधि (भारत) के उसके खाते में अंतरित की जाएगी ।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थाई रूप में स्थानांतरण बोर्ड के अधीन वैधानिक सेवा में किया जाता है तो राज्य रेजर्व भविष्य निधि या केन्द्र सरकार की अन्य अंशदायी भविष्य निधि या राज्य अंशदायी भविष्य निधि का अंशदाता है, तो उस अन्य सरकार की सम्मति से चाहता है कि

(i) उसके उस अन्य अंशदायी भविष्य निधि में उसके स्थानांतरण की तारीख को जमा अंशदाता और उस पर ब्याज की राशि का अंतरण बोर्ड का भविष्य निधि के खाते में किया जाए,

(ii) सरकार के अंशदानों की उसके खाते में उस अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि और उस पर ब्याज सहित उस सरकार की सम्मति से यदि हो, केन्द्रीय राजस्व (सिविल) में जमा की जाएंगी और वह तदुपरांत स्थाई स्थानांतरण की तारीख पहले की गई सेवा की, संगत पेंशन नियमों के अधीन अनुमत्य पेंशन गणना का/की हकदार होगा/गी ।

24. विशिष्ट मामलों में विनियमों के प्रावधानों में छूट :

यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि इन विनियमों के लागू करने से किसी अंशदाता को अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है या होने की संभावना है, तो बोर्ड इन विनियमों में अन्यथा होने पर भी उसे जैसे न्याय-संगत और सम्मत प्रतीत होता है वैसे, अंशदाता के मामले का निपटारा कर सकता है ।

25. अंशदाता को पूर्ति किया जाने वाला लेखाओं का वार्षिक विवरण :
सचिव, हर वर्ष की समाप्ति के यथाशीघ्र, हर अंशदाता को निधि में उसके खाते का ऐसा विवरण भेजेगा, जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को प्रारंभिक शेष, वर्ष में जमा या निकाली गई राशि, वर्ष की 31 मार्च को जमा ब्याज की राशि और उस तारीख को अन्त-शेष दर्शाया गया हो । सचिव, लेखाओं के विवरण के साथ यह भी पूछेगा कि क्या अंशदाता:

(i) विनियम 6 या तद्पूर्व या विनियम के अधीन किए गए नामांकन में परिवर्तन करने का इच्छुक है,

(ii) जहां अंशदाता ने अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में विनियम 6 के खंड (i) के अधीन नामांकन नहीं किया हो, तो क्या उसने परिवार प्राप्त किया है। अंशदाता देख लें कि वार्षिक विवरण सही है या नहीं, सही न हो तो विवरण की प्राप्ति से तीन महीने के अंदर सचिव को अशुद्धियों की सूचना दें ।

26. लेखाएं और लेखा परीक्षा : (1) बोर्ड के नारियल विकास बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता" नाम के खाते की बहियों में इन विनियमों के अधीन इस निधि द्वारा और निधि में की गई अदायगी का लेखा रखना होगा ।

(2) इन रकमों की जांच और लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवम् महालेखाकार द्वारा की जाएगी, जो ऐसे अंतराल पर होगा जैसे कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के अध्याय III का उपधारा (2) में निर्दिष्ट है ।

(3) निधि के खर्चे जहां तक संभव हो, निधि की आय से उठाए जाएंगे । सभी खर्चों के लिए आय पर्याप्त न हो तो नारियल विकास निधि से उठाए जाएंगे ।

(4) निधि की अभिरक्षा एवम् संवितरण नारियल विकास विनियमों (कार्यकलाप, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और अनुरक्षण) के अनुसार विनियमित होगा, ठीक उसी रीति से जैसे बोर्ड की निधियों का होता है।

27. निधि का समापन:—निधि का समापन किया जाएगा—

(क) यदि केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा बोर्ड को विघटित किया जाता है,

(ख) बोर्ड के संकल्प द्वारा, केन्द्र सरकार से अनुमोदित होने पर ।

28. इन विनियमों में होते हुए भी, केन्द्र सरकार अंशदान की दर में परिवर्तन या सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 में अग्रिमों और निकासियों से संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन अधिसूचित कर सकता है और ऐसे परिवर्तन बोर्ड के कर्मचारियों पर बाध्यकर होंगे ।

[फा. सं. 273/91-प्र.]

एस. एस. नायर, अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड

प्रथम अनुसूची

(विनियम 6(3)

अंशदाता का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी ....

सा. भ. नि. संख्या ....

नामांकन पंजी., पृष्ठ. सं. ....

नामांकन का प्रपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/यों को जो नारियल विकास बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1988 के विनियम 2 में की परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य है,/मेरी मृत्यु हो जाने पर, मेरा खाते में निधि में देय राशि, उस राशि के देय होने पर या देय होने के बाद अदा न की गई हो, प्राप्त करने हेतु नीचे दर्शाए अनुसार नामजद करता/करती हूं ।

नामजद/यों का नाम व पता	अंशदाता से संबंध	नामजद की आयु	हर नामजद को देय भाग	आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नामजदगी अवैध हो जाती है इस कालम में मृत्यु की आकस्मिकता	अंशदाता के पहले नामजद की मृत्यु होने पर जिन्हें नामजद का हक मिलते हैं उन व्यक्तियों का नाम	विनियम 2 के प्रावधान के अनुसार नामजद परिवार का सदस्य नहीं है तो कारण दें।

के रूप में न दर्शाया जाए ।
नामांकन मेरी शादी न्यायिक रूप से अलग रहने, तलाक, नामजद के पागल होने या एकांतर नामजदगी पर अवैध हो जाएगा ।

दिनांक ..... 19 ..... को ..... में

(अंशदाता के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर के दो गवाह

1. .....

2. .....

कार्यालय प्रधान के कार्यालय में प्रयोगार्थ

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा नामांकन : .....

पदनाम : .....

नामांकन प्राप्त होने की तारीख : .....

.....

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर

पदनाम : .....

तारीख : .....

प्रतिलिपि :

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

अंशदाताओं को अनुदेश

(क) अपना नाम लिखें ।

(ख) निधि का नाम यथायोग्य पूर्ण रूप में लिखें ।

(ग) परिवार की परिभाषा नारियल विकास बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम में यों है :—

परिवार का अर्थ है :

(1) पुरुष अंशदाताओं के मामले में पत्नी या पत्नियां माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे और यदि अंशदाता के माता-पिता जीवित न हों तो, दादा-दादी;

बशर्ते कि यदि अंशदाता यह प्रमाणित करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से पृथक हुई थी या वह उसके समुदाय की पारंपरिक विधि के अधीन जीवन-निर्वाह की हकदार न रही हो, तो इन विनियमों से संबंधित मामलों में पत्नी को तत् पश्चात् अंशदाता के परिवार की सदस्या तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि बाद में अंशदाता सचिव को लिखित रूप से यह सूचित नहीं करता कि उसे वैसे माना जाए;

(2) स्त्री अंशदाताओं के मामलों में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें मृत पुत्र की विधवा व बच्चे और यदि अंशदाता के माता-पिता जीवित न हों तो दादा-दादी ।

बशर्ते कि अगर अंशदाता सचिव को लिखित रूप से सूचना देकर इच्छा व्यक्त करे कि उसके परिवार में पति को शामिल न किया जाए, तत् पश्चात् पति को इन विनियमों से संबंधित मामलों में अंशदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि, बाद में, अंशदाता लिखित रूप से सूचना को रद्द नहीं करता;

(घ) कॉलम 4 : यदि एक ही व्यक्ति को नामजद किया जाए तो नामजद के सामने पूर्ण रूप से लिखा जाए । यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाए तो हर नामजद को देय भाग भविष्य निधि की रकम के ऊपर निर्दिष्ट किया जाए ।

(ङ) कॉलम 5 : नामजद की मृत्यु (इस कॉलम में आकस्मिकता के रूप में न दर्शाई जाए)

(च) कॉलम 6 : अपना नाम न दर्शाएं ।

(छ) आखिरी प्रविष्टि के बाद वाली खाली जगह में रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद कोई और नाम न जोड़ा जा सके

भविष्य निधि खाते में बकाया राशि की अंतिम अदायगी के लिए आवेदन पत्र

नारियल विकास बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि खाते में की राशि की अंतिम अदायगी अथवा निकायों/निगमों/अन्य सरकारों को अंतरण हेतु आवेदन का प्रपत्र।

सेवा में

अध्यक्ष,
नारियल विकास बोर्ड
एम.जी. रोड,
कोचीन-682 011

महोदय,

मैं दिनांक.....को पूर्वाह्न/अपराह्न में सेवानिवृत्त होने वाला हूं/हो चुका हूं .....माह की सेवा निवृत्ति प्रारंभिकी अवकाश पर हूं/.....को स्थाई रूप से स्थानांतरित हो गया हूं/.....में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड को अंतिम रूप से त्यागपत्र दे चुका हूं और मेरा त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है। मैंने दिनांक.....को पूर्वाह्न/अपराह्न को नारियल विकास बोर्ड में कार्यग्रहण किया था।

2. मेरे भविष्य निधि खाते की संख्या.....है।

3. मैं अपने कार्यालय/बैंक.....के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी पहचान चिन्ह के विवरण, बाएं हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान (अशिक्षित अंशदाता/सदस्य के मामले में) व नमूना हस्ताक्षर (साक्षर अंशदाता के मामले में) विधिवत रूप से राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो प्रतियों में संलग्न हैं।

भाग 1

(यदि सेवा-निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व अंतिम भुगतान के लिये आवेदन किया जाए तब भरा जाना चाहिए)

4. निवेदन है कि मुझे जारी वार्षिक विवरण के अनुसार (संलग्न) मेरी भविष्य निधि खाते में जमा राशि/आय के द्वारा रखे लेजर में मेरे नाम जमा राशि मुझे अदा करने की व्यवस्था करें।

5. प्रमाणित है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिए थे जिनके पुनर्भुगतान स्वरूप.....रु. की.....किस्तें अभी तक निधि के खाते में भरी जानी बाकी हैं।

मैंने निम्न अग्रिम निकासियां ली थीं।

अस्थाई अग्रिम	अन्तिम निकासियां
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....

6. प्रमाणित करता हूं, कि मेरे भविष्य निधि खाते में बकाया राशि की प्रथम किस्त प्राप्त होने पर बाकी किस्तों के भुगतान के लिए निर्धारित फार्म के भाग II में आवेदन सेवा-निवृत्त होने के बाद करूंगा।

अंशदाता के हस्ताक्षर.....

नाम व पता.....

कार्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाओं को इस कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापित कर दिया गया है और वे सही हैं।

अध्यक्ष

भाग-II

(सेवा निवृत्ति के बाद अंशदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यह उन अंशदाताओं पर भी लागू है जो सेवा निवृत्त/कार्यमुक्ति/इस्तीफे की तारीख के बाद पहली बार अंतिम भुगतान के लिए आवेदन करते हैं)

4. अंतिम भुगतान के लिए मेरे दिनांक.....के आवेदन के संबंध में निवेदन है कि मेरे भविष्य निधि खाते में बकाया राशि का भुगतान मुझे किया जाए।

या

निवेदन है कि मेरे नाम जमा, ब्याज सहित संपूर्ण राशि का नियमानुसार भुगतान मुझे किया जाय।.....को अन्तरित कर दिया जाए।

हस्ताक्षर .....

नाम व पता.....

.....

(कार्यालय प्रधान के उपयोग हेतु)

1. वे सेवा निवृत्त हो गए/गई हैं/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · माह के सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाएंगे/जाएंगी/कार्यमुक्त हो चुके/चुकी हैं/ बर्खास्त/स्थाई रूप से · को स्थानांतरित हो गए/गई हैं/उन्होंने बोर्ड की सेवाओं को इस्तीफा देकर · में नियुक्ति पा ली है और उनका इस्तीफा · (दिनांक) पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

2. उनके वेतन से निधि की कटौती, इस कार्यालय में बिल सं · · · · · · · · · · · · · · · · · · दिनांक · · · · · · · · · · · · · को · · · · · · · · · · · · · · · · रु. (· रुपये मात्र) वाउचर सं · दिनांक · · · · · · · · · · · · · · · को की गई थी। कटौती की राशि · रु./थी और अग्रिम के प्रतिसंदाय की वसूली के रूप में · · · · · · · · · · · · · · · · · रु./थी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि नारियल विकास बोर्ड की सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से 12 माह पूर्व और उसके बाद उन्हें किसी प्रकार का अस्थाई अग्रिम या अंतिम निकासी की मंजूरी नहीं दी गई थी।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि नारियल विकास बोर्ड की सेवा छोड़ने/सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से 12 माह पूर्व या उसके पश्चात उनके भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम/निकासियां स्वीकृत की गई थीं और आहरित हुई थी।

	अस्थाई अग्रिम/निकासी की राशि	दिनांक	वाउचर संख्या
1.			
2.			
3.			

4. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निकाय/निगम में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड की सेवाओं से इस्तीफे पूर्व अनुमति प्राप्ति की/नहीं की थी।

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर

फार्म "सी"

अंशदाता के भविष्य निधि खाते में बकाया राशि के अंतिम अदायगी के लिए अंशदाता के नामांकिती अथवा नामांकन न होने पर किसी अन्य दावेदार द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र।

सेवा में

सचिव,
नारियल विकास बोर्ड
एम.जी. रोड,
कोचीन-682 011

महोदय,

निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी · के सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित राशि की अदायगी की व्यवस्था करें। इस संबंध में आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं :—

1. बोर्ड के कर्मचारी का नाम :
2. जन्म तिथि :
3. धारित पद
4. मृत्यु तिथि
5. मृत्यु का प्रमाण (नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध हों तो)
6. अंशदाता को आवंटित भविष्य निधि खाता संख्या
7. मृत्यु के समय अंशदाता के भविष्य निधि खाते में बकाया राशि (यदि ज्ञात हो)
8. यदि नामांकन दर्ज हो तो अंशदाता की मृत्यु के समय जीवित नामांकितियों का विवरण

नामांकिती का नाम	अंशदाता से संबंध	नामांकिती का हिस्सा
(1)		
(2)		
(3)		

9. यदि नामांकन परिवार के सदस्य के अलावा किसी व्यक्ति के पक्ष में हों, परिवार का विवरण यदि अंशदाता ने बाद में परिवार प्राप्त किया था :

नाम	अंशदाता से संबंध	मृत्यु तिथि पर उम्र
(1)		
(2)		
(3)		

10. यदि नामांकन दर्ज नहीं है, तब अंशदाता की मृत्यु तिथि पर परिवार के जीवित सदस्यों के विवरण/अंशदाता की पुत्री अथवा अंशदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में उसके नाम के आगे यह दर्शाया जाए कि क्या अंशदाता की मृत्यु के समय उनके पति जीवित थे ?

नाम	अंशदाता से संबंध	उम्र (अंशदाता की मृत्यु तिथि पर)
(1)		
(2)		
(3)		

11. यदि राशि नाबालिग बच्चे, जिसकी माँ (अंशदाता की विधवा) हिन्दू नहीं हो तब दावे के साथ हरजाना बांड या संरक्षकता प्रमाण पत्र (जैसी भी स्थिति हो) पेश किया जाना चाहिए ।

12. यदि अंशदाता के पीछे कोई परिवार न हो और कोई नामांकन दर्ज न हो तब उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि राशि देय है (प्रमाणित इच्छा पत्र अथवा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि से समर्थित)

नाम	अंशदाता से संबंध	पता
(1)		
(2)		
(3)		

13. दावेदारों का धर्म :

14. क्या .... कार्यालय/बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना इच्छित है। इस मामले में निम्नलिखित दस्तावेज, कार्यरत राजपत्रित अधिकारी/दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित कराके संलग्न करें :

(1) पहचान के वैयक्तिक चिन्ह :

(2) बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामलों में)

(2) दो प्रतियों में हस्ताक्षर के नमूने (साक्षर दावेदारों के मामले में) :

भवदीय,

(दावेदार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम व पता

स्थान :

दिनांक

(कार्यालय प्रधान के प्रयोग हेतु)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....की भविष्य निधि खाता संख्या.....है।

2. उनकी मृत्यु.....को हुई। नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किया गया है/इस मामले में अपेक्षित नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु के संबंध में कोई शक नहीं है।

3. उनके.....माह के वेतन में से रु.....की अंतिम कटौती कार्यालय के बिल सं..... दिनांक.....वाउचर सं..... दिनांक.....के तहत की गई थी/ रु..... अंशदान हेतु कटौती व रु.....की कटौती अग्रिम के प्रतिसंदाय के रूप में की गई थी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु तिथि के पूर्व के 12 महीनों के दौरान उन्हें उनके भविष्य निधि खाते में किसी प्रकार का अस्थाई अग्रिम/अंतिम निकासी की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु तिथि के पूर्व के 12 महीनों के दौरान उनके भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम/अंतिम निकासी की स्वीकृति दी गई थी :—

	अग्रिम निकासी की राशि	भुगतान की तिथि व स्थान	वाउचर सं.
1.			
2.			

5. प्रमाणित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 10(3)-ई-5(ए) 65 दिनांक 1 नवम्बर 1965 के तहत स्वीकृत अग्रिम की वसूली बाकी नहीं है/निम्नलिखित अग्रिमों की वसूली बाकी है।

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

भविष्य निधि से अग्रिम प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

नारियल विकास बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम लेने हेतु आवेदन :

1. अंशदाता का नाम
2. खाता संख्या
3. पदनाम
4. वेतन
5. नीचे दिए अनुसार, आवेदन की तिथि को अंशदाता के नाम जमा राशि
   (1) वर्ष.....के विवरण के अनुसार जमा शेष
   (2) .....से.....तक जमा मासिक अंशदान
   (3) प्रतिसंदाय
   (4) .....से.....तक की अवधि में निकासियां
   (5) शुद्ध जमा शेष
6. अग्रिम की बकाया राशि व अग्रिम लेने का प्रयोजन
7. आवश्यक अग्रिम की राशि
8. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन
   (ख) विनियम जिसके तहत आवेदन किया गया है
9. अग्रिम की कुल समेकित राशि (मद सं. 6 व 7) तथा इसके प्रतिसंदाय के लिए प्रस्तावित मासिक किस्तों की संख्या
10. अंशदाता की आर्थिक स्थितियों का विवरण जिससे अग्रिम के आवेदन का औचित्य सिद्ध होता है

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अनुभाग/शाखा

भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति का प्रपत्र

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता सं ..... से (नारियल विकास बोर्ड) (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1992 के विनियम ..... के अन्तर्गत ..... पर खर्चों की अदायगी के प्रयोजन के लिए रु० ..... (रुपये .....) की राशि का अग्रिम लेने के लिए अध्यक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. यह अग्रिम ..... रु० की ..... मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा और यह वसूली ..... माह में देय ..... माह के वेतन से प्रारंभ होगी ।

3. ..... माह में स्वीकृत एवं ..... माह में की गई अदायगी की अग्रिम राशि रु ..... में से .....रु० की राशि नीचे दिए गए समेकित अग्रिम की वसूली प्रारंभ होने तक वसूली हेतु बकाया रहेगी/यह राशि एवं अब दिए जा रहे अग्रिम की कुल राशि रु ..... की वसूली रु० .....की ..... मासिक किस्तों में उनके ..... माह में देय ..... माह के वेतन से शुरू होगी ।

4. ..... दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के खाते में जमा शेष का विवरण इस प्रकार है:—

(1) ..... वर्ष के खाता पर्ची अनुसार शेष : रु० .....

(2) ..... से ..... तक रु. ..... : रु. .....

प्रति माह की दर से अनवर्ती जमा एवं प्रतिदेय

(3) मद सं. (1) व (2) का योग : रु. .....

(4) अनुवर्ती निकासियां (यदि कोई हों) : रु. .....

(5) स्वीकृति तिथि को शेष मद सं. (3) —(4) : रु. .....

सेवा में

अध्यक्ष

भविष्य निधि से निकासी के आवेदन का प्रारूप

1. अंशदाता का नाम :
2. खाता संख्या :
3. पदनाम :
4. वेतन :
5. कार्यग्रहण एवं अधिवर्षिता की तिथि :
6. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा शेष का विवरण : :
   (1) ——————————वर्ष संबंधी विवरण के अनसार इति-शेष । :
   (2) ——————माह से ——————माह तक जमा अंशदान । :
   (3) मद सं. (1) में दर्शाए इतिशेष के बाद निधि में प्रतिदेय : :
   (4) ——————से——————तक की अवधि के दौरान निकासियां । :
   (5) आवेदन के दिनांक को जमा का कुल शेष । :
7. अपेक्षित निकासी की राशि :
8. (अ) निकासी का प्रयोजन :
   (आ) विनियम, जिसके अंतर्गत आवेदन किया गया है । :
9. क्या इसी प्रयोजन के लिए पहले कभी निकासी की गई थी ? यदि हां, तो निकाली गई राशि व वर्ष बताएं । :

आवेदक के हस्ताक्षर—; ——————

दिनांक : नाम——————

पदनाम——————

अनुभाग——————

भविष्य निधि से निकासी के लिए स्वीकृति पत्र

1. श्री/श्रीमती/कुमारी——————————(पदनाम भी दें) को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता सं.——————से —————— पर होने वाले खर्च के वहन करने के लिए (नारियल विकास बोर्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम 1993 के विनियम ——————के अंतर्गत) रु.—————————— (रु ——————————) निकालने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. निकासी की राशि श्री/श्रीमती / कुमारी ——————————के 6 माह के वेतन अथवा उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा/अंशदान राशि के आधे (जो भी कम हो) से अधिक नहीं है/उनके खाते में जमा शेष/अंशदान का तीन चौथाई है । उनका मूल वेतन रु. ——————है

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————के सेवा काल पूर्व होने पर सेवा निवृत्त होने में कम से कम 30 वर्ष बाकी हैं/उन्होंने ——————दिनांक को बीस/पच्चीस वर्ष की सरकारी सेवा पूर्व की है ।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती/कुमारी ——————द्वारा भवन निर्माण के लिए सामान्य भविष्य निधि सहित सभी सरकार स्रोतों से प्राप्त राशि, निर्माण एवं आवास मंत्रालय की आवास ऋण योजना के विनियम 2(क) व 3(ख) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित ऋण सीमा से अधिक नहीं है ।

5. ————————(दिनांक) को श्री/श्रीमती/कुमारी ————————के खाते में जमा शेष की स्थिति इस प्रकार है:—

(1) ————वर्ष की खाता पर्ची के अनुसार आदि शेष : रु.

(2) ————से ————तक ————रु. प्र. माह की दर से अनुवर्ती जमा एवं अग्रिम के प्रतिदेय :रु.

(3) मद (1) एवं (2) का योग : रु.

(4) अनुवर्ती निकासियां (यदि हों) :

(5) स्वीकृति तिथि को शेष मद सं. (3)–(4) :

6. श्री/श्रीमती/कुमारी ————————को पत्र स :————के अनुसार ————रु. की आंशिक-अंतिम निकासी स्वीकृत की गई थी।

श्री/श्रीमती/कुमारी————————की खाता पर्ची (उनके बताए अनुसार) के मुताबिक उन्हें ————रु. की आंशिक-अंतिम निकासी————————द्वारा स्वीकृत की गई थी।

सचिव

प्रति अग्रेषित : —

1. श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————को नारियल विकास बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि विनियम) 1992 के विनियम 16(2) के उपबंध की ओर आपका ध्यान आकर्षित है। जिसके अनुसार जिन अंशदाताओं को निधि से धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें चाहिए कि वे स्वीकृति प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करें कि धन-राशि का विनियोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए स्वीकृति दी गई थी। अतः धनराशि प्राप्त करने के ————माह तक इस बात का प्रमाण पत्र पेश करें कि इस राशि का विनियोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए स्वीकृति दी गई थी।

2. वित्त अनुभाग

3. वैयक्तिक फाइल

अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

1. अंशदाता का नाम :

2. पदनाम एवं कार्यालय का नाम जिससे संबंध है :

3. वेतन :

4. सामान्य भविष्य निधि खाता सं. :

5. आवेदन दिन जमा शेष :

6. शेष राशि जिसे अंतिम निकासी में परिवर्तित किया जाना है :

7. (अ) अग्रिम लेने का प्रयोजन :

(आ) अग्रिम प्राप्त करने की तारीख :

(इ) स्वीकृत अग्रिम राशि :

8. अग्रिम स्वीकृत से संबंधित पत्राचार का विवरण :

9. यदि इससे पूर्व, कोई अग्रिम अथवा अंतिम निकासी के रूप में उक्त प्रयोजनार्थ कोई राशि प्राप्त की गई हो तो उसका विवरण :

10. (अ) आवेदन की तिथि को सेवा काल (अवरत अवधि सहित) :

(आ) आवेदन तिथि को सेवा निवृत्ति आयु तक की बची सेवा अवधि .

(इ) सेवा निवृत्ति तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

सं. ————————

दिनांक :

उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन किया गया और उन्हें सही पाया गया।

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

सं. ————————

दिनांक ————

नारियल विकास बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1992 के विनियम 18 के अधीन,————————कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ————————को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता सं.————में

बकाया राशि में से ——————————————प्रयोजन के लिए दिनांक ——————————को मंजूर और बिल सं० ————— द्वारा आहरित ——————————————रुपए की अग्रिम राशि को अंतिम निकासी में परिवर्तित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा दी जाती है।

हस्ताक्षर

सचिव

प्रतिलिपि अग्रेषित :—

1.

2.

3.

——————————————कार्यालय——————————महीने के लिए भविष्यनिधि—खाता संख्या आबंटन हेतु ब्यौरा

क्र. सं.	अंशदाता का नाम	अंशदाता के पिता/पति का नाम	अंशदाता की जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदनाम	परिलब्धियां	अंशदान का माहवार दर (पूर्ण संख्या में)	अंशदान के प्रारंभ होने वाला माह	अभ्युक्तियां	(वित्त विभाग द्वारा भरी जाए) आबंटित खाता संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संख्या————————— दिनांक———————

सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए दो प्रतियों में अग्रेषित किया गया। बोर्ड को उपनियमों के अधीन बोर्ड के जिन कर्मचारियों के नाम विवरण में सम्मिलित हुए है उन्हे सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनना अपेक्षित है। पूर्व विवरणों में नाम सम्मिलित नहीं हैं और वे निधि के सदस्य नहीं है। (अभ्युक्ति कॉलम मे उल्लेखानुसार नामांकन सलग्न है)।

प्रमाणित किया जाता है कि सभी कर्मचारी जिनके नाम ऊपर दर्शाए गए हैं, तत्संबंधित उपनियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान देने के लिए पात्र है।

कार्यालय प्रधान

संख्या————————— दिनांक———————

प्रशासनिक अनुभाग को वापिस किया गया। आबंटित खाता संख्याओं की सूचना अंशदाताओं को देने के साथ सेवापुस्तिकाओं, नामों तथा अन्य कार्यालयगत रिकार्डों मे भी नोट किया जाए। किसी भी अंशदाता के भविष्य निधि से संबंधित सभी पत्राचार मे खाता संख्या का उल्लेख किया जाए। क्रम संख्या————मे दर्शाए नामांकनों की पावती एतद्द्वारा दी जाती है।

सचिव

विवरण भरने संबंधी अनुदेश :

1. विवरण दो प्रतियों में भेजा जाए। विवरणो मे उन स्थायी कर्मचारियों के नाम सम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्होंने पिछले माह कार्यभार ग्रहण किया है और कार्य ग्रहण करते ही सदस्य बनना अपेक्षित है, और बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी जो तीन महीने के पश्चात् तक साल की लगातार सेवा पूरी करते हों या जो अन्य प्रकार से अंशदान के पात्र बनते हों।
2. कॉलम III मे विवाहित महिला अंशदाता के मामले में पिता के स्थान पर पति का नाम दिया जाए और यह स्थिति स्पष्ट की जाए।
3. नारियल विकास बोर्ड के उपनियमों के अंतर्गत बोर्ड का अस्थायी कर्मचारी जो किसी महीने के मध्य में सेवा काल का एक वर्ष पूरा करता है, तो वह अगले माह के वेतन मे से अंशदान करने योग्य माना जाएगा।
4. अंशदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन प्राप्त किये जाने चाहिए और अभ्युक्ति कॉलम में आवश्यक टिप्पणी के साथ यह विवरण सचिव को भेजा जाए।

पास बुक का प्रारूप

पास-बुक का आकार 15 से.मी. × 11 सें मी. हो। इसका आवरण-पृष्ठ मोटा हो और एक प्लास्टिक जैकेट मे आवृत्त हो। आवरण-पृष्ठ तथा अन्य पृष्ठों का प्रारूप निम्नानुसार हो।

(1) आवरण-पृष्ठ

बाहर	अंदर
प्रतीक	अंशदाता का नाम :
नारियल विकास बोर्ड पास-बुक	पदनाम :
सामान्य भविष्य निधि	निवासीय पता :
	नामित व्यक्ति का नाम और अंशदाता से संबंध :

नाम :

खाता संख्या :

(2) पृष्ठ भाग (बाहर)

नोट : —अंशदाता से अनुरोध है कि वह विवरण की शुद्धता को सुनिश्चित कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो पास-बुक में इंदराज के दिनांक से तीन महीने के अंदर वित्त अनुभाग को सूचित करें। यदि अंशदाता चाहे तो उसका खाता बही पन्ना उपलब्ध कराया जाएगा।

2. पास-बुक के खो जाने पर कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रत्येक अतिरिक्त पास-बुक जारी करने के लिए अंशदाता से मूल पास-बुक की दुगुनी कीमत वसूली जाएगी।

(3) प्रथम पृष्ठ

कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तारीख	सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या

(4) पृष्ठ 2 के आगे

वर्ष खाता बही पन्ना	आदि शेष	जमा अंशदान	जमा प्रतिदेय	ब्याज दर	ब्याज राशि	निकासियां	अंत शेष	सचिव के पूर्ण हस्ताक्षर

फार्म—1

दाखिल

कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी/सचिव दिनांक—————से	आहरण निकासी संख्या	खाता बही समाप्त	बारंबारता	नामांकन स्वीकृत कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी/सचिव

गत वर्ष वेतन 31 19——को	अंशदान पूर्ण रुपयों में	निकासियों के प्रतिदेय	योग	वाउचर संख्या सहित निकासियां	मासिक शेष जिस पर ब्याज की गणना की जाती है	टिप्पणियां
अप्रैल						19——से 19——तक
मई						शेष
जून						जमा एवं प्रतिदेय :
जुलाई						19——से 19——तक:
अगस्त						ब्याज :
सितम्बर						योग :
अक्तूबर						निकासियां काटकर
नवम्बर						31 मार्च को :
दिसम्बर						जमा शेष :
जनवरी						
फरवरी						
मार्च (अंतिम)						
मार्च (अगला वर्ष)						

योग——————— ———द्वारा इन्दराज जांच की : जांच की : सचिव

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

वित्त अधिकारी

फार्म- II

वर्ष 19------से 19------ के लिए सामान्य भविष्य निधि खाते का ब्राड शीट

खाता संख्या	वर्ष की शुरुआत जमा शेष	------महीने में प्राप्तियां					
		अप्रैल			मार्च		
		अंशदान के रूप में जमा	प्रतिदेय के रूप में जमा	कुल जमा	अंशदान के रूप में जमा	प्रतिदेय के रूप में जमा	कुल जमा

महीने में निकासियां

वर्ष का ब्याज	प्राप्तियों का योग और आदिशेष	अप्रैल	मई	. . . . .	मार्च	इतिशेष	----का योग और इतिशेष	अभ्युक्तियां

फार्म–III

सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर

खाता संख्या	खाता बही पृष्ठ संख्या	अंशदाता का नाम व पदनाम	नामांकन प्राप्ति की तारीख	सचिव द्वारा नामांकन प्राप्ति का अनुप्रमाणन	खाता बंद होने की तारीख व कारण	अभ्युक्तियां

फार्म 4 (लेखा पर्ची)

नारियल विकास बोर्ड, कोच्चिन-682011

लेखा वर्ष---------

ब्याज की दर . . . . प्रतिशत

खाता संख्या	अंशदाता का नाम व पदनाम	आदि शेष	*वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के लिए ब्याज	वर्ष के दौरान निकासियां	शेष

*अप्रैल से मार्च महीने के दौरान की गई वसूलियों सहित।

नोट–1 अंशदाता से अनुरोध है कि वह निधि के उपनियमों के अधीन नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उल्लेख करें।

नोट–2 यदि अंशदाता ने अपना परिवार न होने के कारण किसी भी सदस्य को नामित न किया है परन्तु तत्पश्चात् परिवार शामिल किया है तो ऐसे मामलों में संबंधित तथ्य सचिव को तत्काल सूचित करें।

नोट–3 अंशदाता से अनुरोध है कि वे विवरण की शुद्धता को सुनिश्चित कर लें और विसंगति पाये जाने पर विवरण प्राप्त होने के------------ महीनों के अंदर सचिव को सूचित करें।

हस्ताक्षर. . . .

पदनाम. . . . . .

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

COCONUT DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

Kochi, the 21st September, 1992

S.O. 2496.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Coconut Development Board (General Provident Fund) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of this publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In the regulations :—

(a) "Act" means the Coconut Development Board Act, 1979.

(b) "Board" means the Coconut Development Board constituted under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(c) the expressions 'Chairman' and 'Secretary' wherever they occur, shall mean 'Chairman' and 'Secretary' respectively of the Board;

(d) "emoluments" means pay including dearness pay, if any, special pay, personal pay and leave salary or subsistence grant, if admissible, and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service but does not include dearness allowance or any other allowances;

(e) "Family" means :—

(i) in the case of male subscriber the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand-parent;

Provided that if a subscriber proves that his wife had been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent;

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancel such notice in writing."

NOTE. (1) "Children" means legitimate children.

(2) An adopted child shall be considered to be a child when the Chairman or, if any doubt arises in the mind of the Chairman, the Board, is satisfied that under the personal law of the subscriber, adoption is legally recognised as conferring the status of a natural child.

(f) 'Fund' means the General Provident Fund constituted and established by Regulation 3.

(g) 'Leave' means any kind of leave sanctioned for the staff of the Board under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(h) 'Employee of the Board' means a salaried officer or employee of the Board other than a person in the service of the Central Government or a State Government whose services have been lent or transferred to the Board.

(i) 'Year' means the financial year.

(j) "Schedule" means a schedule to these rules.

(k) Words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, and the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) or the Fundamental Rules, or the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as the case may be.

3. Constitution of the fund.—(1) There shall be constituted a General Provident Fund for the employees of the Board.

(2) The fund shall consist of :—

(a) subscriptions to the Board's Provident Fund together with interest thereon due as on 31st March, 1991 made by the employees of the Board;

(b) subscriptions which are credited to the fund in accordance with these rules;

(c) all sums paid into the fund under these regulations shall be credited to the "The Coconut Development Board General Provident Fund";

(d) such other contributions to the Fund as the Board may from time to time determine with the approval of the Central Government;

(e) the income of the Fund from loans, deposits and investments;

(f) the sums of which payments have not been taken within five years after they become payable shall be credited into the Fund at the end of the year.

4. Management of the fund.—The Fund shall vest in the Board and be managed by the Executive Committee or by the Chairman to such extent as may be specified by the Executive Committee on behalf of the Board.

5. Conditions of eligibilty.—The persons eligible to subscribe to the Fund are :—

(i) the employees of the Board who were in service after their transfer from the Directorate of Coconut Development on the establishment of the Board with effect from 12-1-1981 and continuing in such service on the date of notification of this regulation and had completed one year's continuous service on 12-1-1981 and or subsequently; and

(ii) every employee of the Board (other than a re-employed pensioner) who joined service of the Board on or after 12-1-1981 and has continued in such service thereafter and who has put in not less than one year's continuous service, other than an officer of any Government whose services have been placed at the disposal of the Board and in respect of whom the Board is required to pay leave, pension or provident fund contribution to that Government.

(2) A temporary employee who completes one year's continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

(3) Every employee of the Board to whom these regulations apply, shall be a subscriber to the Fund.

6. Nominations :—(1) A subscriber shall at the time of joining the Fund, send to the Secretary a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable, has not been paid:

Provided that where a subscriber is a minor, he or she shall be required to make the nomination only on attaining the age of majority ;

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any provident fund to which he was subscribing before joining the fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If the subscriber nominates more than one person under sub-clause (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in such forms as may be specified in the First Schedule.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Secretary. The subscriber shall, alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this Regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination.

(a) in respect of any specified nominee that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of sub-clause (b) of clause (5) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Secretary a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provision of this regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent it is valid, take effect on the date on which it is received by the Secretary.

Explanation.—In this Regulation, unless the content otherwise requires, "person" or "persons" shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not.

7. Subscribers Account.—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :— (a) his subscription; (b) interest, as specified in clause (2) of Regulation 12, (c) advances and withdrawals from the fund.

8. Condiitons of subscription.—(1) subscriber shall subscribe monthly to the fund except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber may at his option, not subscribe during any period of leave, other than leave on average pay or earned leave.

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one or more instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscriptions payable in respect of the such period. (2) The subscriber shall intimate his option not to subscribe during the leave in the following manner :—

(a) if he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription his first bill drawn after proceeding on leave;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Secretary/D.D.O. before he proceeds on ltave, failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

Note.—The option of a subscriber once intimated under this sub-clause shall be final.

(3) A subscriber who has withdrawn the amount standing to his credit in the fund under regulation 20 shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Notwithstanding anything in sub-clause (1) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the such month, he intimates to the Secretary/D.D.O. in writing his option to subscribe for the such month.

(5) A subscriber who is entitled for the productivity linked bonus may, if he so desires, deposit the whole or part of the amount admissible under the scheme in his Provident Fund account.

9. Rates of subscription.—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber, subject to the following conditions, namely :—

(a) it shall be expressed in whole rupees ;

(b) it may be any sum, so expressed, which shall not be less than six per cent of his salary and not more than his total salary.

(2) For the purpose of clause (1), the salary shall be (a) in the case of subscriber who was in Board's service on 31st March of the preceding year, the salary to which he was entitled on that date :

Provided that—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his salary shall be the salary to which he is entitled on the first day after his return to duty ;

(ii) If the subscriber was on deputation out of India on such date or was on leave on the such date and continues to be on leave, his emoluments shall be the salary to which he would have been entitled had he been on duty in India ;

(b) In the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year the salary to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year by writing to the Secretary or in the following manner, as the case may be—

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month ;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to susbcribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction, which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty ;

(c) If he was entered Board's service for the first time during the year, by the deduction made in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the fund ;

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month ;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him to the Board on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be—

(a) reduced once at any time during the course of the year ;

(b) enhanced twice during the course of the year ;

or

(c) reduced and enhanced as aforesaid ;

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-clause (1).

Provided further that if a subscriber is on leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave if any, other than those referred to above.

10. Transfer to foreign service or deputation out of India.—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the provisions of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Realisation of subscription.—(1) The Board shall have powers to deduct from the emoluments of any subscriber, the subscription due from him and the principal and interest on the advance ,if any, made to him from the fund.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Secretary :

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Secretary by such body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in Regulation 8, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate specified in regulation 12, forthwith be paid by the subscriber to the fund or in default be ordered by the Secretary to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13.

12. Interest.—(1) The Board shall pay to the credit of a subscriber interest at such rates as may be determined for each year by the Central Government for the General Provident Fund (Central Services) according to the method of calculation prescribed from time to time by them.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner :—

(i) On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sum withdrawn during the current year—interest for twelve months;

(ii) On sums withdrawn during the current year—Interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal ;

(iii) On all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year—interest from the date of deposit upto the end of the current year ;

(iv) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole Rupee (fifty paise counting as the next higher rupee) :

Provided that when the amount standing on the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) In this regulation where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month, the date of deposit shall in the case of a recovery of his subscriptions be deemed to be the first day of the succeeding month in which it is recovered and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the succeeding month of receipt, if it is received by the Secretary before the fifth day of the succeeding month, but if it is received on or after the fifth day of next month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the fund, the interest on such subscription shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to clause (2) of regulation 11, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Secretary before fifteenth day of that month.

(4) In addition to any amount to be paid under regulations 19 20 or 21, interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount becomes payable, whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid :

Provided that the Secretary has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a cheque in payment to that person interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date as intimated or the date of posting the cheque as the case may be.

(5) The interest on amounts, which under clause (2) of regulation 11, clause(s) of regulation 14, regulation 19 or 20 are replaced to the credit of the subscriber in the fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under clause (1) and so for as may be in the manner described in this regulation.

13. Advances from the Fund.—(1) The Chairman may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding an amount equal to three months pay or half the amount standing to his credit in the fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

(a) To pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him ;

(b) to meet the cost of higher education, including travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical professional or vocational course beyond the High School stage ; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years ;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the susbcribers status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies of himself or of his children or any person actually dependent on him; provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber.

Provided further that the condition of actual dependence shall not apply in the case of an advance required to meet further expenses of the parent of a subscriber.

(d) To meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source ;

Provided that the advance under this clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with him official duty or against the Board in respect of any condition of service or penalty imposed on him :

(e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engaged a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part ;

(f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot or flat by a State Housing Board or House Building Cooperative Society ;

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in clause 1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(3) When an advance is sanctioned under clause (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and instalments for recovery shall be fixed with refernece to the consolidated amount.

Note.—(1) For the purpose of this clause, pay includes pay, dearness pay where admissible.

(2) A subscriber shall be permitted to take an advance once in very six months under item (b) of clause (1) o fregulation 13.

14. Recovery of Advances.—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty four. In special cases where the amount of advance exceeds three month's pay of the subscriber under clause (2) of regulation 13, the sanctioning authority shall fix such number of instalments to be more than twenty four but in no case more than thirty six. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in regulation 11, for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave other than leave on average pay or earned leave of not less than one month or 30 days duration, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority the recovery of the advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him or her and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund or in default, be ordered by the Secretary to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under clause (2) of regulation 13.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made to the subscribers account in the fund.

15. Wrongful use of advance.—Notwithstanding anything in these regulations, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the fund under Regulation 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of money, he shall intimate to the subscriber the reasons for his doubt and require him/her to explain in writing within fifteen days of the receipt of such intimation whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in a lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he/she be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments from his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note.—The term 'emoluments' in this regulation does not include subsistence grant.

16. Withdrawals from the Fund.—(1) Subject to the conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the Chairman for special reasons under clause (2) of regulation 13, at any time ;

(A) After the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his or her retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his or her credit in the fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases namely :—

(i) for education outside India for academic technical professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage ;

(b) Meeting the expenditure in connection with betrothal or marriage of the subscriber of his or her sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him/her ;

(c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his/her family or any person actually dependent on him/her ;

(B) After the completion of ten years of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his/her retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his or her credit in the fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) building or acquire a suitable house or ready-built flat for his/her residence including the cost of the site ;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence;

(c) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

(d) purchasing a house-site for building a house thereon for his/her residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other othan the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty ;

(f) constructing a house a site purchased under clause (e) ;

(C) Within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

Note.—(1) A subscriber who has availed himself/herself of an advance under the Scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) and (f) o fclause (B) for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-clause (1) of rgulation 17.

If a subscriber has an ancestral house or built house at a place other than the place of his or her duty with the assistance of loan taken from the Government he or she shall be eligible for the grant of a find withdrawal under sub-clause (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his or her duty.

(2) Withdrawal under sub-clause (a) (d), (e) or (f) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got approved.

(3) The amount of withdrawal sanctioned under these sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on the date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (b), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : 3/4th of the balance as on the date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question minus the amount of previous withdrawal(s).

(4) Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

(5) Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

(6) A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund under regulation 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it has been withdrawn and if he or she fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been utilised for purpose for which it has been drawn, shall forthwith be repaid in one lumpsum and in default of such payment it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his or her emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Secretary or Chairman.

17. Conditions for withdrawal.—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this liimt up to 3/4th of the balance at his credit in the fund having due regard to,—(i) the object for which the withdrawal is being made ; (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of sub-regulation of regulation 16 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and 3(b) of the Scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advances for house building purposes.

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and (b) of the aforesaid Scheme.

Note.—(1)A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-regulation (1) of regulation 16, may be drawn in instalments, the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

(2) In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-regulation (1) of regulation 17.

(5) In case the sanctioning authority is satisfied that the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund is insufficient and he is unable to meet his requirements otherwise than by withdrawal, the amount already withdrawn by the subscriber from the fund to finance his life insurance policy may be taken into account as an addition to the actual amount standing to his credit in the fund for the purpose of the limit laid down in the sub-regulation. After the amount of withdrawal admissible has been so determined :

(i) if the amount so determined exceeds the amount already withdrawn from the fund to finance life insurance policy, the amount so withdrawn may be treated as final withdrawal and the difference, if any, between the amount so treated and the total amount of withdrawal admissible may be paid in cash ; and

(ii) if the amount so determined does not exceed the amount already withdrawn from the fund to finance life insdrance policy, the amount so withdrawn may, irrespective of the limit specified in sub-regulation (1), be treated as final withdrawal.

For the above purpose, the Account Officer shall reassign the policy or policies to the subscriber or to the subscriber and the joint assured, as the case may be, and make it over to the subscriber who will then be free to utilise the same for the purpose for which it has been released.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under regulation 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, whole of the sum so withdrawn or so much withdrawn shall forthwith be repaid in one lump-sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the President.

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the intimation why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation.

3. (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 16 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortagage (other than mortgage to the President), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the President :

Provided that such permission shall not be necessary for :

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years or ;

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the President, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note.—A subscriber who has taken loan from Government in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Government shall be required to furnish the declaration to the following effect namely :—

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Government".

18. Conversion of an advance into withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 13 for any of the purpose specified in clause (1) or regulation 16 may convert, at his or her discretion by written request addressed to the Secretary the balance outstanding against it into a final withdrawal on his or her satisfying the conditions specified in regulation 16 and 17.

19. Final withdrawal of accumulation in the Fund.—When a subscriber quits the service, the amount standing to his or her credit in the fund shall be become payable to him or her :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him or her from the fund in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in the manner specified in the provisc to regulation 20. The amount so repaid shall be credited his or her account in the fund.

Explanation-I.—A subscriber who is granted or refused leave shall deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation-II.—A subscriber, other than the one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he or she is transferred without any break in service to a new post under a State Government or another department of the Central Government (in which he or she is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his or her former post. In such case, his or her subscriptions together with interest thereon shall be transferred—

(a) to his or her account in the other fund in accordance with the regulations of that fund, if the new post is in another department of the Central Government, or

(b) to a new account under a State Government if or Central Government concerned if the new post is under a State or Central Government, if that Government so consents, by general or special order, to such transfer of subscriptions and intervals.

Note.—Transfers shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another Department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Board. In cases where

there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchment followed by immediate employment.

Explanation-III.—When a subscriber is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions, together with interest thereon shall not be paid to him or her but shall be transferred with the consent of that body, to his or her new Provident Fund account under that body.

Transfers shall includes cases of registration from service in order to take up appointment under a body corporate, owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government employee on transfer from one post to another.

Note.—In terms of explanation-III, when a subscriber is transferred without any break to the service under a body corporate owned or controlled by Government, the amount of subscriptions together with interest thereon is not paid to him or her but is transferred with the consent of that body to his or her new provident fund account under that body.

Interest in the type of cases specified above shall be allowed in accordance with the provisions of clause (4) of regulation 12 as if the Board's employee leaves the service.

In terms of these regulations interest on Provident Fund balances is allowed upto the end of the sixth month from the month in which the accumulated amount became payable whichever of these periods be less. It is therefore, to be ensured that transfer of Provident Fund balance in such cases should be effected as early as possible within a period of six months of the transfer of the persons concerned.

20. Retirement of subscriber.—When a subscriber, (a) has proceeded on leave preparatory to retirement or (b) while on leave or has been permitted to retire or been declared by a competent authority to be unfit for further service, the amount standing to his or her credit in the fund shall, upon application made by him or her in that behalf to the Secretary, become payable to the subscriber ;

Provided that the subscriber, if he or she returns to duty, shall, except where the Board decides otherwise, repay to the fund for credit in the account, the amount paid to him/her from the fund in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in cash or securities or partly in cash and partly in securities or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under clause (2) of regulation 13.

21. Procedure on death of a subscriber.—On the death of a subscriber before the amount standing to his or her credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made—

(i) When the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Regulation 6 or of the corresponding rule/regulation heretofore in force in favour of a member or members of his/her family subsists, the amount standing to his/her credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his/her nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his/her credit in the fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his/her family, become payable to the members of his/her family in equal shares :

provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained majority ;

(2) sons of a deceased son who have attained majority ;

(3) married daughters whose husbands are alive ;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive ;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2) (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of first proviso.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him or her in accordance with the provisions of regulation 6 or of the corresponding regulation heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his or her credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his or her nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

22. Manner of payment of amount in the fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the fund becomes payable, it shall be the duty of the Chairman to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in clause (3).

(2) If the person to whom, under these regulations, any amount is to be paid, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment shall be made to such manager and not to the lunatic.

(3) Any person who desires to claim payment under this regulation shall send a written application in that behalf to the Secretary. Payment of amounts withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India.

Note.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under regulations 19, 20 or 21, the Secretary shall authorise prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there no dispute or doubt; the balance being adjusted as soon after, as may be.

23. Procedure on transfer to Board's service of a person from the services under a body corporate, owned or controlled by Government.—If a Board's servant admitted to the benefit of the fund was previously a subscriber, to any Provident Fund of a body corporate, owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, or of the State Government or Central Government, the amount of his or her subscriptions and the employer's contribution, if any, together with interest thereon shall be transferred to his or her credit in the fund with the consent of that body or Government. If a subscriber to the fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund (India), the amount of his or her subscriptions, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his or her account in the Contributory Provident Fund (India).

If a Government employee who is a subscriber to the State Railways Provident Fund or any other Contributory Provident Fund of the Central Government or a State Contributory Provident Fund is permanently transferred to pensionable service under the board, he or she may at his or her option and with the consent of the other government ; (i) transfer the amount of subscriptions with interest thereon standing at his/her credit in such contributory provident fund on the date of his/her transfer, be transferred to his/her credit in the fund, (ii) the amount of government contributions, with interest thereon standing to his or her credit in such Contributory Provident Fund shall, with the consent of the other Government, if any, be credited to the Central Revenues (Civil) and (iii) he or she shall thereupon be entitled to count towards pension, services rendered prior to the date of permanent transfer to the extent permissible under the relevant Pension Rules.

24. Relaxation of the provisions of the Regulations in individual cases.—When the Board is satisfied that the operation of any of these regulation causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to them to be just and equitable.

25. Annual statement of accounts to be supplied to subscriber.—As soon as possible after the close of each year, Secretary shall send to each subscriber a statement of his account in the fund showing the opening balance as on 1st April of the year the total amount credited or debited during the year. The total amount of interest credited on 31st March of the year and the closing balance on that date. The Secretary shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber :—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6 or under the corresponding regulation heretofore in force ;

(b) has acquired a family in case where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his or her family under the proviso to clause (1) of regulation 6.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and error should be brought to the notice of the Secretary within three months from the date of receipt of the statement.

27. Accounts and Audit.—(1) All sums paid into and from the fund under these Regulations shall be accounted for in the books of the Board in an account named "The Coconut Development Board General Profident Fund Account".

(2) Such sums shall be examined and audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him under sub-section (2) of Chapter III of the Coconut Development Board Act, 1979.

(3) All expenses of the fund shall be met from the income of the fund as far as possible. If the income is not sufficient to meet all expenses, the deficit shall be met from Coconut Development Fund.

(4) The custody and disbursal of the fund shall be regulated in accordance with the Coconut Development (Transaction of Business conditions of service of Employees and Maintenance) regulations, exactly in the same manner as the funds of the Board.

27. Winding up of the Fund.—(1) The fund shall be wound up—

(a) if the Board were to be dissolved by a notification by the Central Government ;

(b) by a resolution of the Board approved by the Central Government.

28. Notwithstanding these regulations the Central Government may notify any change in the rate of subscription or modify the procedures relating to advances and withdrawals in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and such changes shall be binding on the employees of the Board.

[F. No. 273/91-Admn.]

S. S. NAIR, Chairman

Coconut Development Board

FIRST SCHEDULE

(REGULATION 6(3)

Subscriber's name Shri/Smt./Kumari———————

G.P.F. Account No. ———————

Nomination Register

Folio No. ———————

FORM OF NOMINATION

I, Shri/Smt./Kumari ———————————————hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are members/non-member(s) of my family as defined in Regulation 2 of the Coconut Development Board General Provident Fund Regulations 1988 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid. ——— Death should not be mentioned under this column as a	Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Regulation indicate the reasons

		contingency
		The nomination shall become invalid on my marriage Legal Separation Divorce Insanity of nominee or alternate nominee.

Dated this————of———— 19————at————

(Signature of the subscriber)

TWO WITNESSES TO SIGNATURE

1. ————————

2. ————————

Space for use by the Head of Office

Nomination by Shri/Smt./Kum. ————————

Designation :————————

Date of receipt of Nomination————————

————————

Signature of Head of Office

Designation ————————

Date : ————————

Copy to :

Shri/Smt./Kumari. ————————

INSTRUCTIONS FOR THE SUBSCRIBER

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the fund may be completed suitably.

(c) Definition of terms 'family' as given in the Coconut Development Board General Provident Fund Regulations, 1988 is reproduced below :
Family means—

(i) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a parental grand-parent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded.

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a parental grand parent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member to the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

(d) Col. 4 If only one person is nominate the words' in full (should be written against the nominee. If more than one person is nominated the SHARE PAYABLE to each NOMINEE over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5 Death of nominee (should not be mentioned as contingency in this column)

(f) Col. 6 Do not mentioned your name.

(g) Draw line across the blank space below the last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

Application forms for final payment of balances in the Provident Fund

Form of application for Final Payment/Transfer to Bodies/Corporate Other Governments of balances in the Coconut Development Board General Provident Fund Account.

To

The Chairman,
Coconut Development Board,
M.G. Road,
Cochin-682011

Sir,

I am due to retire/have retired/have proceeded on leave preparatory to retirement for——————months/have discharged/dismissed/have been permanently transferred to———————————————/have resigned finally from the services of the Board to take up appointment with——————————————————and my resignation has been accepted, with effect from ——————————forenoon/afternoon. I joined service with the Coconut Development Board ————forenoon/afternoon.

2. My Provident fund Account No. is————

3. I desire to receive payment through my office/bank———————————————— Particulars of my personal marks of identification, left hand thumb and finger impressions (in the case of illiterate subscribers) and specimen Sign. (in the case of literate subscribers) in duplicate duly attested by a gazetted officer of the Government are enclosed.

Part 1

(To be filled in when the application for final payment submitted on year prior to retirement)

4. I request that the amount of Rs.——————standing to the credit in my General Provident Fund Account as indicated in the Accounts statement issued to me for the year——————(enclosed)/as appearing in my ledger account maintained by you, may please be arranged to be paid to me ——————————

5. Certified that I had taken the following advances in respect of which——————————instalments of Rs.——————are yet to be repaid to the fund account. I had taken the following advances/withdrawals :—

Temporary advances	Final Withdrawal
1.	1. ....
2.	2. ....
3.	3. ....
4.	4. ....

6. Certified that after the payment of first instalment of my Provident Fund balance, I will apply for the payment of the subsequent instalments in part II of the form immediately on retirement.

Signature of subscriber

Name and address :

Certificate by the Head of the Office

Certified that the above information has been verified from the records being maintained in this office and is correct.

Chairman

Part II

(To be submitted by the subscriber after his retirement. This part is also applicable in the case of subscribers who apply for final payment for the first time after the date of superannuation, discharge, resignation, etc.)

4. In continuation of my application for final payment dated........................I request that the balance in my Provident Fund may please be paid to me.

OR

I request that the entire amount at my credit with interest due under the rules may be paid to me/transferred, to——————————————————

Signature: ——————————
Name & Address :——————————

(For use by Head of Office)

1. He/She has finally retired/will proceed on leave preparatory to retirement for............months/ has been discharged/dismissed/has been permanently transferred to................................./ has resigned finally from Board's service to take up appointment with.............................. and his/her resignation has been accepted with effect from.............................forenoon/afternoon. He joined service with....................on forenoon/afternoon.

2. The last fund deduction was made from his/her pay in this office Bill No........dated........ for Rs..................(Rupees.. only) voucher No.......... of...................19....the amount of deductions being Rs...........................and recovery on account of refund of advance Rs....................

3. Certified that he/she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/her Provident Fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his/her quitting service under Coconut Development Board/proceeding on leave preporatory to retirement or thereafter.

OR

Certified that the following temporary advance/final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her Provident Fund account during the 12 months immediately preceding the date of his/her quitting service under Coconut Development Board/proceeding on leave preporatory to retirement or thereafter.

	Amount of Advance/ withdrawal	Date	Voucher Number
1.	——————	——————	——————
2.	——————	——————	——————
3.	——————	——————	——————

4. Certified that he/she has/has not resigned from the Government service with prior permission of the Board to take up an appointment in a Department of the Central Government or under a State Government or under a body corporate owned or controlled by the State.

Signature of Head of Office

FORM—C

Form of Application for Final Payment of Balances in the Provident Fund Account of a subscriber to be used by the nominees or any other claimants where no nomination subsists.

To

The Secretary
Coconut Development Board
M.G. Road
Cochin-682 011

Sir,

It is requested that arrangements may kindly be made for the payment of the accumulation in the General Provident Fund Account of Shri/Smt./Kumari.. The necessary particulars required in this connection are given below :—

1. Name of the Board's servant
2. Date of birth
3. Post held
4. Date of death
5. Proof of death in the form of a death certificate issued by the municipal authorities, etc., if available
6. Provident Fund Account No. allotted to the subscriber
7. Amount of Provident Fund money standing to the credit of the subscriber at the time of his death, if known
8. Details of nominees alive on the date of death of the subscriber if a nomination subsists

	Name of nominee	Relationship with the subscriber	Share of the nominee
	————	————	————
(i)	————	————	————
(ii)	————	————	————
(iii)	————	————	————

9. In case the nomination is in favour of a person other than a member of the family, the details of the family, if the subscriber subsequently acquired a family :

	Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death
	————	————	————
(i)	————	————	————
(ii)	————	————	————
(iii)	————	————	————

10. In case no nomination subsists, the details of the surviving members of the family on the date of death of the subscriber. In case of a daughter or a daughter

of deceased son of the subscriber, married before the death of the subscriber, it should be stated against her name whether her husband was alive on the date of death of the subscriber.

	Name	Relationship with the subscriber	Age (on the date of the subscriber)
(i)			
(ii)			
(iii)			

11. In the case of amount due to minor child whose mother (widow of the subscriber) is not a Hindu, the claim should be supported by Indemnity Bond or Guardianship certificate, as the case may be.

12. If the subscriber has left no family and no nomination subsists, the names of the persons to whom the Provident Fund money is payable (to be supported by the letter of probate or succession certificate etc.)

	Name	Relationship with the subscriber	Address
(i)			
(ii)			
(iii)			

13. Religion of the claimant (s)

14. The payment is desired through the office/..... .....Bank. In this connection the following documents duly attested by a Gazetted Officer in service/Magistrate are attached.

(i) Personal marks of identification

(ii) Left/Right hand thumb and finger impressions (in the case of illiterate claimants).

(iii) Specimen signatures in duplicate (in the case of literate claimants).

Yours faithfully,

Station :——————

(Signature of claimant)

(Full name and address)

Date : ——————

(FOR USE OF HEAD OF OFFICE)

The Provident Fund Account No.———— of Shri/Smt./Kumari.———— is ————

2. He/She died on ————. A death certificate issued by the Municipal authorities has been produced/is not required in this case as there is no doubt about his/her death.

3. The last fund deduction was made from his/her pay for the month of ————drawn in this office Bill No.———— dated ———— for Rs. ———— (Rupees————) voucher No. ———— dated ————the amount of deduction being Rs. ———— and recovery, on account refund of advance of Rs————

4. Certified that he/she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/her Provident Fund account during thel12 months immediately preceding the date of his/her death.

OR

Certified that the following tempora ly advance/final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her Provident fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his/her death.

	Amount of advance/withdrawals	Date and place of encashment	Voucher number
1			
2.			

5. Certified that no advance/following advance sanctioned in terms of the Ministry of Finance OM No.[10(3)-E V(A)/65 dated the 1st November, 1965 is due for recovery.

(Signature of the Head of Office)

Proforma for application for advance from Provident Fund

Application for advance from Coconut Development Board General Provident Fund.

1. Name of the subscriber
2. Account Number
3. Designation
4. Pay
5. Balance at credit of the Subscriber, on the date of application as below:
   (i) Closing balance as per statement for the year ————
   (ii) Credit from ———— to ———— on account of monthly subscription
   (iii) Refunds
   (iv) Withdrawals during the period from ———— to ————
   (v) Net balance at credit
6. Amount of advance outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken then.
7. Amount of advance required
8. (a) Purpose for which the advance is required
   (b) Regulation under which the request is covered

9. Amount of the consolidated advance (items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid.

10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance.

Signature of applicant

Name ————————

Designation ————————

Section/Branch ————————

Dated :

Proforma for sanction of advance from Provident Fund

ORDER

Sanction of the Chairman is hereby accorded under Regulation ———— of Coconut Development Board General Provident Fund for grant of an advance of Rs. ———— (Rupees ————————) to Shri/Smt./Kum. ———————————— from his/her G.P.F. Account No. ———— to enable him/her to defray the expenses on ————————

2. The advance will be recovered in ———— monthly instalments of Rs.———— each, commencing from the salary for the month of ———— payable in ————.

3. A sum of Rs. ———— (Rupees ————————) out of advance of Rs.———— sanctioned in ———— and paid to him/her in ———— will be outstanding till the commencement of the recovery of the consolidated amount as specified below. this amount together with the advance now sanctioned aggregating to Rs. ———— will be recovered in ———— montly instalments of Rs. ———— each commencing from the salary for the month of ———— payable in ————.

4. The balance at the credit of Shri/Smt./Kum. ———————————— as on ———— is detailed below:—

(i)	Balance as per account slip for the year	Rs. ————
(ii)	Subsequent deposits and refunds of advance at the rate of Rs. ———— p.m. from ———— to ————	Rs. ———— Rs. ————
(iii)	Total of col. (i) and (ii)	Rs. ————
(iv)	Subsequent withdrawals, if any	Rs. ————
(v)	Balance as on date of sanction col. (iii)—(iv)	Rs. ————

Chairman

Proforma for application for withdrawal from Provident Fund

1. Name of subscriber
2. Account No.
3. Designation
4. Pay
5. Date of joining service & date of superannuation
6. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:
   (i) closing balance as per statement for the year ————
   (ii) Credit from ———— to ———— on account of monthly subscription
   (iii) Refunds made to the fund after the closing balance vide (i) above
   (iv) withdrawal during the period from ———— to ————

(v) Net balance at credit on date of application :

7. Amount of withdrawal required :

8. (a) Purpose for which the withdrawal is required :
   (b) Regulation under which the request is covered :

9. Whether any withdrawal was taken for the same purpose. If so, indicate the amount and the year ·

Signature of Applicant
Name ——————————
Designation ——————————
Dated : Section ——————————

Proforma for sanctioning withdrawals from Provident Fund

Sanction of the Chairman is hereby accorded under ———————— Regulation of the Coconut Development Board (General Provident Fund) Regulations 1991 to the drawal by Shri/Smt./Km. —————————— (here enter the designation) of a sum of Rs. ———— (Rupees ——————————) from his/her GPF Account No. —————— to enable him/her to meet expenditure ——————————.

2. The amount of withdrawal does not exceed six month pay of Shri/Smt./Km. ——————————or half the amount at his/her credit/subscription in the General Provident Fund account, whichever is less/three-fourth of the amount at the credit/subscription of Shri/Smt./Kum. ——————————in the General Provident Fund Account. His/her basic pay is Rs. ————.

3. It is certified that Shri/Smt./Km. —————— is within 10 years of his/her retirement on superannuation/has completed twenty/twentyfive years of his/her Government service on ————.

4. It is also certified that the total amount drawn, including the drawal from GPF, from all Government sources by Shri/Smt./Km. ——————————for house building purposes does not exceed the maximum limit prescribed from time to time under Regulation 2(a) and 3(b) of the scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house building purposes.

5. The balance at the credit of Shri/Smt./Km. —————————— as on ———— is detailed below :—

(i) Balance as per account slip for the year ———— Rs.

(ii) Subsequent deposit and refunds of advance at the rate of Rs. ———— from ———— to ———— Rs.

(iii) Total of col. (i) and (ii) Rs.

(iv) Subsequent withdrawals, if any Rs.

(v) Balance as on date of sanction col. (iii)-(iv) Rs.

6. Shri/Smt./Kum. ——————————was last sanctioned a part-final withdrawal for an amount of Rs. ———— vide ———— after the account statement for the year of Shri/Smt./Kum. —————— is understood (as stated by him/her) to have been last sanctioned a part-final withdrawal of Rs. ———— by ——————.

Secretary

Copy forwarded to :—

1. Shri/Smt./Kum. ——————————
his/her attention is drawn to the provision of the Regulation 16(2) of the Coconut Development Board General Provident Fund Regulations, 1992 according to which a subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund should satisfy the sanctioning authority that the money has been utilised for the purpose for which it was drawn. A certificate to the effect that the withdrawal sanctioned above has been utilised for the purpose for which it has been sanctioned may therefore, please be furnished within ———— months of the drawal of the money.

2. Finance Section
3. Personal File

Form of application for conversion of an advance into a final withdrawal

1. Name of the subscriber
2. Designation and office to which attached
3. Pay
4. GPF Account number
5. Balance at credit on the date of application
6. Balance outstanding to be converted into final withdrawal
7. (a) Purpose for which advance taken
   (b) Date of payment of the advance
   (c) Amount of advance sanctioned
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above. If so, particulars thereof
10. (a) Total service, including broken periods, if any, on date of this application
    (b) Period of service, left on the date of application for attaining the age of superannuation
    (c) Date of superannuation

Place :

Date: Signature of Applicant

No. ———— Dated ————

The above particulars have been verified and found to be correct.

Signature and designation of recommending authority.

Sanction of the competent authority

No. ———— Date :————

Sancton is hereby accorded under Regulation18 of the Coconut Development Board General Provident Fund) Regulation, 1992 for the conversion into final withdrawal of an account of Rs.————(Rupees ———— ————)being the outstanding balance out of the GPF advance of Rs.———— ———— sanctioned on ———— and drawn vide Bill No. ————of ———— for the (purpose)————to Shri/Smt./Kum.————of the office of the ————(GPF Account No. ————)

Signature

Secretary

Copy forwarded to :—

(i)

(ii)

(iii)

Statement of particulars for allotment of Provident Fund Account Numbers for the month of ..... office of the

Sl. No.	Name of subscriber	Name of subscriber's father/husband	Date of birth of the the subscriber	Date of joining service	Designation
1	2	3	4	5	6

Emoluments	Monthly rate of subscription (in whole rupees)	Month from which subscription to commence	Remarks	(To be filled in by the Finance Section Account No. allotted.
4	8	9	10	11

No. ———— Dated ————

Forwarded in duplicate to the Secretary for necessary action. The Board's servants whose names are included in the statement are required to join the GP Fund under the ————.—By-laws of the Board. Their names have not been included in the previous statements and they are not already member of the Fund.

(Nominations are enclosed as mentioned in the remarks column)

Certified that all the employee whose names are shown above are eligible to subscribe to the Provident Fund in accordance with the relevant By-laws.

Head of Office

Dated ————

No.

Returned to Administration Section. Account Nos. allotted may be intimated to the subscribers and also noted in the Service Book, nominations and other official records. In all correspondence with Provident Fund of any subscriber, the account number should be quoted. Receipt of nominations at SL. Nos. ———— is hereby acknowledged.

Secretary

Head of Office

Instructions for filling the statement.

The statement should be sent in duplicate. It should include permanent Board's servants joined service in the previous month and are required to join the Fund compulsorily on entry into Board's service and temporary Board's service and temporary Board's servants who will complete one years continuous service or otherwise become eligible to subscribe to the Provident Fund, three months hence.

2. In column 3, husband's name (instead of father's name) may be given in respect of married female subscribers indicating the position.

3. Column 9: Under the Coconut Development Board General Provident Regulations, a temporary Board's servant who completes one year's continuous service during the middle of a month shall commence subscribing to the GP Fund from his/her salary for the month following that in which he/she completes one year's service.

4. Nominations should be obtained in the prescribed form from the subscriber and forwarded to the Secretry alongwith this statement making a suitable note in the remarks column.

FORMAT OF THE PASS BOOK

The Pass Book may be of size 15 cms × 11 cms. It may, have a thick cover and be provided with a plastic jacket. The formats of the cover page and other pages may be as follows:

(i) Front cover page

Outside	Inside
Emblem	Name of subscriber
Coconut Development Board Pass Book	Designation
General Provident Fund	Residential Address : Name of nominee and his/her relations with the subscriber.

Name :

Account No,

(ii) Back page (outside)

Note: The subscriber is requested to satisfy himself as to the correctness of the statement and to bring errors, if any, to the notice of the Finance Section within three months from the date of entries in the Pass Book. The Ledger Folio of the subscriber, if so required by him, will be available for inspection.

2. If this pass book is lost, the matter should be reported to the office. An amount equivalent to twice the cost of the pass book will be charged from the subscriber for issue of each extra pass book.

(iii) First page

Name of office	Date of joining	GPF Account Number

(iv) Page 2 onwards

Year	Ledger Folio	Opening balance	Deposits		Interest		With-drawals	Closing balance	Full signature of secretary
			Sub-scription	Refund	Rate	Amount			

FORM I

LEDGER

Withdrawals

Admitted

JAO

FO/Secretary

Nomination accepted

From Number Discontinued Times JAO/FO/Secretary

Pay on 31st March of the preceding year 19.....	Subscription in whole Rupees	Refunds of withdrawn	Total	Withdrawal with voucher number	Monthly balance on which interest is calculated	Remarks
April						Balance from
May						19——19——
June						
July						Deposits and
August						refunds :
September						Interest from
October						19——19—— :
November						Total
December						
						Deduct with-
January						drawals :
February						
March (final)						Balance on
March (Sy.)						31st March :

Total :———— Posted by———— Checked : JAO/FO Examined : Secretary

FORM II

Broad sheet of the General Provident Fund Account for the year 19—— 19——

No. of Account	Balance at the commencement of the year	Receipt for the Month of					
		April			March		
		Credit on account of subscription	Credit on account of Refund	Total credits	Credit on account of subscription	Credit on account of refund	Total credits

		Withdrawals in the month of						
Interest for the year	Total of receipts and opening balance	April	May	March	Closing balance	Total of and closing balance	Remarks

FORM III

GENERAL INDEX REGISTER

Account Number	Ledger Folio	Name and designation of the subs-criber	Nomination when received	Attestation of receipt of nomination by Secretary	Date of and reason for closure of accounts	Remarks

FORM IV (Account Slip)

Coconut Development Board, Cochin 682 011

Year of Account .....

Rate of interest.....per cent

Account Number	Name of subscriber and designation	Opening balance	*Deposits during the year	Interest for the year	Withdrawals during the year	Balance

*includes recoveries made during the months of April to March.

Note : 1. The subscriber is requested to state whether he desires to make any alteration in any nomination made under the By-Law of the Fund.

Note : 2. In cases where the subsciber has made no nomination in favour of a member of his family owing to his having no family at the time, but acquired a family thereafter, the fact should be reported to the Secretary forthwith.

Note : 3. The subscriber is requested to satisfy himself as to the correctness of the statement and to bring to the notice of the Secretary within.....month(s) from the date of its receipt, discrepancies, if any.

Signature.....

Designation .....

इलेक्ट्रोनिकी विभाग

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1992

का. आ. 2497.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा इलेक्ट्रोनिकी विभाग के जयपुर स्थित इलेक्ट्रोनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[संख्या 7(1)/92-हि. अ.)]

शांतिलाल सरणोत निदेशक,

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 31st August, 1992

S.O. 2497.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Jaipur office of the Electronics Test and Development Centre, Jaipur, a subordinate office of the Department of Electronics, whereof more than 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. 7(1)/92-H.S.]

S. L. SARNOT, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1992

का. आ. 2498.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 खण्ड (क) के अनुसरण में और भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 3 सितम्बर, 90 को अधिसूचना संख्या का. आ. 2499 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम 1 में दिए गए प्राधिकारी को कथित अधिनियम के अधीन अनुसूची के कालम 2 में विनिष्टि के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी और पता	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)
श्री कपिल माथुर वरिष्ठ पाइपलाइन अभियंता इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड सलाया— मथुरा स्टेशन, पोस्ट आफिस सैन्दरा जिला पाली राजस्थान-306102	राजस्थान और उत्तर प्रदेश

[सं. आर. 25027/1/90-ओ. आर. 1]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st September, 1992

S. O. 2498.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India-Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2499, dated the 3rd September, 1990 the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Authority and Address	Areas
Shri Kapil Mathur, Senior Pipeline Engineer, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Mathura Pipelines, Sendra Pump Station, Post Office Sendra, District Pali, Rajasthan-306102.	Rajasthan and Uttar Pradesh

[No. R-25027/1/90-ORI]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1992

का.आ. 2499.—केन्द्र सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 की 50) जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2305 तारीख 7-9-91 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की :

और राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 सितम्बर, 1991 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्र सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन किया जाए—

अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्र सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए सभी विलंगमों से रहित, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा :—

अनुसूची

तहसील : जोधपुर जिला : जोधपुर राज्य : राजस्थान

गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सालावास	708	0	29	88
	710	0	41	04
	713	0	80	64

तहसील : रायपुर जिला : पाली राज्य : राजस्थान

गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्गमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मानपुरा	575	0	09	50
	575	0	09	50
	576	0	16	20
	577	0	03	30
	578	0	00	90
	586	0	00	90
	589	10	10	54
	590/766	0	04	72

तहसील : देसूरी जिला : पाली राज्य : राजस्थान

गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रानीकलां	1025	0	60	30
	1026	0	13	68
	1036	0	61	74
	1046	0	56	88

[सं० आर० 31015/9/89-ओ आर I पार्ट ए]

फुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th September, 1992

S.O. 2499.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2305, dated the 7th September, 1991 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum;

And, whereas, copies of the Gazette Notification had been made available to the public on 26th September, 1991;

And, whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of thepowers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Jodhpur District : Jodhpur State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hectare	Are	Square meters
1	2	3	4	5
Salawas	708	0	29	88
	710	0	41	04
	713	0	80	64

Tehsil : Raipur District : Pali State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5
Manpura	575	0	09	50
	576	0	16	20
	577	0	03	30
	578	0	00	90
	586	0	00	90
	589	0	10	54
	590/766	0	04	72

Tehsil : Desuri District : Pali State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5
Rani Kalan	1025	0	60	30
	1026	0	13	68
	1036	0	61	74
	1046	0	56	88

[No. R-31015/9/89-ORI Pt. A]
KULDIP SINGH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1992

का. आ. 2500.—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्यांक 4070 से 4083 में प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 2665 से 2668 दिनांक 1 अक्टूबर 1991 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पेट्रोलियम के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की;

और आगे केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विलंगमों से रहित इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

और केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रण की कुछ गलतियां हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।

का. आ. 2665 पृष्ठ संख्या 4071 पर क्षेत्रफल की पेमानी कॉलम में "एकड़" के स्थान पर "एअर" पढ़ें

पर गांव के नाम के कालम में "लनां" के स्थान पर "लूनां" पढ़ें।

पर शीकारपुर गांव के क्षेत्रफल के वर्ग मीटर कालम में खसरा संख्या 457 के सामने "96" के स्थान पर "86" पढ़ें।"

पर सालावास गांव के खसरा संख्या कालम में खसरा संख्या "725" के स्थान पर "725/4 पढ़ें।

का. आ. 2666 पृष्ठ संख्या 4073 पर क्षेत्रफल की पेमानी कालम में "एकड़" के स्थान पर "एअर" पढ़ें।

पर गांव के नाम कालम में "मण्डल" के स्थान पर "माडल" पढ़ें।

माण्डल गांव के खसरा संख्या कालम में पृष्ठ भाग द्वितीय पंक्ति–11 पर "31" के स्थान पर "3" पढ़ें।

का. आ. 2666 पृष्ठ संख्या 4074 पर गांव के नाम के कालम में "करीबा (समाप्त)" के स्थान पर "कारव (जारी) पढ़ें।

पर कीरवा गांव के क्षेत्रफल के वर्ग मीटर कालम में खसरा संख्या 106 के सामने "11 वा" के स्थान पर "11" पढ़ें।

पर दयालपुरा गांव के क्षेत्रफल के वर्गमीटर कालम में पृष्ठ भाग द्वितीय पंक्ति 34 पर खसरा संख्या 181 के सामने "3" के स्थान पर पर "34" पढ़ें।

पर रूपावास गांव के खसरा संख्या कालम में पंक्ति–51 पर "18" के स्थान पर "418" पढ़ें।

का. आ. 2666 पृष्ठ 4075 पर गांव के नाम के कालम में "ना (समाप्त) के स्थान पर "रूपावास (जारी "पढ़ें"

का. आ. 2667 पृष्ठ संख्या 4078 पर क्षेत्रफल की पेमानी कालम में "एकड़" के स्थान पर "एअर" पढ़ें।

पर कोटवालिया गांव के क्षेत्रफल के वर्ग मीटर कालम में खसरा संख्या 595 के सामने "48" के स्थान पर "40" एवं खसरा संख्या 398 के सामने "60" के के स्थान पर "69" पढ़ें।

का. आ. 2667. पृष्ठ संख्या 4079 पर खीमेल गांव के क्षेत्र के एअर कालम में खसरा संख्या 382 के सामने "00" के स्थान पर "23" पढ़ें।

का. आ. 2668, पृष्ठ संख्या 4082 पर तहसील के कालम में "देहनूरी" के स्थान पर "देसूरी" पढ़ें।

पर क्षेत्रफल की पेमानी कालम में "एकड़" के स्थान पर "एअर" पढ़ें।

पर पादरली गांव के क्षेत्रफल के हेक्टर कालम में खसरा संख्या 73 के सामने "07" के स्थान पर "0" पढ़ें।

पर पुनाडिया गांव के क्षेत्रफल के हेक्टर कालम में खसरा संख्या 468 के सामने "14" के स्थान पर "0" एवं खसरा संख्या 103 के सामने "29" के स्थान पर "0" पढ़ें।

[संख्या आर-31015/9/89 ओ॰आर॰आई॰ पार्ट-ए]
कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th September, 1992

CORRIGENDUM

S.O. 2500.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2665 to 2668 dated the 4th October, 1991, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at pages 4070 to 4083, issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum, should be acquired;

And, whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows :—

In S.O. 2666, at page 4076, in Village Keerwa against survey No. 5, in column 4, for '82' read '02', at page 4077, in Village Chatelao against survey No. 179, in column 4, for '48' read '08', in S.O. 2667, at page 4080, in Village Dantiwara against survey No. 236, in column 5, for '24' read '34', in S.O. 2668, at page 4083, in Village Punadiya against survey No. 240, in column 5, for '17' read '16'.

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government directs that the right of user in the lands shall instead, of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances, in the Indian Oil Corporation Limited.

[No. R-31015/9/89-ORI-Pt.-A]
KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2501.—यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1330 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एस. एक्स जी. मे जी. एन. ए. क्यू. जी. जी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वागरा

गांव	ब्लाक सं.	हे.	आर.	मे.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वासेटा	189/ए/बी	0	13	2
	191	0	10	53
	192	0	08	97
	190	0	09	62
	188	0	00	86
	194	0	05	14
	195	0	04	94
	196	0	03	38
	199	0	01	08
	182	0	00	94
	200	0	09	36
	201	0	04	55
	232	0	04	42
	233	0	05	20
	234	0	00	98
	230	0	00	72
	229	0	06	76
	228	0	07	28
	227	0	04	42
	226	0	04	68
	225	0	06	24
	254	0	25	74
	219	0	00	68
	255	0	07	54
	कार्ट ट्रैक	0	01	17
	303	0	03	12
	304	0	08	97
	302	0	02	86
	309	0	12	98
	298/ए	0	00	62
	298/बी	0	08	06
	297	0	15	34
	296	0	00	43
	कार्ट ट्रैक	0	01	56

[सं. आ०-12016/1/92/ओ० एन० जी० डी०-IV]
एम० माटिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2501.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1330 dated 30-5-1992 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government ;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from GNXG to GNAO GGS.

State : Gujrat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Vanceta	189/A/B	0	13	26
	191	0	10	53
	192	0	08	97
	190	0	09	62
	188	0	00	86
	194	0	05	14
	195	0	04	94
	196	0	03	38
	199	0	01	08
	182	0	00	94
	200	0	09	36
	201	0	04	55
	232	0	04	42
	233	0	05	20
	234	0	00	98
	230	0	00	72
	229	0	06	76
	228	0	07	28
	227	0	04	42
	226	0	04	68
	225	0	06	24
	254	0	25	75
	219	0	00	68
	255	0	07	54
	Cart track	0	01	17
	303	0	03	12
	304	0	08	97
	302	0	02	86
	309	0	12	98
	298/A	0	00	62
	298/B	0	08	06
	297	0	15	34
	296	0	00	42
	Cart track	0	01	56

[No. O-12016/1/92-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

अधिसूचना

का. आ. 2502—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं 1331 तारीख 30/5/92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. जी. सी. से जी. जी. एस. –II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला भरुच तालुका वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हार.	से.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पालडी	356	0	04	16
	375	0	08	93
	374	0	08	19
	289/ए/बी	0	05	07
	363/ए/बी	0	19	33
	288	0	37	40
	286	0	06	63
	277/बी	0	08	58
	276/बी	0	13	24
	267	0	16	34
	265/ए/बी	0	09	36
	268	0	03	38
	269	0	28	56
	273	0	08	64
	274	0	02	12

[सं. 12016/2/92-ओ. एन. जी. डी.-IV]

एम. मार्टिन डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2502.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1331 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from GNGC to GGS II.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hct.	Are	Cont
Paldi	356	0	04	16
	375	0	08	93
	374	0	08	19
	289/A/B	0	05	07
	363/A/B	0	19	33
	288	0	37	40
	286	0	06	63
	277/B	0	08	58
	276/B	0	13	24
	267	0	16	34
	265/A/B	0	09	36
	268	0	03	38
	269	0	28	56
	273	0	08	64
	274	0	02	12

[No. O-12016/2/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 92

का.आ. 2503:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1332 तारीख 30-5-1992 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

पी.डी.ए. से पादरा ई.पी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : पादरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
तेजपुरा	343	0	07	02
	344	0	05	16
	346	0	04	68
	कार्टट्रेक	0	00	78
	348	0	22	75
	355	0	04	50
	354	0	07	20
	367	0	12	48
	कार्टट्रेक	0	00	52
	412	0	08	06
	414	0	08	02
	411	0	00	43
	421	0	01	98
	415	0	06	47
	419	0	10	92
	420	0	01	82
	कार्टट्रेक	0	00	52
	483	0	08	06
	484	0	07	80
	कार्ट ट्रेक	0	00	78
	491	0	03	90
	490	0	06	37
	486	0	07	15
	487	0	10	92

[सं. 12016/3/92/ओ.एन.जी.डी.-IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2503.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1332 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from PDAI to PADRA EPS

State : Gujarat District Vadodar Taluka : Padra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
Tajpura	343	0	07	02
	344	0	05	16
	346	0	04	68

1	2	3	4	5
Tajpura	Cart track	0	00	78
	348	0	22	75
	355	0	04	50
	354	0	07	20
	367	0	12	48
	Cart track	0	00	52
	412	0	08	06
	414	0	08	02
	411	0	00	43
	421	0	01	98
	415	0	06	47
	419	0	10	92
	420	0	01	82
	Cart track	0	00	52
	483	0	08	06
	484	0	07	80
	Cart track	0	00	78
	491	0	03	90
	490	0	06	37
	496	0	07	15
	487	0	10	92
	190	0	13	26
	191	0	18	46
	188/ए	0	01	04
	188/बी	0	00	52
	181/ए	0	00	28
	183/बी	0	17	68

[No. O-12016/3/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2504.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1333 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डी जे डी डी से डहेज जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	मे.
कोलीयाद	1/ए/बी/सी/पी	0	50	96
	231	0	14	43
	174	0	24	96
	180	0	05	20
	189/बी	0	06	24
	190	0	13	26
	191	0	18	46
	188/ए	0	01	04
	188/बी	0	00	52
	181/ए	0	00	28
	183/बी	0	17	68

[सं. 12016/4/92/ओ. एन. जी. डी-IV)]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2504.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1333 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report received to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DJDD to DAHEJ GGS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No	Hect.	Are	Centiare
Koliyad	1/A/B/C/P	0	50	96
	231	0	14	43
	174	0	24	96
	180	0	05	20
	189/B	0	06	24
	190	0	13	26
	191	0	18	46
	188/A	0	01	40
	188/B	0	00	52
	181/A	0	00	28
	183/B	0	17	68

[No. O-12016/4/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2505:– यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1334 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की उपधारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी जी ए एन से परखाजन जीजीएस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	सेन्टी.
वाव	18	0	10	14
	5	0	09	75
	6	0	02	21

[सं. O-12016/5/92/ओ. एन.जी.डी-IV)]
एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2505.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1334 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from DJAN to PAKHAJAN GGS

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Varga

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
Wav	18	0	10	14
	5	0	09	75
	6	0	02	21

[No. O-12016/5/92-ONG.D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2506 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1335 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

केआईईए सी से ई एल ए ऐ से एल डब्ल्यू एम बी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : हँसोट

गांव	ब्लाक नं.	हे	आर.	सें.
1	2	3	4	5
बलोटा	1043	0	44	85
	1113	0	00	18
	कार्टट्रैक	0	00	78
	1141	0	00	18
	1114	0	04	03
	1115	0	13	13
	1116	0	03	06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1117	0	17	42
	1125	0	00	64
	1122	0	04	56
	1123	0	03	28
	1121	0	04	78
	1120	0	00	38
	1014	0	07	80
	849	0	09	08
	850	0	09	14
	851	0	09	10
	1007	0	01	23
	कार्ट ट्रैक	0	00	76
	852	0	09	88
	853	0	05	46
	854	0	00	12
	843	0	08	00
	863	0	02	21
	866	0	10	06
	864	0	07	67
	865	0	08	58
	871	0	03	12
	873	0	00	32
	872	0	04	88
	790	0	39	78
	781	0	00	08
	788	0	02	99
	787	0	11	05
	786	0	05	85

[सं. O-12016/6/92 /आ. एन. जी. डी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2506.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1335 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from KIAC to ELAA to SWMB

State : Gujarat District : Bharuch Taluka - Hansot

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balota	1043	0	44	85
	1113	0	00	18
	Cart track	0	00	78
	1141	0	00	18
	1114	0	04	03
	1115	0	13	13
	1116	0	08	06
	1117	0	17	42
	1125	0	00	64
	1122	0	04	56
	1123	0	03	28
	1121	0	04	78
	1120	0	00	38
	1014	0	07	80
	849	0	09	08
	850	0	09	14
	851	0	09	10
	1107	0	00	28
	Cart track	0	01	76
	852	0	09	88
	853	0	05	46
	854	0	00	12
	843	0	08	00
	863	0	02	21
	866	0	10	06
	864	0	07	67
	865	0	08	58
	871	0	03	12
	873	0	00	32
	872	0	04	88
	790	0	39	78
	781	0	00	08
	788	0	02	99
	787	0	11	05
	786	0	05	85

[No. O-12016/5/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2507 :- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1336 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, अब केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के.आई.ऐ.सी. से ई.एल.ए.ए. से एस. डब्ल्यू. एम. बी. तक बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : हासोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टी
ईलाव	575	0	04	16
	572	0	18	72
	569	0	28	86

[सं. ओ-12016/7/92/ओ.एन.जी.डी. IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2507.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1336 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KIAC to ELLA to SWMB

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

1	2	3	4	5
Ilao	575	0	04	16
	572	0	18	72
	569	0	28	86

[No. O-12016/7/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1992

का.आ. 2508:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1337 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के.आई.ए.सी. से ई.एल.ए.ए. से एस. डब्ल्यू. एम. बी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : हासोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
अंकलचा	463	0	57	85
	446	0	02	86
	447	0	24	03

[सं० ओ-12016/8/92/ओ एन जी डी-IV]

एम मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2508.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1337 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KIAC to ELLA to SWMB.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

1	2	3	4	5
Ankalva	463	0	57	85
	446	0	02	86
	447	0	24	05

[No. O-12016/8/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2509—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के (1) अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं 1338 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पखाजन जी.जी.एस. से 'टी' बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य – गुजरात जिला भरूच तालुका – वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	से.
1	2	3	4	5
केशवान	951	0	26	72
	957	0	10	72
	956	0	09	88
	960	0	10	92
	961	0	18	72
	976	0	18	46
	962/ए/बी	0	25	74
	963	0	01	98
	913	0	06	86

[सं. ओ-12016/9/92 – ओ. एन. जी. डी. -IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2509.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1338 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan GGS to 'T' Point.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra,

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
Keshwan	951	0	26	72
	957	0	10	72
	956	0	09	88
	960	0	10	92
	961	0	18	72
	976	0	18	46
	962/A/B	0	25	74
	963	0	01	98
	913	0	06	86

[No. O-12016 9/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2510—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1339 तारीख 30-5-92 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन सी ए से जी जी एस – II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य – गुजरात जिला – भरूच तालुका – वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	से.
1	2	3	4	5
पाल्डी	83	0	05	20
	85	0	06	24
	90	0	10	90
	94	0	21	32
	97	0	02	08
	98	0	00	92
	100	0	00	28
	102	0	28	96
	103	0	13	91
	117	0	13	65
	109	0	22	36
	107	0	01	92
	108	0	18	36
	161/ए/बी	0	20	93
	318	0	18	46
	184	0	13	78
	185	0	12	74
	182	0	07	93
	181	0	05	20
	180	0	19	24
	206	0	11	05
	267	0	10	14
	208	0	11	70
	213	0	14	30
	224	0	13	04
	214	0	03	64
	221	0	05	85
	216/ए/बी	0	02	73
	220	0	01	80
	217/ए/बी	0	39	26
	255	0	07	28
	256	0	18	85
	257	0	02	01
	274	0	15	08

[सं. O–12016/10/92/ओ एन जी डी–IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2510.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1339 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNCA to GGS. II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Varga

Village	Block No.	Hect	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Paldi	83	0	05	20
	85	0	06	24
	90	0	10	90
	94	0	21	32
	97	0	02	08
	98	0	00	92
	100	0	00	28
	102	0	28	96
	103	0	13	91
	117	0	13	65
	109	0	22	36

1	2	3	4	5
	107	0	01	92
	108	0	18	36
	161/A/B	0	20	93
	318	0	18	46
	184	0	13	78
	185	0	12	74
	182	0	07	93
	181	0	05	20
	180	0	19	24
	206	0	11	05
	207	0	10	14
	208	0	11	70
	213	0	14	30
	224	0	13	04
	214	0	03	64
	221	0	05	85
	216/A/B	0	02	73
	220	0	01	80
	217/A/B	0	39	26
	255	0	07	28
	256	p	18	85
	257	0	02	01
	274	0	15	08

[No. O-12016/10/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2511—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1340 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया हैं।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी जे डी डी से दहेज जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य – गुजरात जिला–भरूच तालुका–वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
वेगणी	139	0	07	54

[सं. O – 12016/11/92 – ओ एन जी डी — IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2511.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1340 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exericse of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from DJDD to DAHEJ GGS

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Varga.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
Vangani	139	0	07	54

[No. O-12016/11/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2512—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1341 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पखाजन जी.जी.एस. से 'टी' बिन्दु तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य–गुजरात जिला–भरूच तालुका–वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गोलादरा	83	0	07	28
	86	0	00	56
	85	0	18	72
	89	0	14	95
	91	0	09	88
	कार्ट ट्रेक	0	03	38
	111	0	09	36
	109	0	14	56
	108	0	06	50
	107	0	11	70
	118	0	12	74
	119/ए/बी	0	15	08
	120	0	03	64
	123 ए	0	00	30
	122	0	05	46
	121	0	12	48
	कार्ट ट्रेक	0	02	60
	242	0	01	10
	241	0	18	85
	कार्ट ट्रेक	0	00	52
	255	0	01	04
	237	0	09	36
	कार्ट ट्रेक	0	00	78
	257/पी	0	01	56
	258	0	14	56
	259	0	21	84
	287	0	07	80
	286	0	04	94
	288	0	27	56
	300/पी	0	01	12
	302	0	15	34
	304	0	19	24

[सं. ओ-12016/12/92-ओएनजीडी-IV]

एम. माटिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2512.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 1241 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land' Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan GGS to 'T' Point.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Goladara	83	0	07	28
	86	0	00	56
	85	0	18	72
	89	0	14	95
	91	0	09	88
	Cart track	0	03	38
	111	0	09	36
	109	0	14	56
	108	0	06	50
	107	0	11	70
	118	0	12	74
	119/A/B	0	15	08
	120	0	03	64
	123/A	0	00	03
	122	0	05	46
	121	0	12	48
	Cart track	0	02	60
	242	0	01	10
	241	0	18	85
	Cart track	0	00	52
	255	0	01	04
	237	0	09	36
	Cart track	0	00	78
	257/P	0	01	56
	258	0	14	56
	259	0	21	84
	287	0	07	80
	286	0	04	94
	288	0	27	56

1	2	3	4	5
	281	0	08	32
	301	0	34	32
	300/P	0	01	12
	302	0	15	34
	304	0	19	24

[No. O-12016/12/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2513.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1342 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पखाजन जी.जी.एस. से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरूच तालुका - वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	से.
1	2	3	4	5
अंभेल	59	0	12	74
	57	0	13	26
	55	0	05	24
	58	0	08	45
	51	0	15	86
	कार्ट ट्रेक	0	01	56
	42	0	29	64
	43	0	18	33
	31	0	22	88
	32	0	08	84
	कार्ट ट्रेक	0	01	56
	278/ए/बी	0	23	90
	279	0	00	15
	277	0	20	80
	276	0	01	38

[सं. ओ० - 12016/13/92/ओ. एन. जी. डी.-IV]

एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2513.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1342 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1)of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan GGS to 'T' Point.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No	Hect.	Are	Cent.
Ambhel	59	0	12	74
	57	0	13	26
	55	0	05	24
	58	0	08	45
	51	0	15	86
	Cart track	0	01	56
	42	0	29	64
	43	0	18	33
	31	0	22	88
	32	0	08	84
	Cart trak	0	01	56
	278/A/B	0	23	90
	279	0	00	15
	277	0	20	80
	276	0	01	38

[No. O-12016/13/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2514.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1343 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पखाजन जी जी एस से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरूच तालुका - वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	से.
नरणावी	11	0	06	24
	12	0	14	56
	20	0	27	17
	21	0	11	44
	28	0	15	08
	27	0	27	04
	कार्टट्रैक	0	00	65
	38	0	04	03
	36/ए	0	09	75
	36/बी	0	00	68
	35/ए/बी	0	06	24
	32	0	08	06
	33	0	06	24
	कार्टट्रैक	0	00	65

[सं. O-12016/14/92-ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2514.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1343 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan GGS to 'T' Point.

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect	Are	Cent
Narnavi	11	0	06	24
	12	0	14	56
	20	0	27	17
	21	0	11	44
	28	0	15	08
	27	0	27	04
	Cart track	0	00	65
	38	0	04	03
	36/A	0	09	75
	36/B	0	00	68
	35/A/B	0	06	24
	32	0	08	06
	33	0	06	24
	Cart track	0	00	65

[No. O-12016/14/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2515—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1344 तारीख 30-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एम एक्स एफ से जी एन ए क्यू जी जी एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात   जिला - भरूच   तालुका - जंबुसर

गांव	ब्लाक नं.	हे	आर.	से.
1	2	3	4	5
वांसेटा	29	0	20	80
	7	0	20	54
	6	0	11	44
	5	0	06	89
	3	0	11	57
	2	0	01	04
	कार्ट ट्रेक	0	21	72

[सं. O - 12016/15/92 ओ एन जी डी -IV]

एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2515.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1344 dated 30-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNXF to GNAQ GGS.

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Vanceta	29	0	20	80
	7	0	20	54
	6	0	11	44
	5	0	06	89
	3	0	11	57
	2	0	01	04
	Cart track	0	21	72

[No. 12016/15/92-ONC.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2516.—भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप खंड ii तारीख 15-6-1991 के का.आ. सं. 1717 के संदर्भ में प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन स्वरूप उसे निम्न तालिका के अनुसार पढ़ें :

ग्राम का नाम	पढ़ें				
	सर्वे	गट सं	क्षेत्र		
			हे.	एकड़	सोमार
धोवार	--	297 भाग	--	01	54
	के स्थान पर				
	सर्वे	गट सं	क्षेत्र		
			हे	एकड़	सोमार
	--	207 भाग	--	01	54

[सं. ओ-14016/1/92/जी.पी.]

राजीव महर्षि, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2516.—The partial modification to the Notification published in Govt. Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 15-6-91 S.O. No. 1717 be read as per following table :

Name of village	Read					In Place of				
	Survey	Gat No.	Area			Survey	Gat No.	Area		
			H.	Are.	CR			H.	Are.	CR
Dhovar	—	297 Part	—	01	54	—	207 Part	—	01	54

[No. O-14016/1/92/G.P.]

RAJIV MEHRISHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2517.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलिबाग से मौजे सालाव, तहसील मुरुड जंजिरा, जिला रायगढ़ तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. नई दिल्ली 110066 के मार्फत बिछाई जानी चाहिये,

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है,

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. प्रभू निवास दूसरा मजला अलिबाग मु. पोस्ट, तहसील अलिबाग, जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ,

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तहसील : मुरुड जंजिरा

गांव का नाम	सर्वे नं.	हिस्सा नम्बर	क्षेत्र		
			हेक्टर	आर	स आर
1	2	3	4	5	6
सालाव	5	1 भाग	0	02	00
	5	2/1 भाग	0	01	20
	4	2/1+3 भाग	0	01	20
	4	2/8 भाग	0	01	80
	4	2/12 भाग	0	02	50
	4	2/13 भाग	0	07	00
	4	2/14 भाग	0	07	40
	4	2/11 भाग	0	13	40
	4	2/10 भाग	0	00	30
	9	1/4 भाग	0	01	00
	9	1/6 भाग	0	08	80
	9	1/7 भाग	0	04	80
	9	1/3 भाग	0	12	80
	9	3-ए भाग	0	00	80
	9	1/8 भाग	0	04	20
	8	—	0	09	00
	66	—	0	15	40
	80	—	0	01	90

[सं. ओ-14016/1/92-जी.पी.)]

राजीव महर्षि, निदेशक

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2517.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Village-Boris, Tahsil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahsil-Murud Jangira, District Raigad in the State of Maharashtra pipeline should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16. Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066 ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred to the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said land may prefer any objection with n 21 days from the date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav, Natural Gas pipeline, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At Post Tahsil-Alibag, District-Raigad, State-Maharashtra.

And, every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Murud Janjira

Village	Survey Number	Hissa No.	Area		
			Hectare	Are	C. Are
1	2	3	4	5	6
Salav	5	1 Part	0	02	00
	5	2/1 Part	0	01	20
	4	2/1+3 Part	0	01	20
	4	2/8 Part	0	01	80
	4	2/12 Part	0	02	50
	4	2/13 Part	0	07	00

1	2	3	4	5	6
	4	2/14 Part	0	07	40
	4	2/11 Part	0	13	40
	4	2/10 Part	0	00	30
	9	1/4 Part	0	01	00
	9	1/6 Part	0	08	80
	9	1/7Part	0	04	80
	9	1/3 Part	0	12	80
	9	3-A Part	0	00	80
	9	1/8 Part	0	04	20
	8	—	0	09	00
	66	—	0	15	40
	80	—		1	90

[No. O-14016/1/92-G.P.]
RAJIV MEHRISH, Director

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का.आ. 2518.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ मे मौजे बोरीस, तहसील अलिबाग मे मौजे सालाव, तहसील मुरुड जंजीरा, जिला रायगढ़ तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., नई दिल्ली 110 066 के मार्फत बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना आशय घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. प्रभु निवास दूसरा मजला अलिबाग, मु. पोस्ट तहसील अलिबाग, जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरुप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तहसील : अलिबाग

गांव का नाम	सर्वे नं.	हिस्सा नंबर	क्षेत्र		
			हेक्टर	आर.	सें.आर
बेलकडे	--	--	307 भाग	--	80

[सं० ओ-14016/1/99-जी पी]
राजीव महर्षि, निदेशक

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2518.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Village-Boris, Tahsil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahsil-Murud Jangira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipeline should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066 ;

And, whereas, it appears to thhe Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of Notification to the Competent Authority, Tal-Salav Natural Gas Pipeline, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post, Tahsil-Alibag, District-Raigad, State-Maharashtra ;

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra Tahsil : Alibag District : Raigad

Village	Survey Number	Hissa Number	Block Number	Area		
				H	Are	C. Are
Belkade	—	—	307 Part	—	—	80

[No. O-14016/1/92-G.P.]
RAJIV MEHRISH, Director

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992

का.आ. 2519.—यतः दिल्ली बृहद् योजना 1962 में पिंजरापोल (एंड्रयूज गंज) क्षेत्र में लगभग 35 एकड़ माप की नजूल भूमि का भू-उपयोग आवास, 18 एकड़ जोनल हरित और 17 एकड़ सामुदायिक केन्द्र के लिए नियत थी।

और यतः अफ्रीका एशियाई खेलों में भाग लेने वालों के लिए आवास की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दिल्ली बृहद् योजना-62 में भू-उपयोग के अनुसार लगभग 10 एकड़ माप की भूमि सरकार द्वारा टाईप-IV के क्वार्टरों के निर्माणार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी तथा अन्य टुकड़ा 17 एकड़ पर सामुदायिक केन्द्र के निर्माणार्थ और 25 एकड़ पर साधारण पूल क्वार्टरों के निर्माणार्थ हुडको को सौंपी गई थी।

और यतः 1-8-90 को सरकार द्वारा दिल्ली बृहद योजना-2001 को अधिसूचित करते समय उपर्युक्त क्षेत्र के भू-उपयोग के संबंध में जिसे दिल्ली बृहद् योजना-1962 के समरूप होना था, का उल्लेख करना रह गया था जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त क्षेत्र के भू-उपयोग के परिवर्तन में असावधानी हुई।

और यतः दिल्ली बृहद् योजना 1962 में दर्शाए गए अनुसार उक्त भू-उपयोग को बनाए रखने हेतु लोकहित में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दिया गया था।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) में अपेक्षा के अनुसार उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन के भीतर दिल्ली विकास अधिनियम (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 23-5-92 के नोटिस सं. एफ-3(33)89-एम पी के साथ प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित किए गए थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब, उक्त अधिनियम की धारा- 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली की उक्त बृहद् योजना में पूर्वप्रभावी तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन :

"जोन एफ-3 (पिंजरापोल क्षेत्र) में पड़ने वाले और उत्तर तथा दक्षिण में गवर्नमेंट पूल हाउसिंग (एंड्रयूज गंज, सादिक नगर और आयुर्विज्ञान नगर) पूर्व में 45 मीटर चौड़े मार्शल जे.बी. टीटो मार्ग मार्गाधिकार और पश्चिम में 30 मीटर चौड़े मार्गाधिकार खेल गांव से घिरे तथा दिल्ली मुख्य योजना-2001 में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर) के लिए निर्धारित 28.75 हेक्टेयर (71 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को अधिसूचना सं. के-13012/7/71-यू.डी.आई., दिनांक 28-12-73 द्वारा अधिसूचित जोन डी-17, 18, 19, 20 और एफ-2 तथा 3 के संयुक्त क्षेत्रीय विकास नक्शों में निर्धारित भूमि उपयोग अर्थात् "आवासीय" (आवास) 14.17 हेक्टेयर, "व्यावसायिक" (समाज सदन) 6.88 हेक्टेयर और जिला पार्कों /जोनल ग्रीन- 7.70 हेक्टेयर" के लिए निर्धारित रहेगी।

[सं. के० 20013/27/91-डी-1(बी)]

आई. एल. बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 8th September, 1992

S.O. 2519.—Whereas in the Delhi Master Plan, 1962, in Pinjrapole (Andrews Ganj) Area, the land use of a Nazul land measuring about 35 acres was earmarked for housing, 18 acres zonal green and 17 acres for Community Centre;

And, whereas, to meet the urgent need for accommodation for participants of the Afro-Asian Games, as per the land use in MPD-62, a portion of land measuring about 10 acres had been entrusted by Government to CPWD for construction of Type-IV quarters and another portion had been entrusted to HUDCO for construction of Community Centre on 17 acres and General Pool Quarters on 25 acres;

And, whereas, a bona fide error had occurred while notifying the MPD-2001 by the Government on 1-8-90 inasmuch as the land use of the aforesaid area which was to continue to be in conformity with MPD-1962 was omitted to be mentioned as such resulting in inadvertant change of land use of the aforesaid area;

And, whereas, DDA was directed by the Central Government in the public interest to restore the land use of the aforesaid as mentioned in Delhi Master Plan, 1962;

And, whereas, the proposed modification was published with Notice No. F. 3(33)89-MP, dated 23-5-92, in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And, whereas, no objections/suggestions have been received with regard to the proposed modification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with retrospective effect:

MODIFICATION

The land use of an area measuring 28.75 ha. (71 acres) falling in Zone F-3 (Pinjrapole Area) bounded by Government Pool Housing (Andrews Ganj), Sadiq Nagar and Ayurvigyan Nagar, in the North and South; Marshal J. B. Tito Marg 45 metres wide R/W in the East and Khel Gaon Road 30 Mtrs. wide in the West and earmarked in MPD-2001 for public and semi-public use' (proposed Convention Centre)', is restored to land uses earmarked in the composite Zonal Development Plans of Zones D-17, 18, 19, 20 and F-2 & 3 notified vide Notification No. K-13012/7/71-UDI, dated 28-12-73 i.e. for "residential" (housing)—14.17 ha., "commercial" (community centre)—6.88 ha. and "district parks/zonal green—7.70 ha.".

[No. K-20013/27/91-D.I(B)]

I. L. BANSAL,, Under Secy. (DD)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1992

का.आ. 2520.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह निदेश देती है कि "मेकेण्ड मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट

यू.एस.एस.आर द्वारा प्रदान की गई डाक्टर आफ मेडिसन (फिजीशियन) एम.डी. (फिजीशियन)" आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी।

[संख्या वी 11016/5/91-एम. ई. (यू. जी.)]

आर विजयकुमारी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th July, 1992

S.O. 2520.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consultation with the Medical Council of India hereby directs that the Medical qualification "Doctor of Medicine (Physician).....M.D. (Physician) granted by the Second Moscow Medical Institute. U.S.S.R.", shall be recognised medical qualification for the purposes of this Act.

[No. V. 11016/5/91-ME(UG)]

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वेक्षण एवं प्रबेक्षण यूनिट-I)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का.आ. 2521.—दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे दिल्ली प्रशासन को तिमारपुर दिल्ली में टाईप-7 क्वार्टर बनाने हेतु हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है:—

अनुसूची

लगभग 5 एकड़ भूमि माप का भूमिखण्ड जो तिमारपुर दिल्ली में स्थित है, जिसका स्थल संख्या 59 है, और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का आंशिक समस्त भाग है, उपयुक्त भूमि खण्ड की सीमायें निम्नलिखित है:—

उत्तर में—	सरकारी भूमि
दक्षिण में—	ईडल टर्क पार्किंग
पूरब में—	सरकारी भूमि और मैगजीन रोड
पश्चिम में—	दिल्ली प्रशासन क्वार्टर

[म एस एण्ड एस/33/(1)92/ए एस ओ (आई) पार्ट-I/1131]

रणवीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit-I)

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2521.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Officer, Ministry of Works & Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Delhi Administration Construction of Type-VII flat, Timarpur, Delhi.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 5 acres situated in Timarpur Delhi bearing plot No.———— site No. 59 partly/full of Notification No S.O. 1810 dated 20th July, 1974.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : By Govt. land.

South : By Idle Truck Parking.

East : By Govt. land & Magzine Road.

West : By Delhi Administration Quarters.

[No. S&S 33(1)92/ASO(I)/Pt. I/1131]

Sd/- (Illegible)
Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

का.आ. 2522.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 948 दिनांक 12 मार्च, 1992 द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/9/85-डी-I(ए)(i)]

एस एस. प्रशर, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th September, 1992

S.O. 2522.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 948 dated the 12th March, 1922, the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 14th March, 1992;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 14th September, 1992.

[No. S-11017/9/85-D.I(A)(i)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

का.आ. 2523.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 949 दिनांक 12 मार्च, 1992 द्वारा शीशा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद, अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/9/85-डी.-I(ए)(ii)]

एस. एस. प्राशार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1992

S.O. 2523.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 949 dated the 12th March, 1992, the Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 14th March, 1992;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 14th September, 1992.

[No. S-11017/9/85-D.I(A)(ii)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

का. आ. 2524.—केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि उद्योग, भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 11 द्वारा शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का.सं. एस-11017/6/85-डी-I(ए)]

एस.एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1992

S.O. 2524.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the industry, India Government Mint, Calcutta, which is covered by entry 11 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/6/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2525.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रम ब्यूरो कार्यालय, मद्रास में नियुक्त सहायक निदेशक श्री वी. जयारामन को 24 अगस्त से 26 अगस्त, 1992 तक उत्प्रवासी संरक्षी, मद्रास के कार्यालय में उत्प्रवासी संरक्षी, मद्रास के सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22012/1/92-उत्प्रवास]

आर.के. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2525.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri V. Jayaraman, Assistant Director in the office of Labour Bureau, Madras to perform all functions of Protector of Emigrants, Madras in the office of Protector of Emigrants, Madras from 24th August, to 26th August, 1992.

[F. No. A-22012/1/92-Emig.]

R. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2526.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मधाईपुर कोलियरी आफ मैसर्स ई.सी लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एस-22012/435/90—आई.आर (सी II)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2526.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2nd September, 1992.

[No. L-22012/435/90 IR-C(1)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 20/91

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P. Banerjee, Advocate.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 24th August, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/485/90-IR(C.II) dated the 16th April, 1991.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Madhaipur Colliery of M/s. ECL, P.O. Nutandanga, District Burdwan, in denying payment of difference of wages to Shri Hriday Narayan Singh, Pit Clerk w.e.f. 1st April, 1983 to 31st March, 1986 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Sri P. Banerjee the learned Advocate for the management is present today (24-8-92). None appears for the union. It appears from the record that the Reference Case was received by this Tribunal on 24th April, 1991. The parties filed their respective written statements. But the union did not file its rejoinder. On 27th July, 1992 on the prayer of the union the case was fixed on 10th August, 1992 for filing rejoinder of the union. On 10th August, 1992 none was present for the union though Sri P. Banerjee, Advocate for the management was present. Today also none appears for the union.

3. From the conduct of the union it appears to me that the union is not interested to proceed with this case. So I have no other alternative but to pass a no-dispute award. Accordingly a no-dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली 7 सितम्बर, 1992

का.आ 2527 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मधाईपुर कोलियरी आफ मैसर्स ई सी लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/486/90-आई आर (सी II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2527.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madhaipur Colliery of M|s. B.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-92.

[No. L-22012/486/90-IR CII]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 19/91

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C.Ltd.

AND

Their Workman

APPEARANCES:

For the Employers—Shri P. Banerjee, Advocate.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 24th August, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Minisry's Order No. L-22012(486)/90-IR(C.II) dated the 16th April, 1991.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Madhaipur Colliery of M/s. ECL, P.O. Nutandanga, Dist. Burdwan, in denying difference of wages and placement of Shri Madan Singh, Pump Khalasi from Cat. III to Cat. IV as Armature Winder is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Sri P. Banerjee the learned Advocate for the management is present to-day (24-8-92). None appears for the union. It appears from the record that the Reference Case was received by this Tribunal on 24-4-91. The parties filed their respective written statement. But the union did not file its rejoinder. On 27-7-92 on the prayer of the union the case was fixed on 10-8-92 for filing rejoinder of the union. On 10-8-92 none was present for the union though Sri P. Banerjee, Advocate for the management was present. Today also none appears for the union.

3. From the conduct of the union it appears to me that the union is not interested to proceed wih this case. So I have no other alternative but to pass a no-dispute award. Accordingly a no-dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2528:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू सी एल. चन्दा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/6/90-आई आर (सी II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of WC Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-92.

[No. L-22012/6/90-IR CII]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/IC(R)(147)/1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd., Chanda Bayatwari Colliery, Post & District Chandrapur (MS) and their workman, Shri Kankayya Odelwar, represented through the President Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh, Anchaleshwar Ward, Post and District Chandrapur (MS).

APPEARANCES :

For workman—Workman himself.

For Mangement—S/Shri B. N. Prasad and G. S. Kapoor Advocates.

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chandrapur (MS)

AWARD

Dated, August 14, 1992

This is a reference mad by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012(6)| 90-IR(C-II) Dated 24-5-1990, for adjudication of the following dispute:—

SCHEDULE

"Whether the action of the mangement of Chanda Rayatwari Colliery of M/s. W.C. Ltd. in not promoting Sri Kankayya Odelwar, from clerk Grade III to Clerk Grade II w.e.f. 1-8-87 is justified If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. This case was at the stage of recording evidence of parties. On 27-1-1992 Counsel for Mnaagement filed Affidavit of Shri N. K. Seth and stated that no other witness is to be examined. Since the workman was not present on 27-1-1992 the case was fixed for cross-examination of the management's witness on 25-5-1992.

3. The dispute between the workman and the management is with regard to non-promotion of workman concerned from clerk Grade III to Clerk Grade II w.e.f. 1-8-1987.

4. The case was fixed for cross-examination of the witness, evidence of the workman and hearing on the objection of the management whether the workman can himself represent the case on 3-8-1992. On this date, none appeared on behalf of the workman. The Counsel for management, Shri G. S. Kapoor, gave in writing that the management is prepared to upgrade Shri Kankayya Odelwar from Clerical Grade III to clerical Gr. II from the date he gives an option to do the additional jobs as mentioned in National Coal Wage Agreement III, implementation instructions No. 25, dated 1-8-84 as per Clause 1(a), (b), (c) & (d). Since the workman was not present on 3-8-1992 it was unnessary to wait for his option as required by the management and the management's offer as stated above appears to be just and fair and in the interest of the workman concerned. I therefore direct the management to upgrade the workman, Shri Kankayya Odelwar from Clerical Gr. III to Clerical Gr. II and the workman to perform the duties as given above. In case he fails to perform his duties as above the management shall be free to take action according to law, relevant rules etc. Award is given accordingly without any order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2529:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पैराशिया कोलियरी आफ मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-19012/20/86-डी 4 (बी)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2129.—In pursance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parasea Colliery of M/s. Eastern Cool fields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-1992.

[No. L-19012/20/86-D. IV (B)]

RAJA LAL, Desk Officer.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 75 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parasea Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manash Nath Roy ..Presiding Officer

APPEARANCE :

On behalf of Management : Mr. P. Banerjee, Advocate.

On behalf of Workmen : Mr. A. K. Das, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

It appears from the petition filed today, enclosing terms of settlement and a copy of the Office Order dated 18th July, 1987, that the dispute as referred for adjudication to this Tribunal by the appropriate Government, vide Order No. L-19012/20/86-D. IV (B), dated 21st November, 1986, has been amicably settled. In that view of the matter, after hearing the parties and considering the statements as contained in the application, so also the terms, which appeared to be reasonable, I dispose of this reference on the basis of such terms of settlement.

2. Let the terms of settlement and copy of the Office Order be form part of this Award.

3. This reference is thus disposed of as rejected without going into the merits.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 20th August, 1992.

MANASH NATH ROY, Presiding Officer.

EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of C.I.L.)

Office of the C.G.M. Kunustoria Area.

Reference No. A. KNT/P&IR/26(.)/6053, dated 17-7-87.

Regd., with A/D.

To,

The Asstt. Labour Commissioner (Central), Searsole Rajbari, P.O. Searsole Rajbari, Distt. Burdwan.

The Regional Labour Commissioner (Central), 19/1, Apear Garden, Asansol.

The Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

The Secretary to the Government of Indian Ministry of Energy, New Delhi.

Dear Sir(s),

We are sending herewith a copy of memorandum of settlement in form 'H' in respect of Sri Satram Bhar, Ex-Trammer of Parasea colliery, Kunustoria Area, ECL for year kind perusal and necessary record.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

G. R. SINGH, Dy. Chief Personnel Manager.

Kunustoria Area.

FORM—'H'

(See Rule—58)

FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of the PARTIES :

Sri G. R. Singh, Dy. Chief Personnel Manager, Kunustoria Area, ECL, P.O. Toposi, Distt. Burdwan.

Representative of the Workman :

Sri Santosh Dutta, Secretary, CMSI (CITU), Sishubegan, Raniganj.

Sri Satram Bhar, workman concerned.

SHORT RECITAL OF THE CASE.

Sri Satram Bhar, Ex-Trammer of Parasea colliery was dismissed on the misconduct for abusing and assaulting his superior on duty by the competent authority after proper enquiry into the charge-sheet issued to him for the above misconduct. He was dismissed on 30-8-1984.

The representative of CMSI (CITU) represented to the management for his re-instatement. He was also referred by the union to conciliation where it ended in failure and the same was referred to Tribunal, Calcutta. On the request of the union the matter was discussed at different levels and after prolonged discussion the competent authority has considered the reinstatement of Sri Satram Bhar which has been communicated vide letter No. ECL/CMD/C-6D/IL/87/3174 dated 11/13-7-1987, on the following terms and conditions :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. Sri Satram Bhar will be reinstated in his same designation and in the same category prior to his dismissal.
2. He will not be entitled any back wages and financial benefit except continuity of service for the purpose of gratuity only.
3. On reinstatement he will be posted presently at Parasea colliery.
4. He will join his duty on and from 18th July, 1987.

A joint petition will be submitted both by the management and the union before the Presiding Officer Industrial Tribunal (Central) Calcutta for an agreed award in the above context.

Representing the workman.

Santosh Dutta,

Secretary,

CMSI (CITU),

Sishucagan Raniganj.

Representing the Employer.

G. R. SINGH,

Dy. Chief Presonnel Manager,
Kunustoria Area.

WITNESS :

1. Mrs. R. B. Rathore,

Dy. Personnel Manager,
Kunustoria Area.

2. Illegible.

EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiery of Coal India Ltd.)

Parasea Colliery.

Ref. : ECL/PC/P&IR/8/87/1246, dated 18-7-1987.

OFFICE ORDER

In persuance of letter No. A. KNT/P&IR/26(o)/6053, dated 17-7-1987 of the Dy. Chief Personnel Manager, Knt. Area Sri Satram Bhar, Ex-Trammer, Parasea Colliery, dismissed on the misconduct for abusing and assaulting her superior on duty is hereby reinstated on the following terms and conditions :—

1. Sri Satram Bhar, will be reinstated in his same designation and in the same category prior to his dismissal.
2. He will not be entitled any back wages, and financial benefit except continuity of service for the purpose of gratuity only.
3. On resinstatement he will be posted presently at parasea Colliery.
4. He will join his duty on and from 18th July, 1987.

As such, Sri Bhar, is hereby allowed to join his duties on 18-7-1987 and asked to report to the Manager, Parasea Colliery for his duty.

AGENT, Parasea/belbuld

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2530 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दामुआ कॉलियरी आफ डब्ल्यू.सी.एल. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/367/91-1 आई आर (सी II)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damua Colliery of W. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2nd September, 1992.

[No. L-22012/367/91-IR.C.II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC(R)(7)/1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Damua Colliery of W.C. Ltd., Kanhan Area, P.O. Dungaria, District Chhindwara (M.P.)

AND

Their workman, Shri Vidiya S/o Nandlal, represented through the General Secretary, Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS) P.O. Chandamotta, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—None.

For Management—Shri R. Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated, August 19, 1992

This is a reference made by the Central Government Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/367/91-IR(C-II) Dated 28th January, 1992, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management i.e. Manager, Damua Colliery of WCL, Kanhan Area, P.O. Damua, District Chhindwara (M.P.) in dismissing from services to Shri Vidiya S/o Nandlal, Ex tub Loader of Damua Colliery w.e.f. 27th August, 1988 on the basis of the enquiry conducted without giving him opportunity to reform is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. On receipt of the Reference Order the Union sent statement of claim in respect of workman concerned which was received by post in this Tribunal on 2nd March, 1992. Next date fixed for filing the statement of claim by the management was 6th July, 1992. On this date parties absented themselves and the case was adjourned to 4th August, 1992.

3. Workman again failed to appear on 4th August, 1992. Counsel for management appeared and filed a Memorandum of Settlement and verified the same before this Tribunal. The terms of settlement are as under :—

1. Shri Vidhya S/o Nand Lal, Ex-Tub Loader, will be reinstated at Damua Colliery of Kanhan Area w.e.f. 29th April, 1992. He will work at Damua Colliery for a week only and thereafter, he will be transferred to Nandan Mint No. 2.

2. This is full and final settlement in the issue of reinstatement of Shri Vidhya S/o Nandlal, Ex-tub Loader, Damua Colliery.

4. On account of conspicuous absent of the workman which follows that the workman has nothing to say against the terms of settlement which have been verified by the Counsel for Management. Impliedly the workman admits the settlement arrived at between the parties being beneficial to him. In my opinion also the terms of settlement are just and fair. I therefore pass an award in terms of the settlement duly signed by the representatives of the management and the Union. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2531 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ऑफ मैसर्स कोल इण्डिया लि० के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, गोहाटी के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/89/89-आई आर (सी II)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2531.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Guwahati as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Eastern Coalfields of M/s. Coal India Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2nd September, 1992.

[No. L-22012/89/89-IR(C) II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM

Reference No. 2(c) of 1990

PRESENT :

Shri D. N. Hazarika, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Guwahati.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Management of North Eastern Coalfields of M/s. Coal India Ltd.

AND

Their workmen represented by General Secretary, Janata Mazdoor Sangha, Bargalai.

APPEARANCES :

Smt. Mili Hazarika, Advocate—For the Management.

None—For the workman.

AWARD

This Reference arising out of the Central Government Notification No. L-22012(89)/89-IR(C-II), dated 31st January, 1990 relates to the dispute indicated in the schedule below—

"Whether the action of the Management of Coal India Ltd., Margherita, in refusing the payment of ex-gratia to 228 workmen (deployed through different contractors regularly against perennial jobs of Coal India Ltd.) at par with other employees of the Coal India Ltd. is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

On receipt of the Notification the Reference was registered and notices were issued to the parties to file their written statements. Management appeared and submitted written statement. Union never appeared inspite of repeated notices. Hence the case was fixed for ex-parte hearing.

On the date of ex-parte hearing union appeared and prayed for time to file written statement. Thereafter union did not appear in 3 consecutive dates. Therefore case was fixed for ex-parte hearing.

Management in support of their case examined one witness. Witness K. Duara in his evidence stated that case of temporary nature of works like construction of temporary roads and bridges contractors are engaged to complete the works. Contractors engage labourers for completion of works allotted to them. As soon as the work is over, contract between the management and contractor ceases to exist. Management never employed or engaged any contractual labour or contractor for any perennial nature of work. So question of payment of ex-gratia or bonus to these labourers who has been engaged by contractors does not arise.

From the evidence of K. Duara, I find management engages contractors for temporary nature of work and labourers who work under these contractors are not employed by management to do any prennial nature of work. Management is not under any obligation to pay ex-gratia or bonus to these labourers who are temporarily engaged by contractor. Therefore I find management was justified in not paying ex-gratia to 228 workman (deployed through different contractors).

I give this Award on this 14th day of August, 1992 at Guwahati.

D. N. HAZARIKA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का.आ. 2532.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खाकीकोल आफ डब्ल्यू सी एल. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/192/91-आई आर (सी II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2532.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rakhikel Area of W.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-92.

[No. L-22012/192/91-IR(CII)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(130)/1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Rakhikol Area of W.C. Ltd., Kanhan, Post Dungaria, District Chhindwara (M.P.) and their workmen Shri Kishan S/o Lotan, D.P.R. Mazdoor of Incline No. 5/6, represented through the S.K.M.S. Post Chandametta, District Chhindwara (MP)-480447.

APPEARANCES :

For workman—None.

For Management—S/Shri B. N. Prasad & G. S. Kapoor Advocate.

INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Chhindwara (MP)

AWARD

Dated : August, 16, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/192/91-IR(Coal-II) dated 2-7-1991 for adjudication of the following dispute :—

'Whether the action of the management of Western Coalfields Ltd., Kanhan Area in relation to their Rakhi Coal Mine in terminating/dismissing the services of Shri Kishan S/o Lotan D.P.R. Mazdoor of incline No. 5/6 w.e.f. 20-6-1989 is proportionate to the gravity of offence and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Despite several notices neither party filed any statement of claim. Workman failed to put his appearances on 22-8-1991, 11-10-1991, 9-1-1992, 4-3-1992 and 2-4-1992. It appears that he has no interest in the case. No dispute award is therefore recorded in the case. No costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का०आ० 2533.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स आफ टन्डसी प्रोजक्ट आफ डब्ल्यू सी एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/489/90-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Tandsi Project of WC Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-92.

[No. L-22012/489/90-IR-CII]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(59)/1991

PARTIES :

Employers in relation to the mangement of M/s. Tandsi Project of W.C. Ltd., Kanhan Area, P.O. Rampur, District Chhindwara (MP) and their workman Shri Pradeep Kumar Arora, General Mazdoor of Tandsi Project, represented through the Organising Secretary, R.K.K.M.S. (INTUC), Post Chandametta, District Chhindwara (MP)-480447.

APPEARANCES :

For Workman—None.

For Management—S/Shri B. N. Prasad & G. S. Kapoor, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Chhindwara (MP)

AWARD

Dated : August, 16, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/480/90-IR(Coal-II) Dated 3-4-1991, for adjudication of the following dispute:—

"Whether the action of the management of Manager, Tandsi Project, WCL. Kanhan Area, P.O. Rampur, Distt. Chhindwara (M.P.) in dismissing from service to Shri Pradeep Kumar Arora, General Mazdoor of Tandsi Project w.e.f. 17-6-1989 on the basis of the enquiry conducted without giving him an opportunity to reform is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. Both parties were noticed but none filed any statement of claim. Workman never appeared inspite of notice i.e. on 7-6-1991, 30-8-1991, 28-10-1991, 6-1-1992, 3-3-1992 and 2-4-1992. It appears that he has no interest in the case. No dispute award is therfore recorded in the case under reference. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का०आ० 2534.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नन्दन कौलयारी आफ डब्लयू सी एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-22012/436/90 आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2534.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the mangement of Nandan Colliery of WC Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-92.

[No. L-22012/436/90-IR C-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(58)/1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nandan Colliery of W.C. L., Nandan Mine No. 1, Kanhan Area, Post Nandan Colliery, District Chhindwara (MP)-480001 and their workman. Shri Bishanlal S/o Behra, General Mazdoor, represented through the Secretary, S.K.M. Sangh (AITU), Post Chandametta, District Chhindwara (MP)-480447.

APPEARANCES :

For Workman—None.

For Management—None.

INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Chhindwara(MP)

AWARD

Dated August, 16, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/436/90-IR(Coal-II) Dated 3-4-1991 (received on 10-4-1991) for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of Nandan Colliery of W.C. Ltd., in terminating the services of Shri Bishnlal S/o Behra, General Mazdoor, w.e.f. 13-3-1989 is legal and justified? If not to what relief the concerned workman is entitled to and from what date?"

2. On receipt of the reference order parties were noticed. Non appeared for either side on 7-6-1991, 30-8-1991, 9-1-92 30-3-1992, 6-7-1992 and 4-8-1992. No statment of claim has been filed by either party. Workman took no interest in the case. Therefore it appears that the workman has no interest in prosecuting his case. No dispute Award is therefore recorded. Parties to bear their own costs..

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

का०आ० 2535.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सार्थ चिरीमिरी कोलयरी आफ एस ईसी एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-22012/182/91-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th September, 1992

S.O. 2535.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery of S.E.S. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2nd September, 1992.

[No. L-22012/182/91-IR(C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC(R)(13)/1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery of S.E.C. Ltd., District Surguja (M.P.)

AND

Their workman Shri Gharbharan, General Mazdoor, North Chirimiri Colliery, represented through the Secretary, M.P. Koyla Mazdoor Sabha (HMS), P.O. North Chirimiri Colliery, District Surguja (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management—Shri R. Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Surguja (M.P.)

AWARD

Dated : August 19, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/182/91-IR(C-II) dated 8th January, 1992, for adjudication of the following dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of North Chirimiri Colliery of Chirimiri Area of SECL, in dismissing from services of their workman Shri Gharbharan, General Mazdoor, North Chirimiri Colliery is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. This case was fixed on 4th August, 1992 for filing the statement of claim etc. instead of filing the statement of claim by the parties Counsel for the management, Shri Menon, filed an application stating that the Reference Case No. CGIT/LC(R)(149)/91 is already pending and therefore another reference on the same point cannot be entertained. He sought for suitable orders.

3. I have gone through the record of Reference No. CGIT/LC(R)(149)/91 which is fixed for 9-9-92. According to the record, this is the same reference and obviously the same second reference while the earlier reference is pending cannot be entertained. The present reference is accordingly rejected.

The reference is disposed off accordingly.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का० आ० 2536:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग, पेडा पल्ली, जिला करीम नगर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/24/91-आई०आर (डी०यू०)]

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2536.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecommunication, Peddapal (Karimnagar) and their workmen, which was received by the Central Government on 8-9-1992.

[No. L-40012/24/91-IR(DU)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri G. Krishna Rao, B.A., B.L., Industrial Tribunal.

The Thirteenth day of August, Nineteen Hundred Ninety Two

Industrial Dispute No. 52 of 1991

BETWEEN:

Sri K. Chinna Devayya, S/o. Sri Venkatarathnam, Sivapuran, Village Ventrapagad-521263. —Petitioner.

AND

The Sub-Divisional Officer, Department of Telecommunication, Peddapally, Dist. Karimnagar (AP)-505172.

—Respondent.

This case is coming for final hearing before me in the presence of Sri M. Panduranga Rao and Sri B. G. Ravinder Reddy, Advocates for Respondent—Management and None for the Petitioner—workman and upon persuing the material papers on record and having stood over for consideration till this day, the Court passed the following :

AWARD

This is a reference made by the Government of India Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/24/91-IR(DU) dt. 24-9-1991/3-10-1991 for adjudication of the dispute between the Management of M/s. Telecom, Pedapally (A.P.) and their workman, setting forth the point for adjudication in the schedule appended thereto as follows :

'Whether the action of the Management of M/s. Telecom, Paddapally, (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the service of Sri K. China Devava, is justified ? If not, to what relief, the workman concerned is entitled ?"

This reference was registered as I.D. No. 52 of 1991 on the file of this Tribunal. After receiving notices from this Tribunal, both parties put in their appearance and later the Advocate for the Petitioner reported no instructions and the petitioner remained ex parte and did not file any claims statement. The Respondent filed counter.

2. The averments of the counter filed by the Respondent read as follows:

It is submitted that the reference made by the Government is neither maintainable in law nor on facts. The various allegations made in the claim statement are not correct and are therefore hereby denied. The petitioner is put to strick proof of the same. It is submitted that the petitioner was engaged as a Casual mazdoor on daily wages depending upon the availability of work. The casual mazdoors are engaged for laying the cables, erecting poles etc.. The work of the casual mazdoor comes to an end as and when the work is over. The work of the casual mazdoor is not continuous and purely depends upon the availability of work.

It is submitted that in cases of casual mazdoors, there is no question of termination. Casual mazdoors will be discontinued as and when the work is over. Therefore, the allegation that the petiioner was terminated from service and that the termination is in violation of Section 25-F of the I.D. Act is not correct. It is submitted that there is no termination of service much less retrenchment of service. Section 25-F of the I.D. Act is not applicable to the facts and circumstances of this case and question of complying with the provisions of Section 25-F does not raise. It is submitted that the Respondent is a Government of India Department and it has got procedure for engaging regular employees. The casual mazdoors are meant purely for discharging casual nature of work and they have no right of whatsoever nature to seek for absorption or for employment under the Respondent. The various judgements cited by the petitioner in the claim statement are not relevant and are not applicable to the facts of this case. The Petitioner was not eligible for granting of temporary status as he was not engaged prior to 30-3-1985. It is, therefore, prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled for any relief.

3. No oral or documentary evidence are adduced by the Respondent and the Respondent's side was closed.

4. The point for adjudication is whether the action of the Management of M/s. Telecom. Peddapally (A.P.) represented by their sub-Divisional Officer in terminating the services of Sri K. Chinnadevaya is justified, if not, to what relief the workman concerned is entitled to ?

5. POINT : After receiving the notice from this Tribunal the petitioner put in his appearance through his Advocate and later the Advocate reported no instructions for the petiioner. and the petitioner was called absent and set exparte. The Respondent also did not adduce any oral or documentary evidence in this case. The case of the petitioner was not put forth before this Tribunal by filing any claim statement nor was it put forth by adducing any oral or documentary evidence. The Petitioner did not evince any interest to prosecute his case and establish his case by adducing any positive evidence. No material is brought on record to show that the Petitioner workman for more than 240 days continuously within a period of 12 months immediately prior to the date of his alleged termination from service, for the petitioner to claim that the provisions of Section 25-F of the I.D. Act are attracted and the termination from service amounts to retrenchment and therefore he is entitled for instatement on the ground that the provisions of Section 25-F are not complied with. In any view of the matter, there is no material brought on record to hold that the petitioner was terminated from service after he worked for more than 240 days continuously under the Respondent. So under the facts and circumstances of the case, I am of opinion that the petitioner is not entitled to any relief in this Tribunal and adduce any evidence on his behalf to give any relief to him and to pass an Award in his favour. Hence I answer the point accordingly.

6. In the result, an Award is passed holding that the Petitioner is not entitled for any relief in this case. There will be no order as to costs.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 13th day of August, 1992.

G. KRISHNA RAO, Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

NIL

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का०आ० 2537.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यूक्लीयर फ्यूल कम्प्लैक्स, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल० 42012/97/87-डी II(बी)]

बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2537.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on 8-9-92.

[No. L-42012|97|87-D.II(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

THIRTY FIRST DAY OF JULY NINETEEN HUNDRED NINETY TWO

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 3 OF 1989

BETWEEN

The Workmen of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.
... Petitioner

AND

The Management of Nuclear Fuel Complex Hyderabad.
... Respondent

This case is coming for final hearing before me in the presence of M/s. G. Bikshapathi, G. Vidya Sagar, V. Vishwanatham, N. Vinesh Raj and K. V. V. Bhaskar, Advocate for the Petitioner-workman and Sri M. Panduranga Rao, Central Government Standing Counsel for Industrial and Labour case for Respondent-Management and upon perusing the material paper on record and having stood over for consideration till this day, the Court passed the following :

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-42012/97/87-D.II (B) dated 27-12-1988, for adjudication of the dispute between the Management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workmen, setting forth the point for adjudication in the schedule appended thereto as follows :

> "Whether the action on the part of the Management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in terminating the services of Sri D. Hanumantha Rao, as a casual labourer with effect from 27-12-1985 is legal and justified ? If not, to what relief the said workmen is entitled ?"

The said reference was registered as Industrial Dispute No. 3 of 1989 on the file of this Tribunal. After receiving the notices from this Tribunal, both parties put in their appearance and the Petitioner filed the claim statement on 12-7-89 and the Respondent filed the counter on 25-8-1989.

2. The averments of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :

It is respectfully submitted that the respondent appointed the petitioner by its Order NFC/AR/0225/83 dated 18-4-83 on casual basis to work in their Accounts Department with effect from 18-4-1983. The Petitioner joined duty on the same day and was working in that department continuously till 6th May 1984. On 7-5-1984 the Respondent by its order

No. NFC/PAR/0225 dated 7-5-1984 directed the Petitioner to report to Sri G. R. G. Chowdary, Asst. Stores Officer, Accordingly the petitioner reported to the said officer on that day and was working under him till his services were illegally, without any cause and with malafide intention, terminated with effect from 27-12-85. From 18-4-1983 to 27-12-1985 the petitioner was working continuously and to the utmost satisfaction of his superiors. During the period he was paid daily wages once in a month. It is submitted that as per the regulations the employees who worked for more than 180 days in a year, are entitled for regularisation of their services. The petitioner's services ought to have been regularised on 18-4-1984 with effect from 18-4-1984. The petitioner was entitled to be regularised in the services of the Respondent organisation in the post of Helper Grade I and ought to have been paid the same salary as a Helper Grade I is paid. With a view to avoid regularisation of services of the petitioner, the management resorted to the illegal practice to giving artificial breaks and ultimately terminated the services of the petitioner with effect from 27-12-1985. The petitioner was not given any official order to the effect that his services were terminated. The Security Officials at the gate were informed that the petitioner was not to be allowed into the premises. The petitioner was surprised at this action of the Management as he was reliably informed that the Chief Officer of the Personnel Department of the management passed orders regularising his services in the post of Helper Grade-I just 2 or 3 days before and that he will be receiving orders shortly. The petitioner demanded an interview with the Personnel Officer. on 27-12-1985 He was asked to come on the next day The Petitioner went to the factory on 28-12-1985 as usual He was asked to wait to see the Personnel Officer, He waited in the open outside the factor gate till 12.30 hrs. in the afternoon. when he was informed that he should come on the next day. This went on continuously for more than 3 months and ultimately in the month of April, 1986 he was informed that his services were terminated with effect from 27-12-1985 and that the question of continuing him even as a Casual Labour let alone regularising his services in the post of Helper-Grade I does not arise. It is submitted that termination of the services of the petitioner without even a formal order duly served him is illegal and arbitrary. There was absolutely no cause for terminating the services of the petitioner. Whereas junior to the petitioner were continued and regularised the services of the petitioner were terminated. Sarvasri D. Raja Rao, B. Bikishapathi, Murali Krishna etc., who were working as casual labours, were regularised in service but the petitioner's services were arbitrarily terminated. The petitioner completed one year service by 18-4-84 and ought to have been regularised in the post of Helper Grade I with effect from 18-4-1984. The petitioner completed more than 240 days of service and the respondent factory is covered by the provisions of Industrial Disputes Act 1947. The Respondent before terminating the services of the petitioner has not given one month notice or the one month wages in lieu of notice. The Respondent has also not paid retrenchment compensation as per Sec. 25-F of the Industrial Dispute Act. Hence the termination amounts to retrenchment without following Sec. 25-F of the Act is illegal and void. It is submitted that the Petitioner is entitled to regularisation of his services and post of Helper or other categories posts. Number of vacancies in Helper category were filled up from the casual labour who worked for more than 180 days. Instead of regularising the services of petitioner as Helper, terminating his services is illegal and arbitrary. Ever since the termination from service, the Petitioner is facing severe financial difficulties. He could not secure any alternate employment inspite of his best efforts. It is therefore prayed that the Honourable Court may be pleased to hold that the action of management in terminating the services of petitioner w.e.f. 27-12-85 is illegal arbitrary and contrary to provisons of I. D. Act and consequently pass an award directing the Respondent to reinstate the petitioner into service as Helper in category post with back wages, continuity of service and other attendant benefits and grant such other relief or reliefs as the Honourable Court deems fit and perfect under the circumstances.

3. The averments o fthe counter of the Respondent Corporation read as follows :

It is submitted that the various allegations made by the Petitioner in his claim statement are not correct are therefore hereby denied. It is submitted that the Petitioner was working only as Casual Labour and he never put in continuous service under the Respondent. The petitioner was working in leave vacancy and his employment was never regular. His services were utilised as and when work was available and as and when he was willing to work. The Petitioner worked for 167 days in 1983 during the period from 18-4-1983 to 30-11-1983 and for 149 days from 4-5-84 to 25-12-84 and for 199 days from 1-1-1985 to 10-12-1985. It is submitted that the allegation that he was retrenched from service is not correct. The Petitioner was only a Casual Labour and when the employment itself was casual i.e., not regular but only intermittent, there cannot be any termination or retrenchment of his service. The Respondent is a Government Department and it has a procedure for recruitment and the allegation that breaks were injust in the service of the petitioner to avoid regularisation is not correct. The Petitioner was aware that he was working on Casual basis in leave vacancies only and was never assured or any regular employment under the Respondent. It is always open to the Petitioner to offer himself for Casual employment subject to availability of work like others seeking such employment. It is submitted that allegation that Sec. 25-F is violated is not correct as casual employees are specifically excluded from the purview of Sec. 2(oo) of the Industrial Disputes Act. The allegation that some of his juniors are still working has no basis. The reasons being that though all the employees including the Petitioner, applied for regular appointments as internal candidates could not qualify in the interview conducted by the Selection Committee for the purpose of regularisation As such, he was not given regular appointment. It is submitted that the petitioner has not made out any case and he is disentitled to any relief neither in law nor on facts. The Petitioner is put to strict proof that he is not otherwise gainfully employed. It is therefore, prayed that this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the claim petition with costs to the Respondent.

4. W.W.1 was examined for the Petitioner and the petitioner's side was closed Exs. W1 and W2 were marked for the Petitioner. No witnesses were examined on behalf of the Respondent and the Respondent's side was closed.

5. The point for adjudication is whether the action on the part of the Management of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in terminating the services of Sri D. Hanumantha Rao, as a casual labourer with effect from 27-12-1985 is legal and justified ? If not, to what relief the said workmen is entitled?

6. POINT : The case of the Petitioner was that the Respondent appointed him by its order dt. 18-4 1983 as per Ex. W1 on casual basis to work in their Accounts Department, that the Petitioner joined duty on the same day and he was working in that Department continuously till 6-5-1984, that on 7-5-1984 the Respondent by its order dated 7-5-1984 directed as per Ex. W2 the petitioner to report to Sri G. R. G. Choudary, Assistant Stores Officer, that accordingly the Petitioner reported to the said Officer on that day and he was working under him till his services were terminated w.e.f. 27-12-1985, that from 18-4-1983 to 27-12-1985 the Petitioner worked continuously, that during this period he was paid daily wages once in a month, but with a view to avoid regularisation of his service, the Management resorted to the illegal practice of giving artificial breaks and ultimately terminated the services of the Petitioner w.e.f. 27-12-1985, that the Petitioner was not given any official order to the effect that his services were terminated, that the security officials at the gate were informed that the Petitioner was not to be allowing into the premises, that the Petitioner demanded an interview of the Personnel Officer on 27-12-1985, that he was asked to come on the next day, that the Petitioner want to the factory on 28-12-85 as usual, that he was asked to wait to see the Personnel Officer that he waited outside the factory gate till 12.30 hrs. in the afternoon, when he was informed that he should come on the next day, that this went on continuously for more than three months and ultimate in the month of April, 1986 he was informed that his service were terminated with effect from 27-12-1985 and that the termination of the services of the petitioner without even a formal order duly served on him is illegal and arbitratary, that his juniors were continued and regularised in services, that the Petitioner completed one year service by 18-4-1984 and he ought to

have been regularised in the post of Helper Grade I w.e.f. 18-4-1984, that the petitioner completed more than 240 days of service and the Respondent-Factory is covered by the provisions of the I. D. Act, that the Respondent before terminating his services, has not given one month's notice or one month wages in lieu of notice, that the Respondent has also not paid retrenchment compensation as per Section 25 of the I. D. Act.

7. The petitioner examined himself as W. W. 1 and deposed that he was appointed as casual labourer on 18-4-1983 in the Respondent Company, that he was given the post of Inward and Outward Clerk in the Accounts Department of the Respondent-Company, that he worked in the said post till May, 1984, that on 27-12-1985 his services were orally terminated by the Respondent-Company, that the Respondent-Company did not issue any notice to him before terminating his services and the Respondent-Company did not pay him any retrenchment compensation and, it also did not pay notice pay in lieu of not issuing notice to him that no reasons are assigned by the Management of the Respondent-Company for terminating him from service, that he was not given any written order terminating the services by the Respondent-Company, that Ex. W-1 is the appointment order dated 18-4-1984 issued to him by the Respondent-Company directing him to work in the Accounts Department w.e.f. 18-4-1983, that Ex. W-2 is another letter dated 7-5-1984 issued by the Management of the Respondent-Company directing him to report to Sri G. R. G. Choudary, Assistant Stores Officer, after his services are terminated, he approached the Personnel Officer of the Respondent-Company at his house on 27-12-1985 and he asked him to come and meet him in the Respondent-Company on the next day morning that on the next day he went to the Respondent-Company to meet the Personnel Officer, but he was not allowed by the Security Officer to go inside the Company, that he reported that matter about the Security Officer obstructing him at the main gate on that evening at his house and he instructed him to come to the factory on the next day stating that he will phone to the Security Officer to allow him to go into the Company, that accordingly he went to the Respondent-Company on the next day, but he was not allowed to go into the Company by the Security Officer and informed that he did not receive any phone call from the Personnel Officer, that three workmen namely, V. Raja Rao, Murali Krishna and Sri B. Bikshapathi who were juniors to him were regularised by the Respondent-Company, that he completed service of one year, and therefore, he is entitled to be regularised, that he was not paid the salary for Sundays during the period he worked in the Respondent-Company that he worked in the Respondent-Company continuously from 18-4-1983 to 27-12-1985 and for more than 240 days continuously, that there were no breaks in his service during the period from 18-4-1983 to 27-12-1985 and that he prays the Court to pass an Award directing the Respondent to reinstate him with full back wages and continuity of service and all other attendant benefits. There was no cross-examination of W.W. 1 by the Respondent and so the evidence of W. W. 1 stands unrebutted.

8. There is no dispute that the Petitioner worked in the Respondent-Company during the period from 18-4-1983 to 27-12-1985. What was stated by the Respondent in the counter was that the Petitioner was worked only as casual labour and he never put in continuous service under the Respondent, that the Petitioner was working in leave vacancy and his employment was never regular, that his services were utilised as and when work was available and as and when he was willing to work, that the Petitioner worked for 167 days in 1983 during the period from 18-4-1983 to 30-11-1983 and for 149 days from 4-5-1984 to 27-12-1984 and 199 days from 1-1-1985 to 10-12-1985. The Respondent did not file any documentary evidence to show that the petitioner worked in the leave vacancy for the specified periods during the relevant period from 18-4-1983 to 18-12-1985 which was the period during which the petitioner admittedly worked in the Respondent Company. As seen from Ex. 1 the appointment order dated 18-4-1983 it does not disclose that the Petitioner was appointed for any specific period during the leave vacancy. On the other hand it reads that "Sri Hanumant Rao a casual labourer is hereby directed to Accounts Officer-III to work on casual basis in Accounts (Costing) Section w.e.f. 18-4-1983". As seen from Ex. W-1 it is further clear that by the date of Ex. W-1 the Petitioner was already working as Casual labourer and he was directed in Ex. W-1, to the Accounts Officer-III to work on casual basis in Accounts (Costing) Section w.e.f. 18-4-1983 and that Ex. W-1 does not disclose that the Petitioner was appointed for the first time in the Respondent-Company and it categorically discloses that his services were directed to be utilised in the Accounts (Costing) Section while he was working as casual labourers, dis-owing him to work as labourer. So the contention raised by the Respondent in the counter that the Petitioner was working in leave vacancy cannot be countenanced and on the other hand the contents of Ex. W-1 and Ex. W-2 which are the documents emanated from the Respondent, establish that the appointment of the petitioner was not in leave vacancy. Even according to the case of the Respondent, the Petitioner worked in the Respondent-Company during the period from April, 1983 to December, 1985, According to the case of the Respondent in the counter, the Petitioner worked for 149 days during the period from 4-5-1984 to 29-12-1984 and for 199 days during the period from 1-1-1985 to 10-12-1985. So it is clear from the above extracted statement of the Respondent in the counter, a break was given for two days i.e. on 30-12-1984 and 31-12-84 which should be treated as artificial break. So it is clear from the averments of the counter of the Respondent itself that the Petitioner worked for 348 days during the period from 4-5-1984 to 10-12-1985, which leads to the inference that the petitioner worked for more than 240 days within the period of 12 months immediately prior to the date of his termination from service. Such termination without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I. D. Act, amounts to retrenchment as defined in Section 2(oo) of the I. D. Act. Admittedly, the petitioner was not paid any retrenchment compensation and one month's pay in lieu of not issuing one month's notice as contemplated under Sec. 25-F of the I D. Act. Though the documentary evidence with regard to the actual days the petitioner worked in the Respondent is available with the Respondent-Company, the Respondent-Company did not choose to adduce any oral or documentary evidence in this regard and therefore the version of the petitioner that he worked for more than 240 days continuously in a year is acceptable. So in view of my above discussion. I am of opinion that it is established that the petitioner worked for more than 240 days continuously within a period of 12 months immediately prior to the date of his termination from service which amounts to retrenchment under Section 2(oo) of the I. D. Act and the retrenchment of the petitioner without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act, entitles the petitioner for reinstatement into service with full back wages and continuity of service. So I hold that the petitioner is entitled for reinstatement into service with back wages and continuity of service. Hence I answer this point accordingly.

10. In the result, an Award is passed directing the Respondent Company to reinstate the Petitioner into service forthwith with back wages and continuity of service. The Respondent is further directed to pay the back wages to the petitioner within one month from the date of publication of this award failing which the petitioner is entitled to release the same with interest at 12 per cent per annum from the date of publication of this Award. There will be no order as to costs under the facts and circumstances of the case.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 31st day of July, 1992.

G. KRISHNA RAO, Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

Witness examined on behalf of Petitioner	Witness examined on behalf of the Respondent
W.W.1 D. Hanumanth Rao	Nil.

Documents marked for the Petitioner-Workmen

Ex. W1 18-3-83.—Letter issued by the Asst. Personnel Officer, N.F.C. Administration I to Sri D. Hanumanth Rao.

Ex. W2 7-5-84.—Letter issued by the Asst. Personnel Officer, N.F.C. Administration I to Sri Hanumanth Rao.

Documents marked for the Respondent-Management

NIL

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992

का०आ० 2538 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रेलवे मेल सर्विस, करनूल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/177/91-आई०आर(डी०यू०)]

बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th September, 1992

S.O. 2538.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Railway Mail Service, Kurnool and their workmen, which was received by the Central Government on 8-9-92.

[No. L-40012/177/91-IR(DU)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

Present :

Sri G. Krishna Rao, B.A., B.L., Industrial Tribunal.

First August Ninenteen Hundred Ninety Two
Industria Disputes No. 40 of 1992

BETWEEN

Sri K. V. Sugunakar, Ex-Sweeper-cum-Waterman, H. No. 51-1017, LIC Colony, Kurnool-518 003

... Petitioner/Workmen.

AND

1. The Superintendent, Railway Mail Service, 'AG' Division, Kurnool-518 003.

3. The Sub-Record Officer, Railway Mail Service, 'AG' Division, Kurnool-518 003.

...Respondent/Management

This case is coming for final hearing before me in the presence of Sri K. V. Sugunakar, the concerned workman in person and none for the Respondent and upon persuing the material papers on record and having stood over for consideration till this day, the Court passed the following :

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012|177|91-IR (DU) dt. 25-6-1992 for adiudication of the dispute between the Management of Sub-Record Officer, RMS., AG Division, Kurnool and their workman setting forth the point for adjudication in the Scheduled appended thereto as follows :

"Whether the action of the management of Sub-Record Officer, Railway Mail Service, Kurnool in terminating the services of Sh. K. V. Sugunakar w.e.f. 29-5-90 is justified ? If not, what relief he is entitled to?"

The said refence was registered as I.D. No. 40 of 1992 on the file of this Tribunal. After receiving the notice from this Tribunal the Petitioner workman appeared in person and filed a Memo on 1-8-1992 stating that he has been appointed by the Respondents-Management as EDMM in the office of SRO RMS 'AG' Division Kurnool w.e.f. 28-4-1992 and that therefore he request that further proceedings before this Tribunal may kindly be dropped. The respondents 1 and 2 remained ex-parte.

2. This reference was made to this Tribunal at the instance of the Petitioner-concerned workman and the said workman appeared before this Tribunal on 1-8-1992 to which date the matter stood posted for appearance of the parties and he filed a Memo stating that he was appointed by the Respondents and so it is clear that his grievance for which this reference was made, in fulfilled and so he requested the Tribunal to drop further proceedings. The purpose for which the adjudication is to be made by this Tribunal is already fulfilled and the Petitioner-workman was reinstated. Therefore, there is no need to pass any award on merits in this case and further proceedings are to be closed in view of the Memo filed by the Petitioner-concerned workman.

3. In the result, an Award is passed dropping further proceedings in this case as requested by the petitioner-concerned workman. There will be no order as to costs.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 1st day of August, 1992.

G. KRISHNA RAO, Industrial Tribunal

Appendix of Evidence.

NIL

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1992

का०आ० 2539 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/170/80-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th Septembe, 1992

S.O. 2539.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9-9-92.

[No. L-12012/170/89-DII(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 31 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

On behalf of Employer—Mr. S. M. Bose, Chief Officer (Law).

On behalf of Union—Mr. Monoranjan Bhuia.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

On the action of the Regional Manager, Central Bank of India, North Regional Office, for short the Bank, in not refixing the salary of Anadi Mukherjee, for short the workman and effecting recovery of Daftry Allowance, which was already taken into account, while fixing his salary consequent on his promotion from sub-staff to clerical cadre on June 1, 1981 and if such non-action/in action was justified, the dispute was referred to this Tribunal, by Order No. L-12012/170/89-D.II(A) dated September 19, 1989, under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act), for adjudication. The case of the workman was represented by the Central Bank of India Employees' Union, for short the Union.

2. The workman entered the services of the Bank on January 18, 1973 in the subordinate cadre and was posted at the Entally Branch. In 1974, a permanent post in the subordinate cadre was created in that Branch and he was directed to fill up that vacancy, which attracted a special allowance of Rs. 40 per month. In fact, it has been stated that such direction was given in the usual course of business of the Bank.

3. It has also been stated that the workman received such Special pay from April 1974 to June 1981, when he was promoted from the Subordinate Cadre to Clerical Cadre and in fact, in terms of Industrywise Bipartite Settlement, he was enjoying such allowance, even when he was on leave and his employment for seven years was without any break. It has been stated that receipt of Special Allowanre was taken into consideration, while the workman's salary was fixed on promotion to the Clerical cadre and he enjoyed such benefit uninterruptedly till 1987, when he was at Baranagore Branch. But, suddenly, the Bank or its authorities, on July 28, 1987, directed the said Branch to lower down the salary, on deduction of the Special Allowance and subsequently, fitment was made in his case, without considering the Special Allowance/salary, received. It has been alleged that even on protest, the Bank did not amend their action and as such, the present dispute was raised.

4. Such action, was claimed to be contrary to all rules, norms and against violation of principles of natural justice, since the allowance so long enjoyed uninterruptedly, according to the Union, could not be taken away in the manner as was done, because, the same was a condition of service of the workman. In support of their contentions, the Union relied on and referred to Clause 5.3 of the Industry-wise Bipatite (First) Settlement dated October 19, 1966, indicating that there are certain posts, for members of the subordinate staff, which includes Daftries, which again, according to the Union, attracted Special Allowance, in supersession of paragraphs 5.3 and 6 of the Desai Award. It was further pointed out that Clause 5.10 of that settlement postulates that such special allowance would continue to be paid to and received by the permanent incumbent while on leave. It was also indicated that in terms of the 4th Bipartite Settlement of September 17, 1984, on such special allowance, it has been agreed in Clause V that "while the said allowance of the clerical staff will not attract Dearness Allowance, but the same may be payable to the members of the subordinate staff, in terms of Dearness Allowance and that Special Allowance, will also be considered in the matter of Provident Fund, in terms of the Bipartite Settlement. It has further been stated that special allowance attracting posts, are filled up according to promotion policy Agreement and in terms of Clause 12.1 of Chapter XII of the Agreement dated December 20, 1975, on the item selection of subordinate staff to posts attracting such allowance, the 'Stationwise seniority' of members of the subordinate staff shall be the criterion for such posts, attracting special allowance in subordinate cadre, subject to the possessing of requisite skill, knowledge and ability of the employers.

5. It has been pointed out that in the promotion policy agreement, on fixation of emolument in clerical scale of pay on promotion from subordinate to clerical cadre, the Agreement dated December 20, 1975 provides in Clause 9.7 in Chapter IX that for the purpose of fixation of salary on promotion, total emoluments in subordinate cadre, comprising Basic Pay, Special Allowance, if any, D.A., H.R.A., thereon, if any, C.C.A., if any, but excluding all other allowances e.g. cycle allowance etc., by the concerned employee, will be taken as Special Allowance and for the purpose, shall be included, only if drawn by him in a permanent assignment.

6. In the admitted circumstances of drawing Special Allowance by the workman for long 13 years, the Union claimed that the denial to pay the same, to the workman, was unauthorised, not justified, illegal and improper, apart from being, against principles of natural justice, so the Reference should be answered in the affirmative.

7. The Bank has stated that the workman was promoted after appointment on 1-6-81 and at the time of fixation of his salary on such promotion in clerical grade, he was given Special pay @ Rs. 40 per month, but the taking into consideration of such Special Allowance, the fixation of his grade, was done erroneously. It was their case that according to Clause 9.17 of Chapter IX of the Memorandum of Agreement dated December 20, 1975, Special Allowance was considered for the purpose of fixation of salary on promotion to subordinate clerical cadre, to be inserted, only if it was drawn in a permanent assignment, made by order in writing by the Bank and in this case, there was no such order and Special Allowance was drawn by the workman, purely on temporary basis and nature. That being the position, it was claimed that such allowance should not be taken into account for the purpose of fixation of salray in clerical cadre on promotion in this case.

8. It has been stated that such fact of excess payment or drawing of salary made to or received by the workman was sought to be rectified by the Bank by their letter dated August 28, 1987 (Ext. M-1), as addressed to the Bank Manager Barranagar, whreby he was asked to recalculate the salary of the workman from June 1, 1981 and also to arrange for recovery of excess payment made on the basis of such refixation of salary. It was also claimed that in terms of Clause 13.1 of Chapter XIII of the Agreement as mentioned above, Special Allowance in subordinate cadre cannot be claimed as matter of course or right and the Bank had and has the authority to rectify the mistake as committed, in respect of fixing of salary. It was further indicated that selection of subordinate staff to the cadre attaching special allowance, is controlled by Clause 12.1 of Chapter XII of the above Agreement, which indicates that Stationwise seniority of the members of the subordinate staff shall, be the criterion for selection to posts attaching Special Allowance in subordinate cadre, provided the employees possessed the requisite skill, knowledge and ability and Clause 9.17 of Chapter IX of the above Agreement postulate the fixation of emoluments of the clerical scale of pay on promotion to subordinate to clerical cadre and Rules governing the officiating allowance are covered by Clause 18.2 of Chapter XVIII of that Agreement and Clause 13.1 of that Chapter, indicates that officiating in posts carrying special allowance in the subordinate cadre, cannot be claimed as a matter of right and it shall be allowed at the sole discretion of the Bank, when Clause 13.2 of that Chapter lays down the Rules governing eligibility, due, in respect of officiating in any higher cadre or in post, attracting Special Allowance as indicated in that Agreement and such Rules are also agreed to be considered in case of officiating, in posts carrying Special Allowance under subordinate cadre.

9. The dispute as raised, was claimed to be not an industrial dispute and to be utterly misconceived. It has also been stated that without application of mind duly and properly, the instant reference was made by the Appropriate authorities.

10. On the basis of the submissions as indicated earlier, the allegations as make in the written statement have been denied and it was claimed that the workman was not entitled to any relief and the Bank was authorised to rectify its mistake as committed in the manner so indicated, even though the workman concerned, drew such allowance for such a long period of time as mentioned.

11. In their written statement as indicated earlier and also in their rejoinder, the Union claimed that since the workman concerned worked in the permanent post of Daftry, for a prolonged period of seven years and without any break, it should be construed that he worked on a permanent assignment and the plea of the Bank that there was no formal sanction for the Special Allowance, as enjoyed by the workman was not tenable, more particularly when, he has enjoyed such allowance, even when he was on leave. It was stated that the plea of the Bank regarding grant of Special Allowance on Stationwise seniority of members of the subordinate staff, cannot be the criterion of selection in terms Clause 12.1 of the Agreement as mentioned earlier. It was also stated that since, within the long span of seven years of the working of the workman as Daftry, the Bank has not sent any one for such work that would automatically establish that the workman enjoyed such Special Allowance senioritywise and such enjoyment, has become a right as well as privilege to him, on the basis of all cannons of law, including principles of natural justice. It was stated that such denial of special allowance, after a long lapse of so many years, has caused great financial loss to the workman and the recovery as sought to be done, has lowered his salary, in contravention of the principal as indicated earlier and the same was contrary to Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The claim that the workman was paid temporary Daftry allowance in the concerned Branch, was denied and it has been stated that he worked as Daftry, attracting Special Allowance @ Rs. 40 per month, without any dispute and the purported claim that such allowance was paid to him through mistake, cannot be entertained at this late stage.

12. Mr. Bose appearing for the Bank could not deny the fact of employment of the workman and his drawings of Special allowance, at the rate as mentioned earlier, for a long time, but he claimed that such working as Daftry by the workman and enjoyment of the Daftry allowance by him, was not permanent, but was a temporary one. It has been indicated that the workman was employed as Peon in 1973 and he enjoyed such allowance as mentioned, from 1974 to 1981, when he was promoted as Clerk. But, his main defence was that payment or fixation in the instant case after promotion to work in clerical cadre, on taking into consideration the Special allowance, was made through mistake and that is why, the action as impeached and by which the overdrawal of the workmen, was sought to be recovered, was due and proper. He referred to Clause 9.17 of Ext. M-3 which deals amongst others with fixation of emoluments in clerical scale of pay on promotoin from subordinate to clerical cadre, which is to the following effect:—

> "9.17 ..For the purpose of fixation of salary on promotion, total emoluments in sub-ordinate cadre comprising Basic pay, special Allowance, if any, Dearness Allowance thereon, House Rent Allowance, if any, City Compensatory Allowance, if any, but excluding all other allowances such as Cycle Allowance etc. by the concerned employee will be taken as the basis. 'Special Allowance' for this purpose shall be included only if drawn by him in a permanent assignment by a written order of the management. He shall be fixed into the clerical scale of pay at a stage where, together with the other allowance, e.g. Dearness Allowance, City Compensatory Allowance, if any, and House Rent Allowance, if any, he would get a minimum increase of Rs. 40 in his total emoluments over what he was getting as a member of the subordinate staff."

and on that he claimed that so the written order by the Bank was necessary, but he in this case, admittedly there was no such order or any order of assignment. He also referred to Clause 12.1 in Chapter XII of Ext. M-3, which is to the following effect :—

> "12.1—Stationwise seniority of members of the subordinate staff shall be the criterion for selection to posts attracting Special Allowance in Subordinate Cadre, provided the members possess the requisite skill knowledge and ability."

and stated that on such basis, stationwise seniority of a member of subordinate staff was the criterion for selection in a case of this nature. He then, referred to Clauses 13.1, 13.2, and 13.3 of Chapter XIII of Ext. M-3 which are quoted hereunder:—

> "13.1—Officiating in posts carrying special allowance in the subordinate cadre shall not be claimed as a matter of right, and it shall be allowed at the sole discretion of the Management.
>
> 13.2—The rules governing eligibility conditions in respect of officiating by clerks in any higher cadre or in a post attracting Special Allowance as set out in this Agreement shall also be applicable in case of officiating in posts carrying Special Allowance in Subordinate cadre.
>
> 13.3—All members of the Subordinate staff (excluding Watch and Ward Staff, Sweepers, Watermen, Tiffin Boys, Farrash, Hamals and posts for which Special Technical knowledge is required e.g. Drivers, Electricians, Liftmen, Air-conditioning Plant Helpers etc.) shall be eligible for officiating in a permanent post attracting Special Allowance on the basis of their officewise seniority."

in support of justifying that the fixation as made in respect of the workman, after taking into cosnideration the Special Allowance was done wrongly and as such he drew the same wrongly and by the order under challenge, such wrong was sought to be rectified, which was possible and permissible.

13. As indicated already that excepting the claim that the workman was enjoying the Special allowance temporarily and he was entiled to such benefits on stationwise seniority and the defect, on being discovered, was sought to be clarified or rectified duly. There was no dispute on fact and more particularly, on the fact the workman was allowed to draw enhanced salary, after taking into considertion such Special allowance as indicated, for a long time, even after promotion, or there was any material dispute. It was claimed by Mr. Bhuia that Daftry allowance, in terms of the Bipartite Settlement as mentioned earlier, was a Special allowance and such Special allowance, the workman enjoyed from 1974 to 1981 uninterruptedly and thereafter, and such uninterrupted enjoyment of Special allowance was duly taken into consideration, in effecting fitment of the salary of the workman and even thereafter, he enjoyed such enhanced salary of fitment upto 1987, when no objection was taken by the Bank. It has been stated that only on July 28, 1987, it was mentioned that a mistake was committed and for that, the amount so overpaid, was sought to be recovered. This recovery according to Mr. Bhuia was a penal one, as no opportunity was afforded to the workman, before inflicting such action, and the amount as is sought to be recovered, was inappropriate, in terms of Clause 9.7 of the Bipartite Agreement. It was also pointed out by him that Clause 5.3 of the Bipartite Agreement No. 1 speaks of Special allowance and Clause 5.6, will establish that Daftry Allowance was payable to the workman and such allowance was a permanent assistance. According to him, thus, the question would be, whether the workmen enjoyed the Daftry Allowance permanently and his submission was, that the answer should be in the affirmative as the workman received such Special allowance, not on occasion only, but enjoyed the same for a long time and even when he was on leave.

14. Mr. Bhuia also argued that the workmen should also be paid such allowance as a matter of course or right, and his claim was justified, as he performed the duties of Daftry, regularly and permanently, which attracted the Special allowance. He, for the purpose of establishing his case that the acton as taken, was not fair and proper and recovery as sought to be made, was also not due, relied on Exhibit W-2 and W-3, which exhibits in my view, have no application in this case, as they relate to Bombay or part thereof only. It was contended by Mr. Bhuia that in any event, the recovery as sought to be made in this case, was bad, for reasons as indicated earlier and more particularly when, the workman duly received his Special allowance, which was attached to

the post of Daftry and while he was working as such. The view that the workman had performed the work of Daftry for which he was entitled for such Special allowance paid to a Daftry, cannot be doubted or disputed. So, I feel that the amount of Special allowance at the rate of 40 per month, which the workman has drawn during his tenure as Daftry during 1974 to 1981, cannot be recovered on the basis of payments, said to be made through mistake and the workman cannot be made liable or esponsible for such payment, which he has duly received, for performing the Special duty as Daftry and as such, any payment recceived by him, for that period, cannot be recovered. Now the further question would be, whether the Special allowance, which was paid to the workman after 1981, on calculating the same at the time of fitment, can or should be recovered.

15. Daftry Allowance was admittedly admissible to the workman as a Special allowance, so long he performed the duties/work of Daftry and such allowance was not certainly a permanent one and was liable to be withdrawn when the workman lost that character and as such, allowance was not a peramnent one, so the same cannot be said to be taker into consideration, while the workman concerned gets a promotion to a higher or separate cadre. In fact, it will appear from Ext. M-1 that such allowance was paid to the workman on temporary basis and from Ext. W-1, it will also appear that after the said workman, was transferred, one Rajmoni Mishra, has received such allowance from August 1981. Since, here is a case, where the workman was not being paid such Special allowance on permanent assignment and really there is paucity of evidence on that account or where there is no such legal evidence. I feel that the benefits of Clause 9.7 of Chapter IX of the Agreement dated December 20, 1975, canont be brought into play or operation.

16. The action as impeached or as was taken, canont be deemed to be a change in the conditions of service and terms of employment of the workman and as such, the determinations in the case of Mohinder Singh Gill & An. Vs. The Chief Election Commissioner, New Delhi & Ors, A.I.R. 1978 S.C. 851 and those in the case of State of Orissa vs. Binapani, A.I.R. 1967 S.C. 1269, as relied on and referred to by Mr. Bhuia will not apply in this case.

17. Thus, the Reference is answered in the affirmative and only to the extent as indicated earlier, in favour of the workman.

This is my Award.

Dated Calcutta,

The 24th August, 1992.

MANASH NATH ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1992

का०आ० 2540 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुपरिनटैंडेन्ट, पोस्ट आफिस, रीवा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एस-40012/69/88-डी 2(बी) (पीटी)]

के०घो०यी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th September, 1992

S.O. 2540.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Superintendent, Post Office, Rewa and their workmen, which was received by the Central Government on 10-2-92.

[No. L-40012/69/88-DII(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(161)/1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Superintendent, Post Office, Rewa (M.P.) and their workman, Shri Ramsiya Charmakar C/o Shri B. S. Bisen, Bardadih Road, Mukhtiyar Gang, Satna (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—None.

For Management—None.

INDUSTRY : Post & Telegarph DISTRICT : Rewa (M.P.)

AWARD

Dated : August, 26, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-40012/69/88-D-2(B) Dated 13 August, 1989, for adjudication of the following dispute:—

SCHEDULE

"क्या अधीक्षक, डाकघर रीवां (म.प्र.) के प्रबन्धकों द्वारा श्री रामसिया चर्मकार, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल (लेखा कार्यालय, रामनगर) लुनौराकुठार (अमर पाटन) की सेवाएं उनके आदेश दि० 8/1/85 एवं 19/9/86 द्वारा नौकरी से हटाये जाने की कार्यवाही न्यायोचित है', यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोश का हकदार है"।

2. This case was referred for adjudication as early as in August, 1989. Since then despite several notices no statement of claim has been filed by the workman. Nor has put appearance on 21-9-89, 23-10-89, 30-11-89, 1-2-90, 4-4-90, 5-6-91, 9-9-91, 7-1-92, 4-3-92 and 13-7-92. It appears that the workman has; no interest in the case. I therefore pass a No Dispute Award in the case. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992